राष्ट्रीय संस्करण

# दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 60

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, सोमवार, 9 अगस्त, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

मराठाओं से नीरज का नाता, भाले से जीती दुनिया

>> 12

टोक्यो ओलिंपिक का समापन हो रहा है। इस अवसर पर मैं भारतीय दल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने अपने कौशल, टीमवर्क और समर्पण का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर खिलाड़ी एक चैंपियन है। भारत ने जो पदक जीते हैं, उससे देश गौरवान्वित और प्रफुल्लित हुआ है। जापान की सरकार और लोगों को विशेष धन्यवाद। खासतौर से ओलिंपिक के शानदार और सफल आयोजन के लिए। ऐसे समय में और इतनी सफलतापूर्वक इसका आयोजन लचीलेपन का मजबूत संदेश देता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि खेल कैसे लोगों को जोड़ता है। — नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

<< समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पूनिया ● प्रेट्र

रविवार को समापन समारोह के दौरान आतिशबाजी से जगमगाता टोक्यो नेशनल स्टेडियम ● प्रेट्र

TOKYO 2020

- ओलिंपिक खेलों का रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ समापन
- समारोह के दौरान बजरंग बने भारतीय दल के ध्वजवाहक

**39** स्वर्ण के साथ अमेरिका पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। कुल पदक जीतने के मामले में भी वह 113 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। वह अकेला देश रहा जिसने पदकों का शतक पूरा किया

**10** देशों ने अपने स्वर्ण पदकों की संख्या को दोहरे अंकों में पहुंचाया, जबकि पांच देश ऐसे रहे, जिन्होंने कुल 50 से ज्यादा पदक जीते

**7** पदकों के साथ भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत 48वें नंबर पर रहा। 27 स्वर्ण के साथ मेजबान जापान तीसरे स्थान पर रहा

## अलविदा टोक्यो, अब पेरिस में मिलेंगे

**जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली:** कोरोना महामारी के बीच 23 जुलाई से शुरू हुए टोक्यो ओलिंपिक का रविवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। समारोह के दौरान आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। इस ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पूनिया ने समारोह के दौरान ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल की अगुआई की। अब दुनियाभर के खिलाड़ी तीन साल बाद होने वाले अगले ओलिंपिक में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेंगे, जबकि टोक्यो पैरालिंपिक खेल 24 अगस्त से पांच सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे।

समापन समारोह के लिए ओलिंपिक स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया। समारोह की शुरुआत आतिशबाजी के साथ हुई। समारोह में भारत के 10 एथलीटों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समारोह एक वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें 17 दिन की स्पर्धाओं का सार था। शुरुआती वीडियो में फोकस रिकार्ड और स्कोर पर नहीं, बल्कि उन सभी खिलाड़ियों के साहसिक प्रयासों पर था, जिन्होंने रोज कोविड-19 जांच करवाते हुए कड़े बायो-बबल में हिस्सा लिया। समारोह का मुख्य संदेश था कि खेल एक उज्ज्वल भविष्य के दरवाजे खोलेंगे। अंतिम अध्याय की शुरुआत स्टेडियम में आतिशबाजी से हुई, जिसमें आयोजकों ने उन अनगिनत व्यक्तियों के लिए आभार व्यक्त किया, जिन्होंने ओलिंपिक खेलों को समापन समारोह तक पहुंचाने में मदद की। इसके बाद जापान के क्राउन प्रिंस अकिशिनो और अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति के अध्यक्ष थामस बाक आधिकारिक स्टैंड में उपस्थित हुए।

संबंधित खबरें >> पेज 12

खेलों से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का कोई संबंध नहीं है। टोक्यो में शुक्रवार को 4,066 मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब ओलिंपिक खेल समाप्त हो गए हैं तो आयोजकों को फैसला करना होगा कि पैरालिंपिक के दौरान दर्शकों को अनुमति दी जाए या नहीं। इसका फैसला सही समय पर किया जाएगा। — **सेको हाशिमोटो,** अध्यक्ष, टोक्यो ओलिंपिक

---

**जागरण विशेष**

**महामारी से आजादी**

कोरोना संकट के इस अभूतपूर्व काल में हमारे कई नायक लोगों के जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर सुनिश्चित कर रहे हैं। इस विशेष सीरीज में दैनिक जागरण आपको ऐसे ही नायकों से परिचित कराने जा रहा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद महामारी से आजादी दिलाने के पुनीत कार्य में जुटे हैं। (पेज-6)

### चार लाख तक पहुंच गया ब्रिटेन का हवाई किराया

**नई दिल्ली :** कोरोना काल में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रूट पर फ्लाइट टिकट के दाम आश्चर्यजनक रूप से बढ़े हैं। 26 अगस्त के लिए दिल्ली से लंदन तक ब्रिटिश एयरवेज का एक तरफ का किराया 3.95 लाख रुपये पहुंच गया है। ट्विटर पर आइएएस अधिकारी संजीव गुप्ता की शिकायत के बाद विमानन नियामक डायरेक्टरेट जनरल आफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने कंपनियों से किराए की जानकारी मांगी है। (पेज-10)

### तीन दिन में तीसरी प्रांतीय राजधानी पर तालिबान का कब्जा

**काबुल :** अफगानिस्तान में तालिबान ने लगातार तीसरे दिन तीसरी प्रांतीय राजधानी कुंदुज पर भी कब्जा कर लिया। इससे पूर्व आतंकी जौजान प्रांत की राजधानी शबरगान और निमरुज की राजधानी जरंज पर कब्जा कर चुके हैं। वहीं, अफगान सेना तालिबान का कब्जा हटाने को ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। सेना ने 572 आतंकियों को मारने का दावा किया है। (पेज-11)

## आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर में 56 जगहों पर एनआइए के छापे

**बड़ी कार्रवाई** ▶ जमात-ए-इस्लामी के नेताओं के घरों, मदरसों और ट्रस्ट के कार्यालयों को खंगाला

कश्मीर के 10, जम्मू के चार जिलों में छापेमारी, वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज व जिहादी साहित्य बरामद

**राज्य ब्यूरो, श्रीनगर**

आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख जारी रखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने रविवार को आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के मामले में जम्मू-कश्मीर के 14 जिलों में 56 जगहों पर छापेमारी की। सभी छापे प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर के नेताओं के घरों, मदरसों और फलाह-ए-आम (ट्रस्ट) के कार्यालयों पर मारे गए। इस दौरान वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों के अलावा जिहादी साहित्य भी बरामद किया गया। एनआइए के महानिरीक्षक (आइजी) रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई।

यह छापेमारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष निर्देश पर हुई है। कश्मीर संभाग के सभी 10 जिलों और जम्मू संभाग के चार जिलों रामबन, डोडा, किश्तवाड़ व राजौरी में एनआइए टीम ने जमात नेताओं के घरों व कार्यालयों को खंगाला। इन छापों में जमात के मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष से लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष और अन्य प्रमुख नेताओं के घरों में तलाशी ली गई है। ज्ञात हो, इस समय भी जमात ए इस्लामी से संबंध रखने वाले करीब 50 लोग जन सुरक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न जेलों में बंद हैं।

**पुलिस और सीआरपीएफ के 65 दस्तों की मदद ली :** सूत्रों ने बताया कि पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के लगभग 65 संयुक्त दस्ते जिलावार तैयार किए गए थे ताकि छापेमारी के दौरान कोई दिक्कत न आए। यह अभियान सुबह करीब पांच बजे शुरू होकर दोपहर तक चला।

रविवार को श्रीनगर स्थित फलाह-ए-आम ट्रस्ट पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी की। परिसर के बाहर तैनात सीआरपीएफ के जवान। एएनआइ

**धन के गलत इस्तेमाल की शिकायत**

एनआइए प्रवक्ता ने बताया कि जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ पांच फरवरी को टेरर फंडिंग के सिलसिले में केस दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई उन सूचनाओं व तथ्यों पर की गई थी जो पुष्टि करते हैं कि जमात का काडर न सिर्फ जम्मू-कश्मीर व देश के विभिन्न हिस्सों में बल्कि विदेश से भी दान (जकात, बैतुल माल) एकत्र कर उसका इस्तेमाल हिजबुल व लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के लिए कर रही है। वह कश्मीरी युवाओं को गुमराह कर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए तैयार कर रही है। प्रवक्ता ने कहा, सभी आवश्यक सुबूत जमा करने के बाद ही छापे डाले गए हैं।

**2019 में संगठन पर लगा था प्रतिबंध**

जमात-ए-इस्लामी पर केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में पांच साल के लिए पाबंदी लगा दी थी। पीएम की अध्यक्षता में सुरक्षा पर हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले जम्मू-कश्मीर में इस संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया था। हिजबुल मुजाहिदीन को कभी जमात का फौजी बाजू कहा जाता था। जमात-ए-इस्लामी पर 30 वर्ष में दूसरी बार रोक लगाई गई है। 1990-1995 तक भी इसकी गतिविधियों पर रोक थी।

**कई अलगाववादी जमात से निकले हैं :** सैयद अली शाह गिलानी, सलाहुद्दीन, मुहम्मद अशरफ सहराई, अब्दुल गनी बट, मुख्तार वाजा, फिरदौस अहमद, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, शौकत बख्शी, शकील बख्शी समेत, मसरत आलम, अकबर एजाज, सलीम गिलानी, नईम खान समेत वादी के सभी प्रमुख अलगाववादी नेता और आतंकी कमांडर मूलतः जमात ए इस्लामी से ही निकले हैं।

**इनके यहां हुई छापेमारी**

- **श्रीनगर :** गाजी मोइन उल इस्लाम, गुलाम मोहम्मद बट, बशीर अहमद लोन, फहीम रमजान, मोहम्मद अब्दुल्ला वानी
- **अनंतनाग :** मुश्ताक अहमद वानी, नजीर अहमद राना, फारूक अहमद खान, आफाक अहमद मीर, अहमदुल्ल पर्रे
- **बड़गाम :** डा. मु. सुल्तान बट, गुलाम मुहम्मद वानी, गुलजार अहमद शाह, रियाज अहमद सोफी
- **बांडीपोर :** मु. सिकंदर मलिक
- **गांदरबल :** गुल मुहम्मद वानी, जहूर अहमद रेशी, मेहराजुद्दीन रेशी, अब्दुल हमीद बट
- **शोपियां :** मु. यूसुफ शेख, रियाज अहमद गनई
- **कुलगाम :** गुलाम हसन शेख, मु. यूसुफ राथर, पीर ग्यासुदीन शाह, अब्दुल रहमान शाला

## पहुंच वाले भी पुलिस हिरासत में थर्ड डिग्री से नहीं बच पाते

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

- प्रधान न्यायाधीश ने कहा, देशभर में पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए मुहिम चलानी चाहिए
- पुलिस अत्याचार रोकने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता की जानकारी का प्रसार होना जरूरी

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) एनवी रमना ने रविवार को कहा कि हिरासत में प्रताड़ना और पुलिस अत्याचार जैसी समस्या अब भी बनी हुई है। अगर ताजा रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि पहुंच वाले लोग भी थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बच पाते। पुलिस अत्याचार रोकने के लिए कानूनी मदद पाने के संवैधानिक अधिकार व मुफ्त कानूनी मदद उपलब्ध होने की जानकारी का प्रसार जरूरी है। नेशनल लीगल सर्विस अथारिटी (नालसा) को पूरे देश में पुलिस अफसरों को संवेदनशील बनाने का भी अभियान चलाना चाहिए। सीजेआइ ने विज्ञान भवन में आयोजित नालसा के विजन एंड मिशन स्टेटमेंट और लीगल सर्विस एप को लांच करते हुए यह बात कही।

सीजेआइ ने मानवाधिकारों और व्यक्ति की गरिमा के बारे में चिंता जताते हुए कहा, मानवाधिकारों और व्यक्ति की शारीरिक गरिमा को सबसे अधिक खतरा पुलिस थाने में होता है। संवैधानिक घोषणा व गारंटी होने के बावजूद थाने में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व न होने से गिरफ्तार व्यक्ति की बहुत हानि होती है। शुरुआती घंटों में लिए गए निर्णयों से बाद में अभियुक्त का अपने बचाव का सामर्थ्य तय होता है।

जस्टिस रमना ने कहा, पुलिस के अत्याचारों को रोकने के लिए कानूनी मदद के संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध होने की जानकारी का प्रसार जरूरी है। प्रत्येक थाने और जेल में डिस्प्ले बोर्ड और बाहर होर्डिंग लगना इस दिशा में एक कदम है। हालांकि नालसा को देशभर में पुलिस अफसरों को संवेदनशील बनाने के लिए सक्रिय अभियान भी चलाना चाहिए। उन्होंने कहा, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस यूयू ललित को वह विजन स्टेटमेंट जारी करने पर बधाई देते हैं। इसमें समाज की बदलती जरूरतों का ध्यान रखा गया है।

चीफ जस्टिस एनवी रमना। जागरण आर्काइव

**एप से मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता**

लीगल सर्विस एप के जरिये देश के किसी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति मुफ्त कानूनी मदद प्राप्त कर सकता है। आवेदन दे सकता है। मुकदमे से पहले मध्यस्थता की भी सुविधा प्राप्त कर सकता है। अपराध पीड़ित एप के जरिये मुआवजा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और अपनी अर्जी को ट्रैक भी कर सकते हैं।

न्याय तक बहुत पहुंच वाले और बहुत गरीब के बीच का अंतर खत्म करना होगा : रमना पेज>>3

## 9.75 करोड़ किसानों को आज मिलेगी सम्मान निधि की अगली किस्त

**नई दिल्ली, एएनआइ:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की नौवीं किस्त दोपहर 12:30 बजे जारी करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस किस्त में 9.75 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खाते में 19,500 करोड़ रुपये भेजी जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने के साथ ही लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे।

बता दें कि पीएम-किसान योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये दिए जाते हैं। ये 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे बैंक अकाउंट में हस्तांतरित किए जाते हैं। इस योजना के जरिये अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसान परिवारों को भेजी जा चुकी है।

इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई को इस योजना की आठवीं किस्त जारी की थी।

**ऐसे चेक करें पैसा आया या नहीं :** आपके खाते में पैसा आया या नहीं यह पता करने के लिए सबसे पहले https://pmkisan.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद दाहिने किनारे पर फार्मर्स कार्नर पर क्लिक करें। जो पेज खुलेगा उसमें बेनेफिशियरी स्टेटस के आप्शन पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, जहां अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालते ही पता चल जाएगा कि धनराशि मिलेगी या नहीं।

**किनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ :** नए नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी या आयकर देने वाले किसानों को इसका पात्र नहीं माना गया है। इसके अलावा डाक्टर, इंजीनियर, सीए और 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले कर्मचारी भी इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।

**किसानों को तोहफा**

- धनराशि भेजने के बाद पीएम मोदी सोमवार दोपहर को लाभार्थियों से करेंगे बात
- अब तक आठ किस्तों में भेजी जा चुकी है कुल 1.38 लाख करोड़ रुपये की धनराशि

नरेंद्र मोदी। जागरण आर्काइव

**उज्ज्वला 2.0 को कल लांच करेंगे पीएम**

पीएमओ की तरफ से जारी एक अन्य बयान में कहा गया है कि पीएम मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत उप्र के महोबा में लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपेंगे। मोदी लाभार्थियों के साथ बातचीत करने के साथ ही राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। 2016 में शुरू की गई इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। शुरू में इसके तहत पांच करोड़ परिवारों को इसमें शामिल किया गया था। बाद में दायरा बढ़ाकर आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया। इस लक्ष्य को तय समय से सात माह पूर्व अगस्त, 2019 में ही हासिल कर लिया गया। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में अतिरिक्त एक करोड़ कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी। ये कनेक्शन निम्न आय वाले परिवारों को दिया जाएगा, जो पहले की योजना में शामिल नहीं थे।

## माकपा के दफ्तरों में पहली बार फहराया जाएगा तिरंगा

**राज्य ब्यूरो, कोलकाता**

- पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक के आखिरी दिन इस प्रस्ताव को दी गई मंजूरी
- भाजपा की राष्ट्रवाद की नीति के मुकाबले के लिए तैयार की गई है यह रणनीति

इस स्वतंत्रता दिवस पर देशभर में माकपा के कार्यालयों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा की राष्ट्रवाद की नीति का मुकाबला करने के लिए यह रणनीति तैयार की गई है। इस बाबत पूर्व माकपा सांसद मुहम्मद सलीम से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कोलकाता समेत देशभर में माकपा के जितने भी कार्यालय हैं, वहां तिरंगा फहराया जाएगा। माकपा की तरफ से हर साल स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है।

रविवार को माकपा की केंद्रीय समिति की बैठक के आखिरी दिन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने यह प्रस्ताव रखा था।

माकपा की राज्य समिति ने तय किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पार्टी के राज्य कार्यालय मुजफ्फर अहमद भवन में किया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में वहां तिरंगा फहराया जाएगा। माकपा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। अचानक ऐसे फैसले पर कुछ वामपंथी नेताओं का कहना है कि जिस तरह से भाजपा ने राष्ट्रवाद या देशभक्ति का फायदा उठाकर देशवासियों को प्रभावित किया है, उससे मुकाबले के लिए रणनीति में परिवर्तन जरूरी है और इसी नीति के तहत यह निर्णय लिया गया है।

इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भाजपा नेता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ अलीमुद्दीन की छत पर तृणमूल का झंडा देखा जा सकता है। माकपा जल्द से जल्द तृणमूल से जुड़ने का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है।

**गैर-भाजपाई ताकतों के साथ शामिल होने पर उठे सवाल :** केंद्रीय समिति की वर्चुअल बैठक में माकपा की त्रिपुरा इकाई ने भाजपा को रोकने के लिए गैर-भाजपाई ताकतों के साथ हाथ मिलाने पर सवाल उठाया, दूसरी ओर अधिकांश राज्य समितियों ने केरल में पार्टी कांग्रेस आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केरल राज्य कमेटी आपस में चर्चा कर फैसला लेगी कि कोरोना के समय यह प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। पार्टी कांग्रेस अगले साल अप्रैल में केरल के कन्नूर में प्रस्तावित है। कई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, त्रिपुरा में भाजपा को रोकने के लिए राष्ट्रीय रणनीति लागू करने पर चर्चा होगी।

**महामारी से जंग**

## ज्यादा कारगर है कोरोना वैक्सीन की मिक्स डोज

कोविशील्ड की पहली डोज के बाद दूसरी डोज के रूप में कोवैक्सीन लेने वाले संक्रमण से रहे ज्यादा सुरक्षित, उप्र में सामने आए थे कोविशील्ड लगवाने वालों को दूसरी डोज में कोवैक्सीन लगाने के मामले, आइसीएमआर ने 98 लोगों पर अध्ययन के बाद निकाला यह निष्कर्ष

**नीलू रंजन, नई दिल्ली**

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्यकर्मियों की एक गलती ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में एक नई राह दिखाई है। यहां कुछ लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई थी और गलती से उन्हें दूसरी डोज के रूप में कोवैक्सीन दे दी गई। यह मामला सामने आया तो टीका लगवाने वालों में दहशत फैल गई। दो डोज में हुई इस गड़बड़ी के प्रभाव का पता लगाने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने अध्ययन किया तो नतीजे हैरान करने वाले मिले। यह पाया गया कि जिन लोगों को एक डोज कोविशील्ड की और दूसरी कोवैक्सीन की लगाई थी उन लोगों के शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता उन लोगों की तुलना में ज्यादा थी, जिन्हें दोनों डोज कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दी गई थी यानी मिक्स डोज ज्यादा कारगर पाई गई। इससे मिक्स डोज को लेकर दुनियाभर में किए जा रहे अध्ययनों को बल मिला है।

दरअसल मई में सिद्धार्थनगर में 20 लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की और दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई थी। उस समय इसे टीकाकर्मियों की बड़ी लापरवाही के रूप में देखा गया था और वैक्सीन लगाने वालों पर इसके दुष्परिणाम की आशंका भी जताई जाने लगी थी। वैसे नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टीकाकरण पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डा. वीके पाल ने उस समय साफ किया था कि इससे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, फिर भी उन्होंने लाभार्थियों पर नजर रखने की सलाह दी थी। अब आइसीएमआर के अध्ययन से साफ हो गया है कि भले ही वैक्सीन की दूसरी डोज गलती से लगी हो, लेकिन लाभार्थियों के लिए यह बेहतर साबित हुई।

आइसीएमआर के एक वरिष्ठ विज्ञानी ने कहा, अध्ययन के लिए दोनों अलग-अलग डोज लेने वाले सभी 20 लोगों से संपर्क किया गया। इनमें से दो ने इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया। इसके बाद 18 लोगों पर अल्फा, बीटा, डेल्टा जैसे कोरोना वायरस के नए वैरिएंट के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता की जांच की गई। साथ ही 40-40 लोगों के दो अन्य समूह भी बनाए गए, जिनमें एक समूह ने दोनों डोज कोविशील्ड ली थी और दूसरे समूह नो दोनों डोज कोवैक्सीन की ली थी। अल्फा, बीटा और डेल्टा वैरिएंट के खिलाफ उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी देखी गई। अध्ययन से पता चला कि जिन लोगों को गलती से अलग-अलग डोज लगा दी गई थीं, उनमें समान वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों की तुलना में प्रतिरोधक क्षमता अधिक विकसित पाई गई।

अहमदाबाद में रविवार को कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए कोवैक्सीन की डोज लगाती स्वास्थ्य कर्मी। एएफपी

**मिक्स डोज के विचार को मिला बल**

आइसीएमआर ने कहा है कि उसके अध्ययन से इस विचार को बल मिलता है जिसमें कोविशील्ड की पहली डोज के बाद कोवैक्सीन की दूसरी डोज देने की बात कही जा रही है। जाहिर है आइसीएमआर के अध्ययन के आधार पर आने वाले दिनों सरकार टीकाकरण अभियान में वैक्सीन के अलग-अलग डोज को शामिल कर सकती है।

बढ़ोतरी के बाद पांच हजार से ज्यादा घटे कोरोना के सक्रिय मामले पेज>>6

## कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को एक साल का सेवा विस्तार

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को एक साल का सेवा विस्तार प्रदान किया है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को वर्ष 2019 में दो साल के लिए देश का शीर्ष नौकरशाह नियुक्त किया गया था।

कार्मिक मंत्रालय की तरफ से शनिवार की देर रात जारी आदेश के अनुसार, 'कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1982 बैच के आइएएस अधिकारी गौबा को 30 अगस्त के बाद एक साल का सेवा विस्तार प्रदान किया है।' माना जाता है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून बनाने में गौबा की अहम भूमिका रही। वह केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव व गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं। गृह मंत्रालय में वह नक्सली डिवीजन का काम देखते थे और अन्य महती जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया।

राजीव गौबा। फाइल फोटो।

गौबा को वर्ष 2019 में दो साल के लिए देश का शीर्ष नौकरशाह नियुक्त किया गया था

पंजाब में जन्मे गौबा ने पटना यूनिवर्सिटी से भौतिकी में स्नातक किया। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार की सेवा में वापसी से पहले वह 15 महीनों तक झारखंड सरकार के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में चार वर्षों तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित अफसरों की उपस्थिति अनिवार्य पेज>>3

45 लाख डोज टीका हर माह मिले तो साल के अंत तक राजधानी में सबको टीका लग सकेगा। फिलहाल 19.73 फीसद लोगों को ही टीके की दोनों डोज लग पाई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 9 अगस्त, 2021

## न्यूज गैलरी

### एंबियंस ग्रुप के मालिक राज सिंह को भेजा जेल

**नई दिल्ली:** मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए गुरुग्राम स्थित एंबियंस ग्रुप के मालिक राज सिंह गहलोत की रिमांड अवधि शनिवार को समाप्त हो गई। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गहलोत को पटियाला हाउस के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत में पेश किया। जांच अधिकारी ने गहलोत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। इसके बाद उसे 21 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया। ईडी ने 800 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गहलोत को 30 जुलाई को गिरफ्तार किया था। (जासं)

### विदेशी मुद्रा की तस्करी के आरोप में अफगानी पकड़ा गया

**नई दिल्ली:** आइजीआइ एयरपोर्ट पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के कर्मियों ने विदेशी मुद्रा की तस्करी के आरोप में अफगानिस्तानी नागरिक सैयद जावीद सदद को पकड़ा है। आरोपित को एयरपोर्ट कस्टम विभाग के हवाले कर दिया गया है। सीआइएसएफ की खुफिया टीम ने रविवार सुबह 10.15 बजे आरोपित को टर्मिनल 3 के सिक्योरिटी होल्ड एरिया में संदिग्ध हालत में घूमते हुए पाया। उसके बैग से 17 हजार 250 अमेरिकन डालर व 4.07 लाख भारतीय रुपये मिले। (जासं)

### छात्राओं को पुरस्कृत करेगा आइजीडीटीयूडब्ल्यू

**नई दिल्ली:** इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कोरोना काल में सामाजिक और तकनीकी रूप से उत्कृष्ट कार्य करने वाली छात्राओं को सम्मानित करेगा। इनके ऐसे कार्य (नवाचार) को देखा जाएगा जिससे कोरोना काल में मदद मिली हो। ऐसा करने वाली छात्राओं से 10 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। विवि 15 अगस्त को 'कोरोना योद्धाओं की सफल कहानियां' नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाली छात्राओं को क्रमशः पांच हजार, तीन हजार व दो हजार रुपये भी पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। (जासं)

### भारत छोड़ो की वर्षगांठ पर शुरू हुआ भारत जोड़ो आंदोलन

**नई दिल्ली:** भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर जंतर मंतर के नजदीक से 'भारत जोड़ो आंदोलन' शुरू हुआ। इस मौके पर दिल्ली-एनसीआर के साथ ही पड़ोसी राज्यों से काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में अभिनेता गजेंद्र चौहान के साथ ही धार्मिक-आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, कानूनी विशेषज्ञ व पूर्व नौकरशाह शामिल रहे। (जासं)

# टीकाकरण में पुरुषों से पिछड़ रही हैं महिलाएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना के कहर को थामने के लिए टीकाकरण का महा अभियान अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में करीब हर कालोनी से डेढ़ से दो किलोमीटर के दायरे में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके बावजूद टीकाकरण में पुरुषों से महिलाएं पिछड़ रही हैं। उन्हें पुरुषों की तुलना में 15 लाख 93 हजार 261 डोज कम लगी है। आबादी के अनुपात से भी यह कम है। इसका कारण टीके के प्रति हिचकिचाहट व अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का भाव माना जा रहा है।

डाक्टर कहते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं अस्पताल जाने के लिए पुरुषों पर निर्भर हैं। यह भी टीकाकरण में उनके पिछड़ने की बड़ी वजह है। दिल्ली में अभी तक एक करोड़ छह लाख 88 हजार 966 डोज से अधिक टीकाकरण हो चुका है। इसके तहत 61 लाख 39 हजार 955 डोज पुरुषों को लगे हैं, जबकि महिलाओं को 45 लाख 46 हजार 694 डोज लगे हैं। दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की आबादी 826 है। यदि इस लिहाज से देखें तो जितने पुरुषों को टीका लगा है, उस आधार पर 50 लाख 71 हजार से अधिक डोज महिलाओं को लगने चाहिए थे।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज की निदेशक प्रोफेसर डा. सुनीला गर्ग ने कहा कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश में ही पुरुषों की तुलना में महिलाओं के टीकाकरण में करीब तीन करोड़ का अंतर है। इसका एक कारण महिलाओं में टीके के प्रति हिचकिचाहट अधिक होना भी है। इसके अलावा पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम नौकरीपेशा हैं। जिन लोगों को कामकाज से हर दिन बाहर निकलना है वे लोग ज्यादा टीका लगवा रहे हैं। ज्यादातर समय घर में रहने वाली महिलाओं में टीके के प्रति उत्साह कम है। ऐसे में जरूरी है कि पुरुष सदस्य आनलाइन एप्वाइंटमेंट लेते समय घर की महिलाओं के लिए भी स्लाट बुक कराएं और महिलाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें।

**जागरूकता की कमी**

- दिल्ली में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम लगी 15 लाख 93 हजार 261 डोज
- स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भी मानी जा रही कम टीकाकरण की वजह

सुधारना होगा टीकाकरण का अनुपात। फाइल

| दिल्ली में वयस्क आबादी | |
|---|---|
| कुल आबादी | 1,48,98,069 |
| पुरुष | 81,58,180 |
| महिला | 67,38,976 |
| **रविवार दोपहर तक टीकाकरण के आंकड़े** | |
| कुल टीकाकरण | 1,06,88,966 |
| पुरुषों को लगी डोज | 61,39,955 |
| महिलाएं | 45,46,694 |
| अन्य | 2,317 |
| पुरुषों व महिलाओं के टीकाकरण में अंतर | 15,93,261 |
| पुरुषों को डोज | 57.44 फीसद |
| महिलाओं को डोज | 42.53 फीसद |

## कोरोना के 66 नए मामले, 95 मरीज हुए ठीक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर में थोड़ी वृद्धि हुई है। इससे पिछले दो दिन से संक्रमण दर 0.10 फीसद बनी हुई है, जबकि संक्रमण दर घटकर 0.6 फीसद पर आ गई थी। रविवार को कोरोना के 66 नए मामले आए। वहीं 95 मरीज ठीक हुए। इससे सक्रिय मरीजों की संख्या कुछ कम हुई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 14 लाख 36 हजार 761 मामले आए हैं। इसमें से 14 लाख 11 हजार 159 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे मरीजों के ठीक होने की दर 98.21 फीसद है। वहीं मृतकों की कुल संख्या 25 हजार 66 है। इससे मृत्यु दर 1.74 फीसद है। मौजूदा समय में 536 सक्रिय मरीज हैं। दिल्ली में अभी 536 कंटेनमेंट जोन हैं। शनिवार को एक लाख 19 हजार 785 लोगों को टीका लगा। रविवार को सरकारी टीकाकरण केंद्र बंद हो पाने के कारण 11,089 लोगों को ही टीका लग पाया।

## दो वित्तीय संस्थाओं से 29 करोड़ की ठगी के मामले में कार डीलर गिरफ्तार

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :** दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दो अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से 29 करोड़ का कर्ज लेकर फर्जीवाड़ा करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित विकास चावला एक कार कंपनी का डीलर है। वह उप पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पीएफ घोटाले में भी शामिल रहा है। उसे हाल ही में लखनऊ के हजरतगंज थाना पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था।

जनकपुरी निवासी विकास आटोवेव परफार्मेंस कार प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। उसने एचडीएफसी बैंक से इन्वेंटरी फंडिंग (कारों की खरीद) के लिए 15 करोड़ की क्रेडिट सुविधा ली थी। कार के पुर्जे खरीदने के नाम पर 1.50 करोड़ रुपये नकद लिए थे। उसने बीएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से भी इन्वेंटरी फंडिंग के लिए 12.5 करोड़ की क्रेडिट सुविधा ली थी। आरोपित को कारों को बेचने से मिली राशि वित्तीय संस्थाओं के खाते में नहीं रख कर फर्जीवाड़ा किया।

# ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू, डीडीएमए ने जारी किया आदेश

**कोरोना से जंग** ▶ महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए डीडीएमए तैयार

### लाकडाउन लगाने या हटाने पर अब नहीं रहेगा संशय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के उद्देश्य से दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लेकर आदेश जारी कर दिया। इसके तहत दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वृद्धि होने पर सख्त नियम लागू होंगे। संक्रमण बढ़ते ही माल और बाजारों को आड-इवेन के दायरे में लाया जाएगा।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में बताया गया है कि कोरोना के चलते कब और किन हालातों में क्या एक्शन लिया जाएगा। इस दौरान रंगों पर आधारित अलर्ट काम करेंगे। इनमें स्तर -1 (येलो), स्तर -2 (अंबर), स्तर -3 (आरेंज) और स्तर -4 (रेड) होगा। रेड अलर्ट जारी होने पर दिल्ली में पूर्ण लाकडाउन लग जाएगा। कब लाकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब संशय की स्थिति नहीं रहेगी।

डीडीएमए कोरोना संक्रमण के डेल्टा प्लस स्वरूप को लेकर गंभीर है। डीडीएमए ने कहा है कि इस स्वरूप को दिल्ली में फैलने से रोकना है, जिसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अलर्ट के चार स्तर कलर कोड के जरिये बताए जाएंगे। लगातार दो दिन की संक्रमण दर, एक हफ्ते में संक्रमण के कुल नए मामले और एक हफ्ते में औसतन कितने आक्सीजन बेड भरे, इन आधारों पर कलर कोड आधारित अलर्ट जारी करने का फैसला लिया जाएगा। अलर्ट के स्तर के मुताबिक ही आर्थिक गतिविधियों को रोका जाएगा। वहीं अलर्ट के सभी चार स्तर में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और प्रतिष्ठान खुल सकेंगे और आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इस बार में करीब एक माह पहले डीडीएमए विस्तार से जानकारी दे चुका है। डीडीएमए की बैठक में अधिकारियों ने अस्पतालों में आक्सीजन आपूर्ति से जुड़ी तैयारियों का डाटा भी प्रस्तुत किया। उसमें बताया गया कि सरकारी व निजी अस्पतालों में कुल 160 आक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनकी क्षमता 148.11 मीट्रिक टन होगी।

### 10वीं-12वीं के बच्चे प्रैक्टिकल व दाखिले के लिए जा सकेंगे स्कूल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से करना होगा पालन
- शर्तों के साथ साप्ताहिक बाजार भी खुल सकेंगे

अनलाक की प्रक्रिया के तहत सोमवार से दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजारों को खोला जा रहा है। इसके साथ 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल भी खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, यह अनुमति नामांकन, बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल गतिविधियों के लिए ही दी गई है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में कोरोना के नियमों का सभी को पालन करना होगा। इसके अलावा साप्ताहिक बाजारों में भी दुकानदारों एवं बाजार में आने वाले लोगों को कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करना होगा। यदि किसी बाजार में नियमों का उल्लंघन होते पाया जाता है, तो वहां संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कोई भी अनधिकृत साप्ताहिक बाजार भी नहीं लगेगा और न ही सड़क किनारे लगने वाले साप्ताहिक बाजार को खोलने की अनुमति है। इसके अलावा स्कूल परिसरों में अब बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा सकेगा।

दरअसल, डीडीएमए ने स्कूलों में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करने की अनुमति दे दी है। इस शिविरों में सभी आयु वर्ग के बच्चे अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ जा सकते हैं। शिक्षा निदेशालय इन गतिविधियों के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करेगा, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन हो रहा है।

## ट्विटर ने सरकार के दबाव में राहुल का ट्वीट हटाया : कांग्रेस

- पार्टी ने अनुसूचित जाति की बच्ची के मामले में पीएम की चुप्पी पर उठाया सवाल
- सरकार पर पीड़ित परिवार को सहायता नहीं देने का लगाया आरोप

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** कांग्रेस ने रविवार को मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में अनुसूचित जाति की नौ वर्षीय बच्ची के कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में अपनी चुप्पी तोड़ें और उसके परिवार को जल्द न्याय प्रदान करें। विपक्षी दल ने यह भी आरोप लगाया कि ट्विटर ने भारत सरकार के दबाव में जल्दबाजी में काम किया और राहुल गांधी के ट्वीट को हटाने तथा पीड़ित परिवार की तस्वीरें डालने के लिए उनके खाते को निलंबित कर दिया। कुछ अन्य अकाउंट जिन पर ऐसी ही तस्वीरें थीं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ट्विटर से मैं कहना चाहूंगी-डरो मत।

उन्होंने कहा, यह कदम जल्दबाजी में उठाया गया। जो हुआ उससे हम बेहद निराश हैं। यह अत्यंत चुनिंदा कदम है। जो इंसाफ मांगते हुए परिवार के साथ खड़ा हो, आप उसका ट्वीट हटा दें और उसका ट्विटर अकाउंट ब्लाक कर दें। श्रीनेत और रागिनी नायक ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार पर पीड़ित परिवार को सहायता नहीं देने का आरोप भी लगाया। अलका लांबा ने मांग की कि मानसून सत्र के दौरान संसद में महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए और एक दिन इसके लिए समर्पित किया जाना चाहिए। दिल्ली महिला कांग्रेस प्रमुख अमृता धवन ने समयबद्ध न्याय और छह माह के भीतर दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया होता तो अपराध को छिपाने का प्रयास किया जाता।

### राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :** दुष्कर्म व हत्या का शिकार में बच्ची के स्वजन की तस्वीर राहुल गांधी द्वारा ट्वीट किए जाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ बाल अधिकार कानून एवं पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई हो सकती है। मकरंद सुरेश ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने बच्ची के स्वजन की तस्वीर सार्वजनिक करके बाल अधिकार व पोक्सो के कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का पुलिस को निर्देश दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि तस्वीर राजनीतिक लाभ के लिए ट्विटर पर साझा की गई है। उन्होंने याचिका में यह भी कहा कि दुष्कर्म और हत्या जैसे मामले में तस्वीर को साझा करके राहुल गांधी ने स्वजन के दर्द को और अधिक बढ़ाने का काम किया है।

# 98 हजार बढ़ेगा दिल्ली सरकार के मंत्रियों का वेतन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

**72** हजार से बढ़ाकर एक लाख 70 हजार करने के प्रस्ताव को मिली कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री व दिल्ली सरकार के मंत्रियों का वेतन 72 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख 70 हजार करने का प्रस्ताव दिया है। इसे दिल्ली कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। इसी तरह दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में मुख्य सचेतक व विपक्ष के नेता को भी यही वेतन मिलेगा।

इस प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली सरकार के मंत्रियों का मूल वेतन 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये किया गया है। प्रतिदिन मिलने वाला भत्ता एक हजार से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया है। विधानसभा क्षेत्र संबंधी भत्ते को 18 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है। सचिव रखने के लिए 25 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है व 10 हजार रुपये का अतिरिक्त भत्ता दिया गया है। इस प्रकार मंत्रियों का कुल वेतन 1.7 लाख हो जाएगा। बता दें कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का विरोध किया है।

### घूमने के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये मिलेंगे

मंत्रियों को परिवार सहित देश में घूमने के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की राशि मिलेगी। दो डाटा इंट्री आपरेटर रखने के लिए 30 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। गाड़ी खरीदने के लिए 12 लाख रुपये एडवांस राशि दी जाएगी। इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय से मार्च 2020 में अनुमति मिल गई थी, लेकिन कोरोना के कारण दिल्ली सरकार ने इसे अनुमति नहीं दी थी। बता दें कि हाल ही में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली के विधायकों का वेतन 90 हजार रुपये करने की अनुमति दी है। विधायकों को भी देश में परिवार सहित घूमने के लिए एक लाख रुपये की राशि मिलेगी। विधायकों के वेतन में वर्ष 2011 के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी।

## एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा की गई कड़ी

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :** इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल व आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा की कमान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों ने संभाली हुई है, वहीं टर्मिनल के बाहर की सुरक्षा का घेरा दिल्ली पुलिस व सीआइएसएफ के जवान आपसी सामंजस्य से संभाले हुए हैं। पूरे इलाके में जगह-जगह पिकेट लगाए गए हैं।

सीआइएसएफ से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस से उन्हें सूचना मिली कि एक ईमेल आया है, जिसमें अलकायदा की ओर से एयरपोर्ट पर बम धमाके की धमकी दी गई है। सीआइएसएफ अधिकारी ने बताया कि इसी तरह की एक धमकी दिल्ली पुलिस के पास मार्च महीने में भी ईमेल के जरिये आई थी। बाद में यह अफवाह साबित हुई, लेकिन स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस व सीआइएसएफ दोनों अपने-अपने स्तर पर सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हैं। कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसे लेकर सुरक्षाकर्मियों को और भी ज्यादा चौकस रहने को कहा गया है।

# मुख्यमंत्री पोषाहार योजना शुरू, बेघर गरीबों को रैन बसेरों में मिलेगा खाना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री पोषाहार योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन की साझेदारी से राजधानी के सभी रैन बसेरों में गरीबों को दो वक्त का भोजन दिया जाएगा। योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट से पहले हर साल दिल्ली सरकार रैन बसेरों में बढ़ोतरी पर डांट खाती थी, लेकिन आप सरकार ने रैन बसेरों की हालत बहुत अच्छी कर दी है। योजना का शुभारंभ सराय काले खां स्थित रैन बसेरे में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन, अक्षय पात्र फाउंडेशन के चेयरमैन मधु पंडित दासा, आप विधायक विशेष रवि और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के समय में उनकी सरकार ने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को भोजन का भी इंतजाम करना शुरू किया था। इस कार्य में अब दिल्ली सरकार के साथ अक्षय पात्र फाउंडेशन भी सहयोग कर रहा है। यह संस्था धर्म का काम करती है, जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को भूखे नहीं सोने देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार जब वह बेंगलुरु गए थे, तब अक्षय पात्र का किचन और सारा सेटअप देख कर आए थे। यह संस्था बेहद साफ-सफाई के साथ मशीनों से खाना बनाती है। दिल्ली सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन के बीच में आज से जो यह साझा कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसके जरिये सभी रैन बसेरों में अब हमेशा खाना खिलाया जाएगा।

अक्षय पात्र फाउंडेशन के चेयरमैन मधु पंडित दासा ने कहा कि दिल्ली सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान अपने नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम कर रही है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा शहर भर में स्थापित रैन बसेरे इन प्रयासों के उदाहरण हैं।

सराय काले खां में मुख्यमंत्री पोषाहार योजना के तहत बेघरों के बीच खाना वितरित करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (दाएं से दूसरे) साथ में मंत्री सत्येंद्र जैन (दाएं)। सौ. दिल्ली सरकार

## फर्जीवाड़ा कर कार बेचने वाले गिरोह के तीन लोग गिरफ्तार

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली:** दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कार फाइनेंस करवाकर बैंकों को चूना लगाने वाले एक गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपित पहले विभिन्न बैंकों से फर्जी नाम व पते पर नई कारें फाइनेंस करवाते थे। फिर एक-दो किस्तें जमा करने के बाद वे परिवहन कार्यालयों में बैंकों से लोन पूर्ण होने संबंधी फर्जी एनओसी जमा कर देते थे और कारों को ग्राहकों को बेच देते थे। गिरोह मुख्यतौर पर दिल्ली-एनसीआर व उत्तर प्रदेश में इस तरह के धंधे को अंजाम दे रहा था।

डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बताया कि फर्जीवाड़े की शिकायत एक्सिस बैंक के जरिये मार्ग से पुलिस को मिली थी। गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम अमर कालोनी निवासी राजीव कुमार, लोनी, गाजियाबाद निवासी वैभव राणा व विजेंद्र राणा हैं। इनकी निशानदेही पर सात कारें बरामद की गई हैं। इनमें फारच्यूनर, क्रेटा, होंडा सिटी, ब्रेजा, होंडा अमेज, स्विफ्ट, सेल्टोस शामिल हैं। विजेंद्र राणा के खिलाफ हरियाणा में हत्या और अपहरण का मामला भी दर्ज है। उक्त मामले में वह 14 साल जेल की सजा काट चुका है।

**पर्यावरण**

केंद्रीय परियोजनाओं के लिए पेड़ काटे जाने के बदले पौधे लगाने के लिए भूमि देने का केंद्र सरकार से किया अनुरोध, पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी ने इस मुद्दे पर चर्चा कर दिल्ली के अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी देने को कहा

# डीडीए ने पौधे लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों में मांगी जमीन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

राजधानी में जमीन की कमी को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पौधारोपण के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पड़ोसी राज्यों में जमीन मांगी है। डीडीए का कहना है कि केंद्रीय परियोजनाओं के लिए शहर में वन भूमि का अधिग्रहण किए जाने पर आसपास के राज्यों में प्रतिपूरक पौधारोपण की अनुमति दी जाए। मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफएसी) ने पिछले दिनों इस मुद्दे पर चर्चा की और दिल्ली के अधिकारियों से अतिरिक्त जानकारी मांगी है।

डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए दिल्ली में बहुत सीमित भूमि उपलब्ध है। योजना बनाई गई थी कि दिल्ली के 15 फीसद क्षेत्र को हरित आवरण के लिए अलग रखा जाएगा। लेकिन यह क्षेत्र पहले से ही पौधारोपण या अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के कारण संतृप्त है। इसलिए प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए अब खाली गैर-वन भूमि नहीं है।

उन्होंने बताया कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिपूरक पौधारोपण उपयुक्त गैर वन भूमि पर किया जाना है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लागू की गई परियोजनाओं के मामले में प्रतिपूरक पौधारोपण भी वन क्षेत्र की सीमा से दो गुना अधिक किया जा सकता है। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अपवादात्मक मामलों में जहां एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है तो केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लिए किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जमीन चिह्नित की जा सकती है।

अपनी हालिया बैठक में एफएसी ने देखा कि प्रतिपूरक पौधारोपण मानदंडों में किसी भी तरह की छूट से दिल्ली के वन क्षेत्र में कमी आएगी जो वर्तमान और भविष्य में दिल्ली वासियों के लिए वांछनीय स्थिति नहीं है। इसलिए, कमेटी ने दिल्ली के वन विभाग और डीडीए को दुनिया के अन्य जगहों और दिल्ली के प्रमुख शहरों में हरित आवरण के तुलनात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है।

एफएसी ने यह पता लगाने के लिए अतिरिक्त जानकारी भी मांगी कि मानदंडों में ढील दिल्ली के ड्राफ्ट मास्टर प्लान और ब्लू ग्रीन पालिसी के मसौदे में हरित कवर को कैसे प्रभावित कर सकती है। दिल्ली सरकार और डीडीए आइआइटी-दिल्ली, टेरी आदि प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की एक बहु-विषयक टीम द्वारा एक अध्ययन भी करवाएंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि आसपास के राज्यों में प्रतिपूरक पौधारोपण तत्काल भूमि किस हद तक उपलब्ध होगी।

गौरतलब है कि दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत एक पेड़ काटने पर 10 पौधे लगाए जाने चाहिए। 2019 में जारी इंडिया स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली का हरित आवरण, जिसमें वन और वृक्ष शामिल हैं, वर्तमान में कुल क्षेत्रफल का 324 वर्ग किमी या 21.9 फीसद है। 2017 में यह 305.4 वर्ग किमी या 20.6 फीसद था।

हरियाली बढ़ाने की कोशिश। फाइल फोटो

## सीबीआइ अधिकारी बन ठगी करने वाले गिरोह के पांच लोग गिरफ्तार

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली**

सीबीआइ अधिकारी बनकर ज्वेलर व उनके कर्मचारियों से ठगी करने वाले कुख्यात ईरानी गिरोह के पांच बदमाशों को करोलबाग थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर ज्वेलरों को अपना शिकार बना रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से सुराग मिलने के बाद पुलिस ने पांचों आरोपितों को दबोच लिया है। इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में 80 से अधिक मामले दर्ज हैं।

डीसीपी मध्य जिला जसमीत सिंह के मुताबिक 27 जुलाई को बैंक स्ट्रीट करोलबाग में सीबीआइ अधिकारी बनकर पांच बदमाशों ने एक ज्वेलर के कर्मचारी से 300 ग्राम सोने के आभूषण की ठगी की थी। शिकायत मिलने पर करोलबाग थाने के एसीपी विद्युत कौशिक व एसएचओ मनीष जोशी के नेतृत्व में करोलबाग मार्केट से हनुमान चौक के बीच करीब एक किलोमीटर तक के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के मोहल्ला ईरानी निवासी मुहम्मद अली उर्फ मुहम्मद साबिर हुसैन की पहचान हुई। जांच में पता चला इसी मोहल्ले के मुहम्मद काबिल उर्फ इमरान हुसैन, अनवर अली, शौकत अली जाफरी व मुख्तियार हुसैन उर्फ शेख मुख्तार उमर भी गिरोह में शामिल हैं। मुहम्मद अली गिरोह का सरगना है। जांच में पता चला कि 26 जून को पांचों बदमाश ट्रेन से दिल्ली आए थे। उनकी वापसी की टिकट तीस जून की थी। इसके बाद पुलिस टीम ने एक अगस्त को भोपाल से इलाहाबाद जा रही ट्रेन में सवार पांचों आरोपितों को झांसी जंक्शन, उत्तर प्रदेश से दबोच लिया। पकड़े गए पांचों आरोपित आपस में रिश्तेदार हैं।

**10** वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट व इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है सीआइएससीई ने आइसीएसई की। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी और रिजल्ट 20 सितंबर तक घोषित होगा।



# समुद्री सुरक्षा पर यूएनएससी परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की तरफ से आयोजित एक उच्चस्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। पीएमओ ने बताया कि मोदी यूएनएससी की खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने रविवार को बताया कि परिचर्चा में यूएनएससी के सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के शामिल होने की संभावना है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी व प्रमुख संगठन भी हिस्सा ले सकते हैं। परिचर्चा का विषय है, 'समुद्री सुरक्षा बढ़ाना- अंतरराष्ट्रीय सहयोग का विषय।'

पीएमओ ने बताया कि यूएनएससी

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जागरण आर्काइव

ने समुद्री सुरक्षा व अपराध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और कई प्रस्ताव पारित किए हैं। हालांकि, यह पहला मौका होगा, जब समुद्री सुरक्षा पर उच्चस्तरीय खुली परिचर्चा विस्तार से होगी। एएनआइ के अनुसार, परिचर्चा शाम 5.30 बजे शुरू होगी।

पीएमओ ने कहा, 'कोई एक देश समुद्री सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की चिंता नहीं कर सकता। इसलिए यूएनएससी में इसे व्यापक विषय के रूप में बढ़ाना होगा। समुद्री सुरक्षा में एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, जिससे वैध समुद्री गतिविधियों की रक्षा हो और पारंपरिक व गैर-पारंपरिक खतरों से निपटा जा सके।'

पीएम मोदी ने वर्ष 2015 में क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास (सागर) का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारतीय इतिहास में समुद्र का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा था कि समुद्र देश की शांति और संपन्नता को बढ़ाने में मददगार है।

## कोविड व क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा के लिए दौरे पर आए दक्षेस महासचिव

नई दिल्ली, प्रेट्र : दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के महासचिव एशला रूबान वेराकून कोरोना वायरस महामारी से निपटने समेत क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा के लिए एक सप्ताह के आधिकारिक दौर पर रविवार को भारत पहुंचे हैं। वह विदेश राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला व विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्वी) रीवा गांगुली दास के साथ चर्चा करेंगे।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, वेराकून 14 अगस्त तक भारत दौरे पर हैं। सूत्रों ने बताया कि वेराकून दक्षेस के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग को और बढ़ाने के साथ ही कोरोना वायरस महामारी से निपटने के तौर-तरीकों पर भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। दक्षेस के सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।

# स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित अफसरों की उपस्थिति अनिवार्य

- कैबिनेट सचिव ने किया आगाह, शामिल नहीं होने को गंभीरता से लिया जाएगा
- केवल संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को ही किया गया है आमंत्रित

नई दिल्ली, प्रेट्र : कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित अधिकारियों को आगाह किया कि अगर वे इसमें शामिल नहीं हुए तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को भेजे पत्र में गौबा ने कहा कि लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह की अपनी महत्ता है। समारोह के लिए आमंत्रित अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे इसमें भाग लेंगे। उन्होंने कहा, ऐसा देखा गया है कि कुछ आमंत्रित अधिकारी समारोह में शामिल नहीं होते हैं। इस अवसर की बड़ी राष्ट्रीय महत्ता होने पर विचार करते हुए यह व्यवहार अनुचित है। अधिकारियों को साफ तौर पर याद दिलाने की जरूरत है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होना उनका कर्तव्य है।

### गृह मंत्रालय ने प्लास्टिक से बने झंडे का इस्तेमाल रोकने को कहा

स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का उपयोग न करें। इस तरह की सामग्री से बने तिरंगे का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक समस्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसका हमेशा सम्मान होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजन के अवसरों पर कागज के बजाय प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लास्टिक के झंडे कागज के झंडे की तरह जैविक रूप से अपघटित नहीं होते हैं। झंडे की गरिमा के अनुरूप प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का उचित निपटान सुनिश्चित करना भी एक व्यावहारिक समस्या है।

गौबा ने अपने पत्र में यह भी कहा कि कोरोना महामारी के कारण शारीरिक दूरी की जरूरत को देखते हुए केवल संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को ही इस साल समारोह में आमंत्रित किया गया है।

# विधेयकों को पारित कराने के खिलाफ एकजुट होगा विपक्ष

**टकराव जारी** ▶ मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते में भी गतिरोध टूटने के आसार नहीं

### पेगासस जासूसी मामले पर बहस की मांग में भी नहीं आएगा बदलाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते में भी विपक्ष पेगासस जासूसी मामले पर बहस की मांग का अपना रुख नहीं बदलेगा और दोनों सदनों में कई अहम विधेयकों को बिना चर्चा आनन-फानन में पारित कराए जाने को भी मुद्दा बनाएगा। विपक्षी नेताओं ने संकेत दिया है कि संसद में विपक्षी आवाज की हो रही अनदेखी के साथ विधेयकों को पारित कराने के सवाल को विपक्षी दल राष्ट्रपति के पास ले जाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। संसद में पेगासस पर अपनी बात रख पाने में नाकाम रहे विपक्षी नेताओं ने रविवार को एक संयुक्त वीडियो जारी कर साफ संकेत दिया कि पेगासस मामले पर दोनों सदनों में जारी गतिरोध अगले हफ्ते भी थमने वाला नहीं है।

विपक्ष पेगासस जासूसी मामला मानसून सत्र के पहले दिन से ही उठा रहा है। बीते तीन हफ्ते से एकजुट विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही लगातार बाधित रही है। संसद में विपक्षी दलों की अगुआई

पेगासास जासूसी मामले को लेकर मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते में भी विपक्ष ने अड़ियल रुख कायम रखने के संकेत दिए हैं। जागरण आर्काइव

कर रही कांग्रेस ने आगे की रणनीति को लेकर कहा कि पेगासस और किसानों के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं का मानना है कि असल में सरकार गतिरोध को तोड़ना ही नहीं चाहती। वह पेगासस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए संसदीय परंपरा की गंभीर अनदेखी कर हंगामे और अव्यवस्था के बीच औसतन पांच मिनट में विधेयक पारित करा रही है। ऐसे में संवैधानिक मर्यादा पर हो रहे प्रहार का मसला राष्ट्रपति के समक्ष उठाया जाए, इसको लेकर सभी विपक्षी दल सहमत हैं।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बारे में कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज की अहमियत होती है। हमारे संसदीय इतिहास में अनेक बार इस तरह के गतिरोध का हल निकालने के लिए सरकारों ने पहल की है, लेकिन मोदी सरकार पेगासस पर बहस की साधारण मांग नहीं मान रही। उलटे इस गतिरोध में विधेयकों को आनन-फानन में पारित कर लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज पर बुल्डोजर चलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विधेयकों को इस तरह से पारित कराए जाने पर विपक्षी दलों के अगले कदमों की तैयारी का संकेत देते हुए कहा कि जब सरकार ही संसदीय परंपरा की अनदेखी कर रही हो, तब एकजुट होकर विपक्ष को इसका विरोध करना ही पड़ेगा।

पेगासस पर विपक्ष का आक्रामक रुख सोमवार को दोनों सदनों में जारी रहेगा, इसका साफ संदेश देने के लिए विपक्षी नेताओं ने रविवार को एक साझा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जारी किया। इसमें पेगासस और किसानों के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं कराने को लेकर सरकार को घेरा गया है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो जारी किया। इसमें सरकार से पेगासस और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की बात सुनने की अपील की गई है। तीन मिनट के वीडियो में प्रमुख विपक्षी नेताओं की छोटी-छोटी क्लिपिंग है। डेरेक ने कहा कि जब सरकारी टीवी चैनल विपक्ष को ब्लैक आउट करेंगे तो हमारे पास लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का यही तरीका है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 14 दिन से पेगासस और किसानों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मगर इसे नकारते हुए बिना बहस बिल पारित किए जा रहे हैं। इस संयुक्त वीडियो में कांग्रेस के मनीष तिवारी और दीपेंद्र हुड्डा, राजद के मनोज झा, राकांपा की वंदना चव्हाण, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी के साथ द्रमुक, माकपा, भाकपा, सपा आदि के नेताओं ने भी पेगासस पर बहस नहीं कराने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया है।

# सरकारी कर्मियों के दिव्यांग बच्चों की फैमिली पेंशन में होगा बड़ा इजाफा

- केंद्रीय मंत्री ने दी सरकार के अहम निर्णय की जानकारी, पेंशनभोगियों के बच्चों को भी होगा लाभ

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों व पेंशनभोगियों की फैमिली पेंशन में बड़ा इजाफा किया जाएगा। इस अहम निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग बच्चों की मर्यादा व देखभाल पर विशेष बल दिया था। यह निर्णय इसी क्रम में लिया गया है।

कार्मिक राज्यमंत्री सिंह ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को विशेष चिकित्सकीय देखभाल तथा वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। इस निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वे सुविधाजनक रूप से जीवन बिता सकेंगे। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के तहत पेंशनधारक की फैमिली पेंशन और दिवंगत सरकारी कर्मचारी के भाई-बहन या बच्चे की आय के नियम की पात्रता में ढील देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का मानना है कि फैमिली पेंशन के लिए पात्रता के मुद्दे पर आय का नियम परिवार के अन्य सदस्यों के मुकाबले दिव्यांग बच्चे या भाई-बहन के मामले में लागू नहीं हो सकता। मंत्री ने कहा कि सरकार ने दिव्यांग बच्चे या सहोदर के मामले में फैमिली पेंशन की पात्रता को लेकर आय के नियम की समीक्षा की और निर्णय लिया कि उनके मामले में घोषित फैमिली पेंशन की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। जागरण आर्काइव

निर्देश जारी किए हैं कि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त बच्चा अथवा भाई-बहन जीवन भर फैमिली पेंशन के लिए पात्र होंगे, बशर्ते उनकी कुल आय परिवार पेंशन के अलावा, सामान्य दर पर पात्र परिवार पेंशन से कम हो। यानी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा उठाए गए अंतिम वेतन के 30 फीसद हिस्से व उस पर स्वीकृत महंगाई राहत भत्ते के बराबर या उससे कम हो। फिलहाल परिवार का कोई सदस्य, जिनमें दिव्यांग बच्चे व भाई-बहन शामिल हैं को उस स्थिति में अपनी आजीविका कमाने वाला माना जाता है, जब फैमिली पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी आय न्यूनतम परिवार पेंशन (9,000 रुपये) और उस पर स्वीकृत महंगाई राहत भत्ते के बराबर या उससे ज्यादा हो।

### 'न्याय तक बहुत पहुंच वाले और बहुत गरीब वर्ग के बीच का अंतर खत्म करना होगा'

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, अगर हम कानून शासित समाज बनाए रखना चाहते हैं तो न्याय तक बहुत पहुंच वाले और बहुत गरीब वर्ग के बीच का अंतर खत्म करना होगा। हमें सामाजिक, आर्थिक विभिन्नता जो कि हमारे समाज की सच्चाई है, को हमेशा याद रखना होगा। हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें, जिसमें समानता वास्तविकता हो। इसीलिए न्याय तक पहुंच एक अंतहीन मिशन है।

अगर न्यायपालिका लोगों का विश्वास बनाए रखना चाहती है तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को भरोसा दिलाना होगा कि हम उनके लिए हैं। बहुत लंबे समय तक वंचित जनसंख्या न्याय व्यवस्था के बाहर रही है। लंबी, परेशानी भरी खर्चीली प्रक्रिया न्याय तक पहुंच के लक्ष्य को पाने में परेशानी है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती इन बाधाओं को पार करना है।

जस्टिस रमना ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी तकनीकी उपकरणों की मदद से हमने कानूनी सहायता को जारी रखा। हमें आश्वस्त किया गया है कि भविष्य में भी ऐसी कोई चुनौती संस्था के काम को बाधित नहीं कर पाएगी। जस्टिस यूयू ललित ने इस मौके पर कहा कि हर व्यक्ति तक मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी पहुंचाने में पोस्ट आफिस नेटवर्क का सहारा लिया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों से जरूरतमंदों की कानूनी मदद करने की अपील की।

# लोस चुनाव में खराब ईवीएम की संख्या बताने का आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की कुल संख्या बताने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता सर्टिफिकेट (एसटीक्यूसी) निदेशालय ने खराब मशीनों की संख्या उजागर की है।

केंद्रीय सूचना आयोग ने इलेक्ट्रानिक और आइटी मंत्रालय के तहत आने वाले एसटीक्यूसी निदेशालय का दरवाजा खटखटाने वाले वेंकटेश नायक की याचिका पर फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुए एम2 और एम3 जेनरेशन की इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफाइड पेपर आडिट ट्रेल (वीवीपैट) की इकाइयों के आडिट और परीक्षण की जानकारी दी जाए। इन मशीनों का निर्माण ईसीआइएल और बीईएल ने किया है। याचिकाकर्ता वेंकटेश नायक को आरटीआइ की धारा आठ (आइ)(डी) के तहत इस संबंध में सूचना देने से मना कर दिया गया था। उन्होंने एसटीक्यूसी टीम की जांच की हुई एम2 और एम3 ईवीएम की

**सीआइसी का फैसला**

- एसटीक्यूसी को आडिट अफसरों के नाम व पद गोपनीय रखने की छूट दी

सूचना आयोग ने आडिट की तारीखें और स्थान बताने का निर्देश दिया। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

संख्या और वीवीपैट की कुल संख्या भी पूछी है। उन मशीनों की भी कुल संख्या पूछी गई है, जिनका साफ्टवेयर सही नहीं पाया गया था। इसके अलावा, नायक ने एसटीक्यूसी के अफसरों के बारे में भी पूछा था। आडिट करने वाली स्वतंत्र एजेंसी और उसकी तारीखें व भौगोलिक स्थान भी पूछे थे। इसलिए आयोग ने एसटीक्यूसी को आडिट करने वाले अधिकारियों के नाम और पद तो गोपनीय रखने की छूट दे दी है लेकिन आडिट की तारीखें और स्थान बताने का आदेश दिया है।

# असम से मिजोरम में वाहनों का जाना शुरू, सरमा आज मिलेंगे मोदी से

गुवाहाटी, प्रेट्र : देश के बाकी हिस्सों से माल लेकर आए ट्रक शनिवार देर रात से मिजोरम जाने लगे। ये ट्रक असम की मिजोरम से लगने वाली विवादित सीमा के मध्य बने राजमार्ग से होकर जा रहे हैं। असम से मिजोरम के लिए वाहनों का आवागमन दोनों प्रदेशों के पुलिस बलों के बीच हुए खूनी टकराव के 13 दिन बाद शुरू हुआ है। जल्द ही रेल सेवा भी शुरू होने की उम्मीद है। एएनआइ के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा सोमवार को नई दिल्ली में प्रदेश के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और दोनों प्रदेशों के सीमा विवाद के बारे में उन्हें जानकारी देंगे।

देश के विभिन्न इलाकों से माल लेकर मिजोरम जा रहे ट्रक पिछले कई दिनों से असम के ढोलई में खड़े हुए थे। इन ट्रकों में दवाइयां, कुकिंग गैस, डीजल और अन्य जरूरी सामान था। दोनों प्रदेशों के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद तनाव कम हुआ और स्थानीय निवासियों ने सीमा पर लगाए गए अवरोध हटा लिए

ट्रक चालकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते असम के मंत्री अशोक सिंघल और परिमल सुक्लाबैद्या। एएनआइ

लेकिन ट्रक ड्राइवर सुरक्षा कारणों से मिजोरम के लिए रवाना होने को तैयार नहीं थे। अंततः शनिवार को असम के मंत्री अशोक सिंघल और परिमल सुक्लाबैद्या ने ट्रक चालकों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया तब रात में मिजोरम के लिए ट्रक रवाना हुए। असम के कोलासिब जिले के एसपी वनलालफाका राल्टे के अनुसार रविवार सुबह तक 50 वाहन असम से मिजोरम जा चुके थे। दोनों प्रदेशों के बीच वाहनों का आवागमन सामान्य हो रहा है। एसपी सीमा के नजदीक वैरेंग्टे नाम के कस्बे में मौजूद हैं। कछार जिले की एसपी रमनदीप कौर ने बताया है कि पुलिस सुरक्षा में वाहनों का आवागमन शुरू हो चुका है। कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। जबकि सिलचर स्थित मिजोरम हाउस के लाइजन आफीसर कापथंगा ने बताया है कि शनिवार शाम को मिजोरम जा रहे नौ वाहनों पर असम के लैलापुर में हमला हुआ लेकिन बाद में हालात नियंत्रित हो गए।

# जजों के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट डालने पर पांच गिरफ्तार

- आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर टिप्पणी मामले में सीबीआइ ने की कार्रवाई
- किसी बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए सांसद, पूर्व विधायक समेत कुछ लोगों से एजेंसी ने की पूछताछ

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट डालने के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इस मामले में वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा सदस्य नंदीगाम सुरेश और इसी पार्टी के अमांची कृष्ण मोहन की भूमिका जांच के दायरे में है। एजेंसी ने किसी बड़े षड्यंत्र का पता करने के प्रयास में दोनों से पूछताछ की है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा था कि निचली अदालतों के जज जब कोई शिकायत दर्ज कराते हैं तो एजेंसियां उस पर ध्यान नहीं देती हैं। हम सीबीआइ के रुख में बदलाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता।

सीबीआइ प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा, किसी बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए एजेंसी ने एक सांसद, एक पूर्व विधायक समेत कुछ लोगों से पूछताछ की है। कुछ अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिनके नाम प्राथमिकी में नहीं हैं।

### 16 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था मामला

सीबीआइ ने शनिवार को आंध्र प्रदेश से दो लोगों-पत्तापू आदर्श और एल सांबा सिवा रेड्डी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआइ ने 28 जुलाई को धामी रेड्डी कोंडा रेड्डी और पामुला सुधीर को गिरफ्तार किया था। वहीं, कुवैत में रहने वाले लिंगा रेड्डी राजशेखर रेड्डी को नौ जुलाई को भारत पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया था। सीबीआइ ने न्यायाधीशों के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट डालने के मामले में 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी मामले में एजेंसी ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है।

**रखी बात**

भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर देशवासियों को दी बधाई, 1942 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शुरू किया था यह आंदोलन

# हम सब पहले भारतीय हैं : उप राष्ट्रपति

नई दिल्ली, आइएएनएस : उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर रविवार को देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि विविधताओं के बावजूद हम सब पहले भारतीय हैं।

उप राष्ट्रपति ने कहा, 'मैं भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की वर्षगांठ पर अपने सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आंदोलन की शुरुआत गांधीजी ने अपने शक्तिशाली नारे 'करो या मरो' के साथ देशवासियों को प्रोत्साहित करने के साथ की, जिसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया और अंततः 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।'

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हमें भारत के उन वीर सुपुत्रों और सुपुत्रियों के अनगिनत बलिदानों को याद करना चाहिए, जिन्होंने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था।

उप राष्ट्रपति ने कहा कि भले ही हमारी वेशभूषा अलग है, हम अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग-अलग धर्मों का पालन करते हैं, हम सब पहले भारतीय हैं और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। यह खूबसूरत धरा हम सभी की है और एक बेहतर कल के निर्माण की यात्रा में हम सभी एक साथ हैं।

**बुराइयों को खत्म करने के लिए खुद को करें समर्पित :** उन्होंने कहा कि लोगों को भारत से गरीबी, निरक्षरता, असमानता, भ्रष्टाचार और जातिवाद, सांप्रदायिकता एवं लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए खुद को फिर समर्पित करना चाहिए।

**साझेदारी और देखभाल हमारा मूल सिद्धांत :** नायडू ने कहा कि भारतीय सभ्यता 'साझेदारी और देखभाल' के मूल सिद्धांत में निहित है। यह हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए क्योंकि हम अपने समाज में सद्भाव, भाईचारा, आपसी सम्मान और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं।

उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू। जागरण आर्काइव

### जीवन में फिर भारतीयता को अपनाएं

उप राष्ट्रपति ने कहा, 'आइए, जीवन में भारतीयता का फिर से स्वागत करें, चाहें वह मातृभाषा के उपयोग में हो, पोशाक में या भारतीय परंपराओं के सम्मान में।' उन्होंने आगे कहा, 'आइए हम एक अधिक समावेशी, आत्मविश्वास से भरे आत्मनिर्भर भारत के लिए एक साथ कदम बढ़ाएं।'

## संसदीय समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा- नौकरियां जाने की सही जानकारी दें

नई दिल्ली, प्रेट्र : एक संसदीय समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से कहा कि देश में कोविड के दौर में नौकरी खोने वालों की सही तस्वीर पेश करने के लिए वह विश्वसनीय एजेंसियों के जरिये की गई सेवानिवृत्ति पेंशन योजना ईपीएफओ के आंकड़ों और विश्लेषण का सही ब्योरा दें। पिछले साल मार्च के महीने से लाकडाउन के प्रतिबंधों के दौरान देश में आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ गई थीं।

पिछले हफ्ते संसद में पेश श्रम पर स्थायी समिति की 25वीं रिपोर्ट में कहा गया कि मंत्रालय को अन्य प्रतिष्ठित एजेंसियों के जुटाए आंकड़ों और शोध पर भी विचार करना चाहिए। साथ ही ईपीएफओ के एकत्र किए डाटा के जरिये विश्वसनीय तरीके से बेरोजगारी की दर या नौकरियां जाने का पता लगाया जा सकता है। इससे कोविड के कारण नौकरियों में आई कमी की सही जानकारी मिल जाएगी।

**कह के रहेंगे** माधव जोशी

# अब बीमारू राज्य नहीं रहा उप्र : नड्डा

**सम्मान** ▸ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने कोरोना वारियर्स का बढ़ाया हौसला

जागरण संवाददाता, आगरा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में विकास कराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, लेकिन अब उसका स्वास्थ्य अच्छा है। अब उप्र बीमारू राज्य नहीं है। कोई बीमार न पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश देता हूं, सारा देश आपके साथ खड़ा है। भाजपा अध्यक्ष आगरा में आयोजित चिकित्सक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान आगरा मंडल के कोरोना वारियर्स (चिकित्सकों) को सम्मानित किया गया।

इससे पहले उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि उप्र का पहला कोरोना का केस आगरा में मिला। इटली से लौटे कारोबारी के सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए। प्रदेश में लैब नहीं थी, लेकिन अब चार लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। आक्सीजन के मामले में प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दो लाख गांवों में हेल्थ वालिंटियर तैयार किए जाएंगे। अब तक लगभग 1.80 लाख वालिंटियर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर बूथ पर हेल्थ वालिंटियर को दो-दो हेल्थ किट दी जाएंगी। इसमें आक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, एंटीजेन टेस्ट किट, इम्युनिटी बूस्टर आदि चिकित्सीय उपकरण होंगे।

सम्मान समारोह से पूर्व बृज क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ दो सत्र में हुई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि संगठन को सर्वस्पर्शी एवं सर्वव्यापी बनाने के लिए जातिगत दीवारों को तोड़ें। विनम्रता से सभी को साथ लाएं, सेवा से सभी का विश्वास जीतें।

उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की चुनौती से बचने को वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करें। अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करें। रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाकर काम में लगाएं।

आगरा में रविवार को आयोजित चिकित्सक सम्मान समारोह में डा. एमसी गुप्ता को सम्मानित करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

### स्वतंत्र देव बोले, गुंडागर्दी का हो रहा अंत

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस गुंडागर्दी, अराजकता व आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। एक खानदान ने मिलकर पूरे राज्य को लूट लिया। अब गुंडागर्दी का अंत हो रहा है। गुंडों की संपत्ति पर बुल्डोजर चलवाने वाला कोई है तो वह पीएम मोदी और सीएम योगी हैं। भाजपा के पास ईमानदार नेतृत्व है। हाल ही में साढ़े चार लाख नियुक्तियां हुईं, एक नियुक्ति पर सवाल नहीं उठा।

> योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण से लेकर इन्सेफलाइटिस का डटकर मुकाबला किया। कोरोना पाजिटिविटी 0.001 फीसद रह गई है। उप्र में 5.35 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। 30 मेडिकल कालेज खोले गए। एमबीबीएस की 1550 सीटें बढ़ाई गई हैं।
> –जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

> तीसरी लहर की आहट को देखते हुए पहले से ही तैयारी कर ली गई हैं। किसी को भी चिकित्सीय सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कोरोना से निपटने के लिए हम पहले से तैयार थे, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छाशक्ति की वजह से हुआ।
> –योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

## मप्र विस में नहीं बोल पाएंगे मूर्ख, पप्पू, निकम्मे जैसे शब्द

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा के सोमवार से प्रारंभ होने वाले मानसून सत्र में सदस्य मूर्ख, चोर, पप्पू, निकम्मे, बेशर्म, पाखंडी सहित 1560 शब्द एवं वाक्यांश का उपयोग नहीं कर सकेंगे। विधानसभा सचिवालय ने 40 पेज की असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह पुस्तिका तैयार की है, जिसका रविवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने विमोचन किया।

पुस्तिका में 23 नवंबर, 1954 से लेकर 16 मार्च, 2021 तक विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विलोपित कराए गए शब्द एवं वाक्यांश शामिल हैं। इनमें धोबी के कुत्ते की तरह, छुट्टे सांडों की तरह फिरना, कलमुंही, सफेदपोश गुंडे, बेशर्मों की तरह बैठना, मूर्खतापूर्ण, बेशर्म, झूठा, टुच्चा, ढोंगी, पाखंडी, नालायक, जमूरा, औकात, पापी, भाड़ में जाए, निकम्मा, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री नहीं चलेगा, आपके यहां गुलामों की फौज है, बकवास, अय्याशी, निकम्मी सरकार, धिक्कार, बेशर्म हुकूमत, दस नंबरी, यार, मक्खनबाजी, भांड, चमचे, मिर्ची लगना, भ्रष्टाचारी, फालतू की बात, मोटी अकल, लल्लू मुख्यमंत्री, पागल, ढपोलशंखी, गप्पी दास, अलीबाबा चालीस चोर, धिक्कार, शिखंडी, ओछी, पप्पू पास हो जाएगा, बंटाधार सहित अन्य शामिल हैं।

## सपा सरकार बनने पर सबसे पहले कराएंगे जातीय जनगणना : अखिलेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि खुद को पिछड़ों का हमदर्द बताने वाली भाजपा ने इस तबके का हक छीना है। हक मांगने पर उन पर लाठियां चलवाई हैं। उप्र चुनाव में भाजपा को वोट की असली लाठी दलित और पिछड़े मारेंगे जिनका हक और सम्मान उसने छीना है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी जातीय जनगणना नहीं कराएगी क्योंकि उसे मालूम है कि पिछड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है। विधानसभा चुनाव में सपा सरकार बनने पर प्रदेश में सबसे पहले जातीय जनगणना कराई जाएगी।

अखिलेश लखनऊ में सपा मुख्यालय में महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। महान दल का सपा से गठबंधन है। मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए अखिलेश ने कहा कि योगी वह होता है, जो दूसरों का दर्द समझता है। मुख्यमंत्री तो 'ठोक देंगे' जैसी असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। योगी के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें लैपटाप चलाना नहीं आता, इसलिए भाजपा के संकल्प पत्र में इसका जिक्र होने के बावजूद उन्होंने युवाओं को लैपटाप नहीं दिए। बकौल, अखिलेश मुख्यमंत्री ने तो भाजपा का संकल्प पत्र तक नहीं पढ़ा। यदि पढ़ते तो उसमें पहले पन्ने पर दर्ज किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को अमली जामा पहनाते। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद को नकली बताते हुए चुटकी ली कि जब वह सड़कों के गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं तो आपके सम्मान की रक्षा कैसे करेंगे। कहा कि असली केशव तो महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य हैं। सपा सरकार बनी तो महान दल के कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ नहीं लगेगी।

**सपा में कर सकते महान दल का विलय** : सम्मेलन में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा कि हम भाजपा को रोकने के लिए महान दल का सपा में विलय भी कर सकते हैं। हम हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के 15 से 20 हजार वोट काटेंगे और समाजवादी पार्टी को इतना दिलाएंगे। उन्होंने दूसरे छोटे दलों को भाजपा की बी-टीम बताते हुए उनसे सतर्क रहने के लिए कहा।

**कोरोना काल में हुई मौतों की जांच भी कराएंगे**: अखिलेश ने दोहराया कि हमारी सरकार बनी तो प्रदेश में कोरोना काल में हुई मौतों की जांच कराई जाएगी। समाजवादी सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों की मदद भी करेगी।

बोले, उप्र चुनाव में भाजपा पर वोट की लाठी चलाएंगे दलित और पिछड़े

# हरियाणा विस में बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेगा पंजाब का कोई विधायक या अधिकारी

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

▸ 20 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में दिखेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पंजाब का कोई विधायक, अधिकारी या कर्मचारी बिना पहचान पत्र के विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। पिछले बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर अकाली विधायकों द्वारा किए गए हमले के बाद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने यह व्यवस्था दी है। मानसून सत्र के दौरान पुख्ता सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए स्पीकर ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ राज्यों के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाई है।

तीनों राज्यों के अधिकारियों की यह बैठक इसी सप्ताह होगी, जिसमें हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा स्पीकर को सौंपी गई उस रिपोर्ट को लागू करने पर मंथन होगा, जो उन्होंने बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पर हुए हमले के बाद तैयार की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा और पंजाब विधानसभा में प्रवेश के लिए सात कामन द्वार हैं। इन सातों द्वार पर पुलिस सुरक्षा सख्त रहेगी। मुख्यमंत्री पर हमला करने से पहले अकाली विधायक विधानसभा की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में बैठे थे। इसलिए इस पार पार्किंग एरिया में भी मजबूत सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। हरियाणा विस का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। विधानसभा सचिवालय मानसून सत्र की तैयारियों में जुटा हुआ है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के अनुसार विस में एक सीट पर एक विधायक के बैठने की व्यवस्था की गई है। विस सचिवालय का पूरा जोर सख्त सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगा। हरियाणा विधानसभा में प्रवेश के लिए तीन मुख्य द्वार हैं। इन सभी पर सबसे अधिक सुरक्षा इंतजाम रहेंगे। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव मुख्यमंत्री पर हुए हमले के मामले में अपनी तीन रिपोर्ट स्पीकर को दे चुके हैं, जिनसे स्पीकर संतुष्ट नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने यह मामला विधानसभा की विशेषाधिकार हनन कमेटी को भेज दिया है।

स्पीकर के अनुसार प्रीविलेज कमेटी को यह अधिकार है कि वह पूछताछ के लिए डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को बुला सकती है। यदि उसे लगता है तो सीएम पर हुए हमले का मामला विधानसभा में चर्चा के लिए भेजा जा सकता है। फिर विधानसभा उस पर कोई भी निर्णय ले सकती है। प्रीविलेज कमेटी का गठन ही विधायकों के मान-सम्मान को बरकरार रखने के लिए हुआ है। विधानसभा कमेटियों में लंबे समय से निष्क्रिय चल रहे विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाने से जुड़े सवाल पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जनता ने विधायकों को चुनकर विधानसभा में भेजा है। यदि वे विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते तो यह जनता के साथ छलावा है। इसके अतिरिक्त विधानसभा की कमेटियों में विभिन्न मसलों पर चर्चा होती है। कई ऐसे विधायक हैं, जो लंबे समय से इन बैठकों में नहीं आते।

स्पीकर के अनुसार विधानसभा कमेटियों के अध्यक्ष विधायकों ने यह लिखकर दिया है कि कुछ विधायकों के नियमित रूप से बैठकों में नहीं आने की वजह से कोरम पूरा नहीं हो पाता और वे कोई निर्णय भी नहीं ले पाते। इसलिए गैरहाजिर रहने वाले विधायकों के स्थान पर नए विधायकों को कमेटियों में शामिल किया जाए। हमने निर्णय लिया है कि गैरहाजिर रहने वाले विधायकों को आखिरी बार पत्र लिखकर पूछा जाएगा कि वे बैठकों में शामिल होंगे या नहीं। अगर वे शामिल होने का भरोसा दिलाते हैं तो ठीक है अन्यथा उनके स्थान पर नए विधायकों को कमेटियों में शामिल कर दिया जाएगा।

## हिटलर की तरह काम कर रहे हैं जगदानंद सिंह : तेजप्रताप

जागरण संवाददाता, पटना : छात्र राजद के संरक्षक एवं बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने कहा कि बिहार प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। छात्र राजद की बैठक में आरोप लगाते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप ने कहा कि लालू प्रसाद के शासनकाल में सभी गेट जनता के लिए खुले रहते थे। पहले और अब प्रदेश कार्यालय के कामकाज में जमीन-आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा कि राजद कार्यालय में अनुशासन के नाम पर तानाशाही हो रही है। कार्यालय का गेट बंद रखा जाता है। कोई सिस्टम नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष हिटलर की तरह बोलते हैं।

**कुर्सी बपौती नहीं** : तेजप्रताप यादव ने कहा, हम भी मंत्री थे, पद से हटना पड़ा। कोई कुर्सी को बपौती न समझे। ऐसी छाप छोड़नी चाहिए कि कुर्सी चली जाए तो भी लोग याद रखें। प्रदेश अध्यक्ष की अपनी सोच हो सकती है, हमारी सोच सबको लेकर चलने की है।

**इसलिए भड़के** : रविवार को छात्र राजद की राज्यस्तरीय बैठक के दौरान कार्यालय के दो मुख्य गेट में एक बंद था तथा दूसरा आधा खुला हुआ था। इस पर तेजप्रताप भड़क गए। वह पहले भी प्रदेश अध्यक्ष पर मनमानी करने का आरोप लगा चुके हैं।

# पटना में फ्लेक्स से गायब हुआ जदयू अध्यक्ष का नाम, मिली चेतावनी

राज्य ब्यूरो, पटना

▸ केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार 16 को पटना आ रहे आरसीपी सिंह

जदयू के प्रदेश कार्यालय में रविवार को पूरे दिन एक फ्लेक्स ने तल्खी बनाए रखी। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के स्वागत में जदयू के प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक अभय कुशवाहा ने बड़े आकार का फ्लेक्स जदयू प्रदेश कार्यालय की चारदीवारी के समीप लगा दिया। इसमें पार्टी के सभी नेताओं का जिक्र था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का नाम गायब था। बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निर्देश देकर उस फ्लेक्स को हटवाया और चेतावनी भी दी। बता दें, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह 16 अगस्त को पटना आने वाले हैं। केंद्र में मंत्री बनने के बाद उनका यह पहला दौरा है।

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी कार्यालय में प्रवेश करते समय उन्होंने फ्लेक्स देखा। पहले उन्होंने उसे हटाने का निर्देश दिया और उसके बाद अभय कुशवाहा से बात की। बताया कि पार्टी के प्रोटोकाल के लिहाज से इस तरह का फ्लेक्स अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। इस बाबत जब अभय कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बहरहाल वह नवादा में हैं। फ्लेक्स लगाने के लिए उन्होंने जरूर कहा था, लेकिन उसे देखा नहीं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से बात कर अपनी गलती स्वीकार कर ली है। नए तरीके से फ्लेक्स तैयार कर लगाया जाएगा।

**उपेंद्र और मेरे एकमात्र नेता नीतीश कुमार** : जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से मेरी मुलाकात पर अगर किसी की छाती पर सांप लोट रहा है तो मैं क्या करूं! राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह पहली बार रविवार को उपेंद्र कुशवाहा के घर सुबह के नाश्ते के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि दोनों को मिलकर जदयू को मजबूत बनाना है और दोनों के एकमात्र नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उन्हें मजबूत बनाना है, तभी पार्टी भी मजबूत होगी।

दरअसल, ललन सिंह से पूछा गया था कि विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा से उनके रिश्ते में तल्खी आ गई है। ललन सिंह का जवाब था कि विपक्ष तो बिना जमीन के पौधा उगा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पुराने साथी हैं। लोकदल के जमाने से ही वे लोग साथ काम करते रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। बकौल ललन, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। इसलिए मुलाकात का सिलसिला तो चलता रहेगा।

### राजग में सहमति नहीं बनी तो उप्र-मणिपुर में अकेले लड़ेगा जदयू

राज्य ब्यूरो, पटना : उत्तर प्रदेश (उप्र) और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू भी दांव आजमाएगा। जदयू की सोच है कि वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़े। अगर सहमति नहीं बनी तो पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। दोनों राज्यों में जदयू के चुनाव लड़ने का प्रमुख कारण राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना है, जिसके लिए एक निश्चित संख्या में वोट और संसदीय प्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है। पार्टी की बिहार इकाई के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के साथ अन्य प्रवक्ताओं ने कहा कि बिहार और अरुणाचल प्रदेश में जदयू को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता है। अब अगली कोशिश इसे राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का दर्जा दिलाने की है।

# भाजपा विरोधी दलों के नेताओं संग ममता करेंगी बैठक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▸ अगले माह फिर दिल्ली जाएंगी बंगाल की मुख्यमंत्री

बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनने को बेकरार हैं। यही वजह है कि उन्होंने भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश अभी से ही शुरू कर दी है। पिछले दिल्ली दौरे के दौरान तृणमूल प्रमुख कहा था कि वह हर दो महीने में दिल्ली आएंगी। ऐसे में ममता आगामी सितंबर के मध्य में फिर दिल्ली जाने की योजना बना रही हैं। सूत्रों ने बताया कि वह इस बार दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में किसान सम्मेलन भी कर सकती हैं।

तृणमूल की राज्यसभा सदस्य डोला सेन का कहना है कि तृणमूल प्रमुख सितंबर में दिल्ली का दौरा करेंगी। इस बार कांस्टीट्यूशन क्लब में भाजपा व पीएम विरोधी व किसान नेताओं के साथ अलग-अलग बैठक करेंगी। अपने पिछले दौरे में भी उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर कमल नाथ, आनंद शर्मा समेत कई नेताओं के साथ बैठक की थी। पीएम से भी मिली थीं। सेन का कहना है कि ममता दिल्ली पहुंचेंगी तो गाजीपुर, टिकरी बार्डर व जंतर-मंतर भी जा सकती हैं। वह वहां के आंदोलनकारियों से मुलाकात करेंगी।

त्रिपुरा के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस की नजर असम पर भी है। ममता बनर्जी ने असम के विधायक अखिल गोगोई को वहां पार्टी का नेतृत्व करने की पेशकश की है। असम के शिवसागर से विधायक और कृषक मुक्ति संग्राम समिति के नेता अखिल गोगोई ने शनिवार को ममता बनर्जी से मुलाकात की। अखिल गोगोई का कहना है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों का गठबंधन 2024 में केंद्र से भाजपा को बेदखल करेगा।

# लोगों से बोले दिलीप घोष, काम नहीं करें भाजपा पार्षद तो लैंप पोस्ट से बांध दें

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बंगाल भाजपा अध्यक्ष व मेदनीपुर से सांसद दिलीप घोष का गुस्सा रविवार को अपनी पार्टी के ही एक पार्षद के खिलाफ फूट पड़ा। खड़गपुर इलाके में जलजमाव की समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोगों द्वारा भाजपा पार्षद के काम नहीं करने की शिकायत सुनकर घोष ने अपना आपा खो दिया और लोगों से कहा कि वह पार्षद के घर के सामने जाकर कचरा फेंके और शौच करें। घोष यही नहीं रुके, उन्होंने स्थानीय लोगों को यह सलाह भी दी कि वे भाजपा पार्षद को लैंप पोस्ट (पोल) से बांध दें। घोष की यह बात सुनकर स्थानीय लोग भी हैरान रह गए।

बता दें कि खड़गपुर इलाका घोष का गढ़ माना जाता है और 2016 में पहली बार वे यहीं से विधायक चुने गए थे। दरअसल रविवार को घोष का खड़गपुर ग्रामीण इलाके में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने का कार्यक्रम था। इससे पहले सुबह खड़गपुर के वार्ड नंबर-दो में घोष पार्टी के एक बीमार कार्यकर्ता को देखने गए थे। यहां से जब वह निकले तभी स्थानीय लोगों के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा और उनकी गाड़ी रोककर इलाके में जलजमाव की शिकायत की। स्थानीय लोगों ने जब उनसे कहा कि इस वार्ड के पार्षद भाजपा के ही हैं, तब वह आपा खो बैठे। उन्होंने लोगों से कहा कि उनके घर (पार्षद) जाओ और कचरा फेंको, शौच... करो। यही नहीं, उन्होंने पार्षद को लैंप पोस्ट से बांधकर रखने की भी सलाह दी। घोष ने आगे यह भी कहा कि उन्होंने विधायक व एमपी कोटे का पैसा पहले ही नगर पालिका को दिया था, लेकिन अभी तक खर्च नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि नगरपालिका के खिलाफ प्रदर्शन व सड़क अवरोध करने पर मैं आपके साथ हूं।

दिलीप घोष ने आपा खोया। जागरण आर्काइव

### भाजपा पार्षद ने बयान पर जताई आपत्ति

इधर, घोष के इस बयान पर स्थानीय भाजपा पार्षद ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि उन्हें एक जनप्रतिनिधि के बारे में इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, स्थानीय तृणमूल नेताओं ने भी इस बयान को लेकर घोष की आलोचना की है।

# त्रिपुरा में दिनभर चला तृणमूल कांग्रेस का सियासी ड्रामा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

▸ टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ त्रिपुरा जाकर अभिषेक ने जताया विरोध

बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भाजपा के बीच जंग तेज हो गई है। त्रिपुरा के धलाई जिले में शनिवार को तृणमूल नेताओं पर हुए कथित हमले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार रविवार सुबह वहां के दौरे पर पहुंचे। उनके साथ मंत्री ब्रात्य बसु, राज्यसभा सदस्य डोला सेन व अन्य तृणमूल नेता भी थे।

अभिषेक की अगुवाई में तृणमूल नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले एवं कोविड नियमों के उल्लंघन में 12 नेताओं/कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कड़ा प्रतिवाद जताया। त्रिपुरा में पूरे दिन तृणमूल का सियासी ड्रामा चलता रहा और उनके निशाने पर भाजपा की बिप्लब देव सरकार रही। इससे पहले सुबह अगरतला हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी गिरफ्तार पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए सीधे खोवई के लिए रवाना हो गए। खोवई थाना पहुंचकर अभिषेक ने रात्रि कर्फ्यू लगने के बाद कोविड पाबंदियों का उल्लंघन के आरोप में 12 टीएमसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी रिहाई की मांग की। अभिषेक इस मांग को लेकर घंटों थाने में ही बैठे रहे। यही नहीं गिरफ्तारी के खिलाफ अभिषेक व अन्य तृणमूल नेताओं ने थाने में पुलिस अधिकारी के साथ काफी कहासुनी व बदतमीजी भी की। शाम में जब खोवई जिला अदालत से टीएमसी कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई उसके बाद अभिषेक थाने से बाहर निकले। इससे पहले अदालत के बाहर भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया।

**सियासत**

उप्र में 13 फीसद मानी जाती है निषादों की आबादी, अबकी चुनाव में इनको साधने के लिए भाजपा को चलना होगा बड़ा दाव

# निषादों के हाथ सियासी पतवार, किसकी नैया लगाएंगे पार

अजय जायसवाल, लखनऊ

अपनी नाव में बिठा कर गंगा पार कराने के लिए केवट ने प्रभु श्रीराम के चरण धोए थे, लेकिन आज राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि सभी दल उसी निषाद समाज की मान-मनौव्वल में लगे हैं कि चुनावी नैया पार हो जाए। इस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे दल संदेश दे चुके हैं कि सियासी पतवार उनके हाथ में है। अपने मजबूत वोट बैंक से वह बड़े राजनीतिक दलों का खेल कई सीटों पर बिगाड़ सकते हैं। चुनौतीपूर्ण चुनाव में कोई दल किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए भाजपा हो या फिर सपा व अन्य दल, सभी का प्रयास है कि निषाद समाज उनके साथ रहे। इन्हें भी किसी बड़ी पार्टी के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए वह इसकी बड़ी कीमत वसूलने की कोशिश में भी हैं।

**160 विस सीटों पर प्रभाव**: सूबे की 50 फीसद से अधिक पिछड़ी आबादी में तकरीबन 13 फीसद निषाद हैं जो अति पिछड़ी उपजातियों में माने जाते हैं। समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं का स्पष्ट तौर पर दावा है कि राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से उनके समाज का 160 सीटों पर ठीक-ठाक प्रभाव है। इन सीटों पर 60 हजार से लेकर 1.20 लाख तक वोट निषाद समाज का है। वैसे अन्य सीटों पर भी 10-20 हजार वोट का दावा किया जाता है। यही कारण रहा है कि निषाद समाज के वोटबैंक पर सभी राजनीतिक पार्टियों की सदैव नजर रही है। इस वोटबैंक को साधने के लिए समय-समय पर बड़े-बड़े दांव चले भी गए हैं। सबसे बड़ा दांव समाज की अति पिछड़ी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने या वैसा ही आरक्षण देने की मांग का रहा है। जिस पार्टी ने भी इस दिशा में कुछ करने की बात कही, समाज का वोट उसी पार्टी को जाता रहा है।

**तेज हुईं गतिविधियां** : माना जाता है कि 2007 में बसपा, 2012 में सपा और फिर 2017 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में निषाद समाज की खास तौर से पूर्वांचल में बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री के गृह नगर गोरखपुर में तो निषाद वोटबैंक निर्णायक भूमिका तक में रहा है। छह माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर निषाद समाज के वोट को जुटाने के लिए सभी पार्टियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। संगठन में स्थान देने के साथ ही राज्यसभा सदस्य बनाकर जय प्रकाश निषाद के जरिये भाजपा इस समाज में पैठ मजबूत करने में जुट गई है। बिहार सरकार के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी की पिछले दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के भी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। दूसरी ओर सपा ने भी भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री काजल निषाद को साथ लेकर निषाद समाज को अपने से जोड़ने की कोशिश की है। पार्टी पिछले दिनों वाराणसी में मल्लाहों की नाव यात्रा निकाल चुकी है। पार्टी का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ 10 अगस्त को जालौन में फूलन देवी की जयंती भी मनाएगा। हालांकि, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के छोटे-छोटे दलों की सक्रियता से अबकी पहले जैसी स्थिति नहीं दिख रही है।

**दो टूक बात पर अड़े छोटे दल** : भाजपा के साथ आए निषाद (निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल) पार्टी के डा. संजय निषाद का बेटा भाजपा से सांसद है, लेकिन उनकी अब भाजपा से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। डा. निषाद कहते हैं कि भाजपा अपना वादा नहीं निभा रही है। वह कहते हैं कि आरक्षण देने पर भाजपा के रुख को आचार संहिता लगने तक देखेंगे। वह समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और मंत्रिपरिषद में भागीदारी भी चाहते हैं। कहते हैं कि समाज को आरक्षण मिलने पर ही वह भाजपा के साथ रहेंगे। बिहार में एनडीए के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) की यूपी में बढ़ती सक्रियता को वह गंभीरता से नहीं लेते।

### इसीलिए 'पालिटिकल सीन' में फूलन देवी

भाजपा के बाद सपा भी छोड़कर वीआइपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने लोटनराम निषाद कहते हैं कि अगर आरक्षण मिले तो उनकी पार्टी, भाजपा में विलय तक कर सकती है। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को फूलन देवी की जयंती पर घर-घर 50 हजार प्रतिमाएं लगाने के अलावा कैलेंडर व लाखों लाकेट बांटे जाएंगे। फूलन के जरिये निषादों में पैठ की वीआइपी की कोशिश है।

## केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया शिव का जलाभिषेक

जासं, बुलंदशहर: रविवार को गांव अमरगढ़ में गंगा-जमुना तहजीब की अविरल धारा बहती दिखाई दी। यहां केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने गुरु के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने सावन माह में अमावस्या के अवसर पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर जलाभिषेक भी किया।

आरिफ मोहम्मद खान दो दिन से अपने पैतृक गांव मोहम्मदपुर बरवाला आए हुए हैं। रविवार को वह गांव अमरगढ़ पहुंचे। यहां अपने गुरु पूरण चंद शास्त्री से मिले। उनसे साठ वर्ष पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। इस मौके पर ग्राम प्रधान सहित अन्य लोगों ने राज्यपाल का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल ने अपने मित्र नरेश शर्मा के घर पहुंचकर उनके बच्चों से हालचाल जाना। राज्यपाल ने अन्य लोगों से भी मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी।

**10,000** करोड़ रुपये तक निर्यात को पहुंचाने की दिशा में काम कर हैंडलूम उद्योग। वर्तमान में निर्यात महज 2,500 करोड़ रुपये का है। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किया आह्वान।



## प्रो. एसके मेहता लद्दाख विवि के नए कुलपति

राज्य ब्यूरो, जम्मू : विख्यात वैज्ञानिक प्रो. एसके मेहता को लद्दाख विश्वविद्यालय का नया कुलपति (वाइस चांसलर) बनाया गया है। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने प्रो. मेहता को कुलपति नियुक्ति पर अपनी मुहर लगा दी है।

प्रो. मेहता राष्ट्रीय सोसायटी आफ केमिस्ट्री के फैलो हैं और केमिस्ट्री विभाग के चेयरमैन रहे हैं। चंडीगढ़ रीजन इनोवेशन नालेज क्लस्टर के समन्वयक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ग्लोबल इनीशिएटिव आफ अकेडमिक नेटवर्क (ज्ञान) के स्थानीय समन्वयक और यूजीसी की करियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के समन्वयक रहने के दौरान प्रो. मेहता ने बेहतरीन कार्य किया है। अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके 360 लेख प्रकाशित हो चुके हैं। वह 15 पुस्तकें लिख चुके हैं।

## कागजों में उग रहे दावों के पौधे... घट रहा वन घनत्व

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

सरकारी स्तर पर हरित क्षेत्र बढ़ाने के दावे भले कितने ही किए जाते हों, लेकिन बहुत बार पौधारोपण कागजों में ही कर दिया जाता है। शायद इसीलिए झारखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन घनत्व घट रहा है। इसी वजह से इन राज्यों के वन क्षेत्र में कार्बन सोखने की क्षमता भी घट रही है। हालांकि दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर एवं हिमाचल में कार्बन सोखने की क्षमता में पहले के मुकाबले इजाफा दर्ज किया गया है।

यह जानकारी सामने आई है सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) की हालिया रिपोर्ट 'स्टेट आफ इंडियाज एन्वायरमेंट 2021 : इन फिगर' से। यह रिपोर्ट बताती है कि भारतीय वन लकड़ी एवं गैर लकड़ी वन उत्पाद के रूप में पारिस्थितिक सेवाएं देते हैं। कई बड़े राज्यों में ये सेवाएं घट रही हैं जो इस बात का प्रमाण है कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। वर्ष 2015-16 के मुकाबले वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 में यह कमी देखने को मिली है।

### ऐसे होती है इनकी माप

वन पारिस्थितिक सेवाओं में मुख्यतः तीन तत्व होते हैं

**लकड़ी :** इसे वनों से प्राप्त लकड़ी जैसी पारिस्थितिक संपत्ति से जोड़ा जाता है।

**गैर लकड़ी वन उत्पाद :** भोजन में प्रयोग होने वाले पौधे, पेय पदार्थ, चारा, ईंधन, दवाएं, फाइबर व जैव रसायन, शहद, रेशम इत्यादि।

**कार्बन रिटेंशन :** इससे अभिप्राय कार्बन को सोखकर उसके बदले दी जाने वाली स्वच्छ वायु से है।

- सीएसई की ताजा रिपोर्ट में झारखंड, पंजाब, हरियाणा, मप्र, छत्तीसगढ़ व उप्र समेत 14 राज्यों को लेकर जताई गई चिंता
- दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर एवं हिमाचल में कार्बन सोखने की क्षमता में पिछले साल के मुकाबले हुआ इजाफा

जंगलों पर संकट। फाइल फोटो

इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर सरकारी नीतियों की खामियां जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारों को अपनी नीतियों और कार्यशैली दोनों में सुधार करना चाहिए। कार्बन रिटेंशन पर खासतौर से ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ हरित क्षेत्र बढ़ाने के बजाय वन क्षेत्र का घनत्व भी बढ़ाया जाना जरूरी है। यह रिपोर्ट एक आइने की तरह है, जिसे आधार बनाकर भविष्य की कारगर नीतियां बनानी चाहिए। -सुनीता नारायण, महानिदेशक, सीएसई

**तीनों श्रेणियों में प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति (फीसद में)**

| राज्य | लकड़ी | वन उत्पाद | कार्बन रिटेंशन |
|---|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | 48 | 34 | 52 |
| छत्तीसगढ़ | 42 | 16 | 9 |
| राजस्थान | 34 | 30 | 28 |
| बंगाल | 31 | 34 | 4 |
| पंजाब | 31 | 38 | 12 |
| दिल्ली | 31 | 37 | 38 |
| बिहार | 31 | 25 | 06 |
| मध्य प्रदेश | 29 | 29 | 10 |
| उत्तर प्रदेश | 25 | 34 | 2 |
| झारखंड | 25 | 45 | 15 |
| उत्तराखंड | 24 | 40 | 38 |
| हरियाणा | 19 | 92 | 11 |
| जम्मू कश्मीर | 30 | 30 | 50 |

## बच्ची एक, मां दो! जननी और पालने वाली में फंसा पेंच

नितिन धीमान, अमृतसर : अमृतसर की नवीं आबादी क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के घर तीसरी बेटी की किलकारियां गूंजीं। परिवार ने इसे हंसी-खुशी स्वीकार किया। तीन बच्चियों को पालने में परेशानी बताकर पड़ोस की महिला ने हमदर्दी दिखाई कि एक माह तक वह नवजात की देखभाल कर सकती है। परिवार ने उसे बच्ची सौंप भी दी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसका मन बदल गया। अब वह बच्ची को लौटाने के लिए तैयार नहीं है। कह रही है कि परिवार ने मौखिक तौर पर बच्ची गोद दी थी। पुलिस भी पशोपेश में है कि आखिर क्या करे।

रतन सिंह चौक स्थित नवीं आबादी की रहने वाली बेबी ने बच्ची को जन्म दिया। उसके अनुसार, जान पहचान की महिला तानिया की संतान नहीं है। तानिया ने कहा कि तुम्हारी दोनों बेटियां अभी छोटी हैं, इसलिए तीसरी बच्ची की परवरिश करना मुश्किल होगा। एक महीने तक हम बच्ची को अपने पास रख सकते हैं। इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी और बच्ची की परवरिश भी। बेबी ने सोचा कि वह ठीक कह रही है और पति की सहमति से बच्ची को तानिया के हवाले कर दिया। करीब दस दिन बाद जब वह तानिया के घर बच्ची से मिलने गई तो उसने उन्हें बाहर से ही लौटा दिया। बाद में पति को लेकर पहुंची तो तानिया ने बच्ची देने से ही इन्कार कर दिया। उसने परवरिश करने की एवज में 35000 रुपये की मांग की।

**तानिया ने कहा, मौखिक तौर पर गोद दी थी बच्ची :** रविवार को पुलिस तानिया के घर पहुंची तो उसने बच्ची देने से इन्कार करते हुए कहा कि बेबी ने उसे बच्ची मौखिक तौर पर गोद दी थी। एक माह तक बच्ची को अपने सीने से लगाकर रखा है। मां से बढ़कर परवरिश की है। मुझे इससे बेहद लगाव हो गया है और मैं एक पल भी इसके बगैर जीवित नहीं रह सकती। बेबी झूठा आरोप लगा रही है कि उसने 35000 की मांग की है। सच तो यह है कि बेबी का परिवार मुझे धमका रहा है।

**पेचीदा हुआ मामला, पुलिस भी हैरान :** जांच अधिकारी एएसआइ गुरजीत सिंह के अनुसार यह अपनी तरह का अलग मामला है। आखिर बच्ची किसके हवाले की जाए। फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। कानून के तहत हर पहलुओं की जांच कर ही इस मामले में कोई कार्रवाई की जाएगी।

# उप्र-बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर

**आफत** ▶ संगमनगरी में चल रहीं नावें, पूर्वांचल में भी भयावह हालात

### मुंगेर में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, कई गांवों में फैला पानी

जागरण टीम, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश और बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उप्र में नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। बाढ़ के पानी से घिरे गांवों में लोग भवनों की छत पर शरण लिए हुए हैं। सैलाब में सड़कें गुम हो चुकी हैं। आलम यह है कि चित्रकूट और प्रयागराज में नावों से आवाजाही हो रही है। बिहार में भी बारिश की वजह से नदियों में उफान देखा जा रहा है। गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंगा, कोसी समेत पहाड़ी नदियों में पानी लबालब है। गंगा समेत अन्य नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

उप्र के बांदा में केन व यमुना नदी उफनाने से पैलानी तहसील क्षेत्र के दो दर्जन से ज्यादा गांव पानी से घिर गए हैं। यमुना नदी में बाढ़ के कारण फतेहपुर जिले के ललौली में सड़क पर दो फीट ऊपर तक पानी आने से कानपुर-बांदा मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा का जलस्तर पांच सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। इटावा में चंबल का जलस्तर फिर बढ़ना शुरू हो गया है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर रविवार शाम खतरे का निशान पार कर गया। जलस्तर बढ़ते ही तटवर्ती इलाकों में हालात गंभीर हो गए। यमुना भी बढ़ रही है। हालांकि अभी जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा नीचे है। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ, जल पुलिस और पीएसी मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डा. महेंद्र सिंह ने रविवार को बलिया व बनारस तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। इससे पहले बलिया कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राहत-बचाव कार्य की तैयारियां परखीं।

प्रयागराज के दारागंज क्षेत्र में छोटा बघाड़ा के पास एनडीआरएफ की टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करते जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री। जागरण

**खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक उफान पर :** बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान 39.33 मीटर से महज 42 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। यदि बढ़ने की यही रफ्तार रही तो अगले 48 घंटों में यहां गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक उफान पर है। यहां गंगा खतरे के निशान से 0.96 सेमी ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 19 सेमी की वृद्धि हुई है। बूढ़ी गंडक के जलस्तर में पिछले 24 घंटों के दौरान 54 सेमी की वृद्धि हुई है। कटिहार में भी गंगा और कोसी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। महानंदा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर है।

## धनबाद में सीबीआइ टीम ने दोबारा रीक्रिएट किया सीन

जासं, धनबाद : धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) उत्तम आनंद की हत्या मामले में सीबीआइ टीम तेजी से जांच में जुटी है। रविवार सुबह टीम ने घटनास्थल पर दोबारा सीन रिक्रिएट किया। इस बार दोनों आरोपितों को भी मौके पर लाया गया। उनसे कई सवाल भी टीम के अधिकारियों ने पूछे। टेंपो चालक और उसके सहयोगी को सीबीआइ ने पूछताछ के लिए पांच दिनों की रिमांड पर लिया है।

सीबीआइ की टीम रणधीर वर्मा चौक पर जज को धक्का मारने वाले आटो और आरोपितों को साथ लेकर पहुंची थी। साथ में फोरेंसिक विशेषज्ञ भी थे। सीन रीक्रिशन उसी वक्त (सुबह पांच बजकर आठ मिनट) किया गया, जिस वक्त सैर कर रहे न्यायाधीश को धक्का मारा गया था। पहले मिनी ट्रक से आटो को सड़क पर उतारा गया। फिर धक्का मारने की घटना दोहराई गई। आरोपित आटो चालक लखन वर्मा से ही आटो चलवाया गया और उसके साथी राहुल वर्मा को वैसे ही बगल में बिठाया गया, जैसा घटना के दिन हुआ था। लखन वर्मा ने आटो चलाया और धक्का मारने का सीन दोहराया।

वह भी पता करने का प्रयास किया गया कि आखिर जज की मौत कैसे हुई। थ्री डी लेजर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आटो की गति, सड़क पर उसके मुड़ाव, सड़क की स्थिति, रफ्तार, आटो चलाने वाले की ड्राइविंग हैबिट आदि बिंदुओं पर जांच की गई। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 28 जुलाई की सुबह सैर करने निकले धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को आटो चालक ने सड़क खाली होने के बावजूद तेजी से उनकी तरफ जाकर धक्का मारा था।

## सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन और पर केस चलाने का आदेश

- सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की ओर से दाखिल याचिका पर दिया फैसला
- निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किया रद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में एफआइआर में नाम होने और पीड़िता द्वारा कोर्ट में दिए गए बयान में नाम लिए जाने के बावजूद तीन लोगों को अभियुक्त बनाकर समन करने से इन्कार करने का निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला रद कर दिया है। शीर्ष अदालत ने तीन अन्य को भी अभियुक्त बनाकर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और संजीव खन्ना की पीठ ने पीड़िता की याचिका पर सुनाया है। इस तरह इस मामले में अब कुल छह लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा।

यह मामला अलीगढ़ का है, जिसमें पीड़िता दिव्यांग है। शिकायत में छह लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था और छह लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई थी। लेकिन पुलिस ने दो हिस्सों में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सिर्फ तीन लोगों को ही अभियुक्त बनाया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में अर्जी देकर तीन अन्य लोगों विनीत, मदना और तरन को भी अभियुक्त बनाकर समन करने की मांग की। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई। लेकिन हाई कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी। इसके बाद पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इन तीनों को भी अभियुक्त बनाकर मुकदमा चलाए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 2016 से लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने गत 29 जुलाई को फैसला सुनाया है।

पीड़िता की ओर से पेश वकील डीके गर्ग ने बहस के दौरान कहा कि पीड़िता न्याय पाने के लिए अदालत दर अदालत भटक रही है। सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना नवंबर 2014 की है। पीड़िता की नाबालिग बहन घटना की चश्मदीद गवाह है। एफआइआर में छह लोगों के नाम थे। पीड़िता व अन्य ने अदालत में दिए बयान में भी सबका नाम लिया था। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने बाकी तीन को अभियुक्त बनाकर मुकदमा चलाने की मांग खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में आइपीसी की धारा 376डी (सामूहिक दुष्कर्म), 147, 323, 336 के तहत अलीगढ़ के पिसवा थाने में मामला दर्ज हुआ था। एफआइआर में सभी का नाम था। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज कराए बयान में भी इन तीनों का नाम लिया था। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इन तीनों को अभियुक्त बनाने की अभियोजन पक्ष की अर्जी खारिज कर दी और हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के दौरान किसी पक्ष का हित प्रभावित न हो, इसलिए वह केस का ज्यादा विवरण देने से परहेज कर रहा है, लेकिन इतना पर्याप्त होगा कि एफआइआर में तीनों के नाम थे और जांच व कोर्ट में अभियोजन पक्ष के गवाहों ने इनके नाम लिए हैं। ट्रायल कोर्ट ने विनीत, मदना और तरन को समन किए जाने की अर्जी खारिज करके गलती की है।

## हेलीकाप्टर की तलाश में मछुआरों की मदद

जागरण संवाददाता, पठानकोट : रणजीत सागर झील (आरएसडी) में गत मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए सेना के ध्रुव हेलीकाप्टर एएलएच मार्क-चार के पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल एस बाठ व सह-पायलट कैप्टन जयंत जोशी का रविवार को भी कोई सुराग नहीं मिल पाया।

हादसे के एक प्रत्यक्षदर्शी अवतार सिंह ने दावा किया है कि हेलीकाप्टर घरों से करीब 150 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था और फिर अचानक झील में समा गया। उन्होंने कहा कि अगर मछुआरों की मदद ली जाए तो जल्द कामयाबी मिल सकती है। उन्हें झील की सारी जानकारी है। करीब तीन साल पहले एक बोट झील में डूब गई थी, जिसे स्थानीय लोगों ने बड़ी आसानी से निकाल लिया था।

**झील में जमा गाद बनी बनी बाधा :** हेलीकाप्टर को तलाशने के अभियान में तलहटी में जमी गाद बाधा बन रही है। गाद कितनी गहरी है इसका पता नहीं चल पा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों पायलट एवं को-पायलट के शव क्रैश हुए हेलीकाप्टर में ही हो सकते हैं। रणजीत सागर झील में हुए हादसे में तमाम प्रयास के बाद कोई नतीजा नहीं मिल रहा है।

## बंगाल की युवती से दरिंदगी के मामले में आरोप-पत्र दाखिल

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ (झज्जर)

कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ धरने में शामिल होने आई बंगाल की युवती के साथ टीकरी बार्डर पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने जिला अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। 139 पेज के इस आरोप पत्र में पुलिस ने दो महिला आरोपितों को गवाहों की सूची में रखा है। दोनों से पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली थी। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को आरोपित माना है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है। तीन अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। एक आरोपित अनिल मलिक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पर भी आरोप पत्र जल्द दाखिल करने का दबाव बढ़ गया था।

बंगाल से आंदोलन में आई युवती की 30 अप्रैल को मौत हो गई थी। उसके पिता की शिकायत पर बहादुरगढ़ के शहर थाने में आठ मई को केस दर्ज किया गया था। किसान सोशल आर्मी के चार कार्यकर्ताओं अनिल मलिक, अनूप चनौत, अंकुर सांगवान और जगदीश बराड़ के अलावा दो महिला वालंटियर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जांच के लिए डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में गठित एसआइटी केवल अनिल को गिरफ्तार कर पाई। अनूप, अंकुर और जगदीश फरार हैं। अनूप व अंकुर की अग्रिम जमानत याचिका जिला अदालत के बाद हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। पुलिस ने अंकुर व अनूप की गिरफ्तारी पर तो 25-25 हजार का इनाम भी रख हुआ है। जांच के दौरान नामजद की गई योगिता सुहाग और कविता आर्य समेत 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई। एसआइटी दावा कर चुकी है कि बंगाल की युवती के साथ अनिल व अनूप ने दुष्कर्म किया। अंकुर ने छेड़छाड़ की और जगदीश बराड़ ने चुप रहने के लिए दबाव बनाया।

पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। दो महिला आरोपितों की इस मामले में कोई भी आपराधिक भूमिका नहीं मिली। दोनों इस घटना के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। इसलिए उन्हें गवाहों की सूची में रखा गया है। -विजय कुमार, एसएचओ, शहर थाना बहादुरगढ़

## मामूली चोरी के आरोप में डेढ़ साल घर में कैद रहा आदिवासी परिवार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के बीरभूम के शांतिनिकेतन में मामूली चोरी के आरोप में गांव के मुखिया के निर्देश पर एक आदिवासी परिवार को डेढ़ साल घर में कैद रहकर नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ा। इतना ही नहीं मुखिया ने पीड़ित परिवार से गांव के किसी भी सदस्य के बातचीत करने पर 10 हजार का जुर्माना लगाने का फरमान भी दे रखा था। इस भय से पूरे गांव ने पीड़ित परिवार से संपर्क तोड़ रखा था। शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और जांच शुरू हुई।

जानकारी के मुताबिक, घटना नवंबर, 2019 में शांतिनिकेतन के बालीपाड़ा गांव की है। सुकोल हेम्ब्रम नाम के एक पुजारी ने कालिदास चोड़ और उनके एक रिश्तेदार छोटन पर स्कूल की चाबियां चुराने का आरोप लगाया था। उन्होंने मामले की जानकारी गांव के प्रधान सुनील हांसदा को दी। गांव में सालिसी सभा (खाप पंचायत) बुलाई गई। प्रधान ने आठ सदस्यों के परिवार को घर में कैद रहने का अमानवीय निर्देश दिया। सिर्फ गांव के भीतर भोजन का जुगाड़ करने की सुविधा दी गई।

## 12वीं के छात्र आज से दे सकेंगे आपत्तियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

12वीं कक्षा के छात्रों की आपत्तियों का निपटारा करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। सोमवार नौ अगस्त से शुरू होकर यह प्रक्रिया चार चरणों में 12 अगस्त तक पूरी होगी। 14 अगस्त तक शिकायतों का निपटारा कर दिया जाएगा।

**इस तरह होगा आवेदन :** अंकों से असंतुष्ट छात्रों को अपने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पत्र के माध्यम से आपत्तियां बतानी होंगी। स्कूल इस रिकार्ड को आनलाइन व आफलाइन दोनों तरीके से अपने पास रखेंगे। संबंधित समिति आपत्तियों के आधार पर परिणाम की जांच करेगी। यदि परिणाम सही पाया जाता है और आपत्ति का कोई कारण नहीं निकलता है तो छात्र को समिति की ओर से जवाब भेज दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का रिकार्ड स्कूलों को भी अपने पास रखना होगा। बोर्ड ने इस पूरी प्रक्रिया को टाइप-एक श्रेणी में रखा है।

**परिणाम में त्रुटि होने पर क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी देखेंगे :** यदि छात्रों के मूल्यांकन में कोई गलती पाई जाती है तो परिणाम समिति की ओर से सभी दस्तावेज के साथ गलती होने व इसके प्रभाव को लेकर स्कूलों को सूचित किया जाएगा। स्कूल के प्रधानाचार्य व परिणाम समिति के अध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में सूचना दी जाएगी, जिसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी जरूरी सुधार करेगा। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से इस तरह के सभी मामलों को मुख्यालय में भी रिपोर्ट देनी होगी। स्कूलों की ओर से क्षेत्रीय कार्यालयों में स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फार रिसोल्यूशन (एसआरएसआर) के माध्यम से आवेदन भेजा जाएगा। इसके लिए स्कूल लाग-इन करने पर लिंक से आवेदन भेज सकेंगे। आवेदन करते समय स्कूलों को टाइप दो पर क्लिक करना होगा।

**गलत अंकों को लेकर स्कूल कर सकेंगे आवेदन :** यदि छात्रों का गलत अंकों को लेकर विवाद है तो स्कूल की ओर से लाग-इन कर लिंक से टाइप तीन पर क्लिक कर आवेदन करना होगा। इसके तहत अंकों की गलत गणना व परिणाम अपलोड करने में हुई त्रुटि की जांच की जाएगी। इसकी जांच के लिए सीबीएसई के सहायक सचिव, केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य, निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य व शिक्षा निदेशक स्तर तक के अधिकारी जांच समिति में शामिल होंगे। समिति अपनी जांच पूरी कर क्षेत्रीय कार्यालयों को रिपोर्ट सौंपेगी। जांच करने पर यदि परिणाम में कोई गलती नहीं पाई जाती है तो क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से छात्रों को जानकारी दी जाएगी। वहीं, यदि परिणाम में कोई गलती है तो क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सुधार किया जाएगा।

**12** अगस्त तक पूरी हो जाएगी मानक संचालन प्रक्रिया

### ये छात्र कर सकते हैं दावा

- जो अंकों से संतुष्ट नहीं हैं
- अंक गणना में गलती हुई है
- नई मूल्यांकन नीति को लेकर आपत्ति हो

### इस तरह होगा निपटारा

नई मूल्यांकन नीति से आपत्ति है तो इसके लिए स्कूलों की ओर से टाइप चार पर क्लिक कर आवेदन करना होगा। आपत्ति को लेकर पूरा विवरण देना अनिवार्य है। विवाद को संयुक्त सचिव, उप सचिव व सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य की अध्यक्षता वाले बोर्ड में रखा जाएगा।

**गौरव**

पहली बार जरनल ड्यूटी में शामिल की गईं महिला अधिकारी, मसूरी स्थित आइटीबीपी अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद मुख्य धारा में शामिल हुए 53 अफसर

# सरहद पर पहली बार आइटीबीपी की कमान संभालेंगी दो महिला अफसर

जागरण संवाददाता, मसूरी

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) में अब महिला अधिकारी भी जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरहद पर दुश्मन को सबक सिखाएंगी। पहली बार आइटीबीपी के इतिहास में दो महिला अधिकारियों को जनरल ड्यूटी (जीडी) में शामिल किया गया है। रविवार को मसूरी में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आइटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल ने इन दोनों अफसरों के कंधों पर सितारे सजाए। कुल 53 अधिकारी आइटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हुए।

आइटीबीपी में महिला कांस्टेबल की भर्ती वर्ष 2009-10 में शुरू की गयी थी। बल के जनसंपर्क अधिकारी विवेक कुमार पांडे ने बताया कि इसके बाद वर्ष 2013-14 में महिला उपनिरीक्षकों को शामिल किया गया और अब सहायक सेनानी जीडी (जनरल ड्यूटी) के तौर पर दो महिला अधिकारी प्रकृति राय और दीक्षा आइटीबीपी की मुख्य धारा में आई हैं। प्रकृति बिहार के समस्तीपुर और दीक्षा उत्तर प्रदेश के इटावा की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि नए प्रविधानों के अनुसार, बल में महिलाओं की तादाद 15 फीसद रहेगी।

मसूरी स्थित आइटीबीपी अकादमी से रविवार को पासआउट हुईं सहायक सेनानी प्रकृति राय।

एक साल का प्रशिक्षण पूरा कर पासआउट हुईं सहायक सेनानी दीक्षा। जागरण

रविवार को मसूरी स्थित आइटीबीपी अकादमी में एक साल का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 42 अधिकारी बतौर सहायक सेनानी (जीडी) मुख्य धारा में शामिल हो गए। वहीं, छह माह के प्रशिक्षण के बाद 11 सहायक सेनानी बतौर इंजीनियर तैनात होंगे। मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आइटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल ने परेड की सलामी ली। समारोह में सहायक सेनानी (जीडी) जोसी ए दिलीप को गृहमंत्री स्वार्ड आफ आनर प्रदान किया गया।

## परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहीं बेटियां

जागरण संवाददाता, मसूरी

महिलाएं अब हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी इच्छाशक्ति का लोहा मनवा रही हैं। इन्हीं में से एक हैं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) सहायक सेनानी (जीडी) दीक्षा और प्रकृति राय। अब तक आइटीबीपी में महिला अधिकारी चिकित्सा शाखा या भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर शीर्ष पदों पर तैनात हैं। यह पहली बार है जब ये दो महिला अधिकारी सीधे आइटीबीपी में कमीशंड हुई हैं। उन्हें अब कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात किया जाएगा। ये दोनों बेटियां परिवार की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं।

**पिता को देख आया वर्दी पहनने का जुनून :** एक पिता के लिए इससे ज्यादा गर्व का पल और क्या हो सकता है कि उनकी बेटी उनके सामने उन्हीं के विभाग की अधिकारी बन जाए। ऐसा ही एक भावुक पल उस समय आया जब इटावा (उत्तर प्रदेश) निवासी दीक्षा मसूरी स्थित आइटीबीपी अकादमी से बतौर सहायक सेनानी पास आउट हुईं। उनके पिता कमलेश कुमार भी आइटीबीपी में इंस्पेक्टर हैं। वर्तमान में वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तैनात हैं। जैसे ही दीक्षा अकादमी से पास हुईं पिता कमलेश कुमार ने उन्हें सैल्यूट किया। दीक्षा ने पीछे जिले के श्रीनगर स्थित एनआइटी से बीटेक किया था। इसके बाद वह निजी कंपनी में दो साल नौकरी करती रहीं, लेकिन मन में पिता की ही तरह वर्दी पहनने की ललक थी। आइटीबीपी में महिला अधिकारियों की नियुक्ति शुरू हुई तो उन्होंने नौकरी छोड़ संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा के जरिये आइटीबीपी में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार उन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया है।

## अलवदर के तीन आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट पेश

जागरण संवाददाता, जम्मू : पुलवामा आतंकी हमले (14 फरवरी, 2019) की दूसरी बरसी पर जम्मू शहर को आइईडी से दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकी संगठन अलवदर के तीन आतंकियों के खिलाफ जम्मू पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है। तीनों आतंकियों सुहेल बशीर शाह, अब्दुल्ला शकील खान और राहिल हुसैन भट्ट को जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीनों मौजूदा समय में कोट भलवाल जेल में बंद हैं।

अदालत में दायर चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि अलवदर ने इन तीनों आतंकियों को जम्मू शहर में तीन से चार स्थानों पर आइईडी धमाका करने का जिम्मा सौंपा था। इसके बाद यह तीनों कश्मीर से आइईडी लेकर जम्मू आए थे। इसके के दिन गत 14 फरवरी को जम्मू बस स्टैंड पुलिस ने इंदिरा चौक इलाके में नाका लगाया हुआ था। वहीं पर संदिग्ध हालत में घूमते सुहेल को हिरासत में ले लिया गया।

# बढ़ोतरी के बाद पांच हजार से ज्यादा घटे सक्रिय मामले

**राहत** ▶ पिछले 24 घंटे के दौरान 39 हजार से अधिक नए केस मिले

## केरल में कम नहीं हो रहे मामले, फिर आधे से ज्यादा केस वहीं से मिले

जेएनएन, नई दिल्ली

कोरोना के सक्रिय मामलों में कई दिनों की बढ़ोतरी के बाद गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में पांच हजार से ज्यादा सक्रिय मामले कम हुए हैं। इस दौरान 39 हजार नए केस मिले हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब 40 हजार से कम नए मामले पाए गए हैं। प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या पांच सौ से नीचे आई है। केरल की स्थिति में सुधार नहीं है। नजर आ रहा। नए मामलों में से आधे से ज्यादा केरल से ही हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय मामले चार लाख छह हजार पर आ गए हैं। एक दिन में सक्रिय मामलों में 5,331 की कमी आई है। मृत्युदर में कोई बदलाव नहीं हुआ है और दैनिक एवं साप्ताहिक संक्रमण दर भी तीन फीसद के नीचे ही बने हुए हैं। केरल में 20 हजार से ज्यादा मामले पाए गए हैं। सबसे ज्यादा 139 मौतें भी वहीं हुई हैं।

### केंद्र ने राज्यों को अब तक 52 करोड़ से ज्यादा डोज मुहैया कराईं

मंत्रालय ने बताया कि केंद्र की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की 52 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा जल्द ही इन्हें 8,99,260 डोज और मुहैया करा दी जाएंगी।

| रविवार सुबह 08 बजे तक कोरोना की स्थिति | |
|---|---|
| नए मामले | 39,070 |
| कुल मामले | 3,19,34,455 |
| सक्रिय मामले | 4,06,822 |
| मौतें (24 घंटे में) | 491 |
| कुल मौतें | 4,27,862 |
| ठीक होने की दर | 97.39 फीसद |
| मृत्यु दर | 1.34 फीसद |
| पाजिटिविटी दर | 2.27 फीसद |
| सा. पाजिटिविटी दर | 2.38 फीसद |
| जांचें (शनि.) | 17,22,221 |
| कुल जांचें (शनि.) | 48,00,39,185 |

| देश में कोरोना की स्थिति | |
|---|---|
| 24 घंटे में नए मामले | 39,070 |
| कुल सक्रिय मामले | 4,06,822 |
| 24 घंटे में टीकाकरण | 55.91 लाख |
| कुल टीकाकरण | 50.68 करोड़ |

### अब वाट्सएप पर पाएं कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट

नई दिल्ली, प्रेट्र : आपने कोरोना का टीका लगवा लिया है तो आप कुछ ही सेकेंड में इसका सर्टिफिकेट वाट्सएप पर पा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के कार्यालय ने यह जानकारी दी। वर्तमान में लोगों को टीकाकरण प्रमाण पत्र कोविन पोर्टल पर लाग-इन कर डाउनलोड करना होता है। मांडविया के कार्यालय ने ट्वीट किया, 'प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर आम आदमी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा रहा है। अब कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र तीन आसान चरणों में 'माईगोव कोरोना हेल्पडेस्क' से प्राप्त करें। संपर्क नंबर +91 9013151515 को सेव करें। व्हाट्सएप पर 'कोविड सर्टिफिकेट' टाइप कर भेजें। ओटीपी डालें। अपना प्रमाण पत्र कुछ सेकेंड के अंदर हासिल करें।'

## महामारी से आजादी

# जान जोखिम में डाल लगा रहीं जिंदगी का टीका

उत्तराखंड में जंगल व नालों को पार कर स्वास्थ्यकर्मियों की टीमें चला रहीं टीकाकरण अभियान

**जागरण विशेष**

शैलेंद्र गोदियाल ● उत्तरकाशी

कोरोना महामारी से बचाव में टीका बेहद अहम माना जा रहा है। पर्वतीय इलाकों के दुर्गम गांवों में टीकाकरण करना आसान नहीं है। श्वेता राणा और सोनम रावत जैसी स्वास्थ्यकर्मी जान जोखिम में डाल लोगों को टीका लगा रही हैं। कहीं जंगली जानवरों का डर है तो कहीं भूस्खलन में फंसने का, लेकिन इनके उत्साह में कमी नहीं है।

**खड़ी चढ़ाई और खतरनाक रास्ते:** चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 15 गांव ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए आठ से 15 किमी की खड़ी चढ़ाई तय करनी पड़ती है। स्वास्थ्य कर्मी उफनाते नदी-नालों, जंगल-झाड़ियों और विकट पगडंडियों से होकर गांवों तक पहुंच रहे हैं। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 225 किमी दूर ओसला गांव जाने के लिए तालुका से 18 किमी की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। आग्जिलरी नर्स मिडवाइफरी (एएनएम) श्वेता राणा टीकाकरण के लिए दो बार तालुका जा चुकी हैं।

श्वेता टीम के साथ बीती छह जुलाई को सुबह सात बजे रवाना हुई। तालुका से एक किमी पहले भूस्खलन से सड़क बंद थी। सो, टीम ने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे-तैसे रास्ता पार किया। ओसला के पैदल मार्ग पर जिया गदेरा (पहाड़ी नाला) उफान पर था। लकड़ी की पुलिया से होते हुए टीम आगे बढ़ी।

**बिस्कुट-पानी से कटा दिन:** श्वेता बताती हैं कि बारिश में जंगल से होते हुए रात आठ बजे उनकी टीम ओसला पहुंची। दिन बिस्कुट-पानी के सहारे गुजरा। आइस पैक व 2,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ओसला में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होने से वैक्सीन सुरक्षित रही।

**ग्रामीणों को समझाना भी चुनौती:** वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीणों को राजी भी करना था। समझाने पर लगभग सौ ग्रामीणों ने वैक्सीन लगवाई। ढाटमीर गांव में लोग वैक्सीन के लिए राजी नहीं हुए। फार्मेसिस्ट वासुदेव राणा कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारी और कुछ लोगों को तालुका बुलाकर टीका लगाया। तालुका से 14 किमी की पैदल दूरी पर स्थित पंवाणी गांव में टीकाकरण करने वाली एएनएम संगीता रावत और एक अन्य गांव जाने वाली एएनएम सोनम रावत को भी ऐसी ही चुनौतियों से जूझना पड़ा।

**भालू के हमले का भी है खतरा:** मोरी तहसील के कलाप, पासा व पोखरी गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं। आठ-दस किमी पैदल चलना पड़ता है। एएनएम सीता चौहान कहती हैं कि जंगल के बीच से जाना पड़ता है। रुद्राला से पोखरी-पासा जाते हुए कुछ दिन पहले उन्हें जंगल में भालू भी दिखा। यह रास्ता खतरे से खाली नहीं है। अधिकांश ग्रामीण छानी (गांव से दूर पारंपरिक घर, जहां मवेशी भी साथ रहते हैं) या सेब के बागीचों में रहते हैं।

कोरोना टीकाकरण के लिए उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती गांव ओसला के रास्ते में भूस्खलन जोन से गुजरती स्वास्थ्य विभाग की टीम ● सौ: श्वेता राणा

### तीन साल की बेटी से दूर हैं श्वेता

ओसला गांव में टीकाकरण करने वाली एएनएम श्वेता राणा कहती हैं कि नवंबर 2020 से वह अपनी तीन साल की बेटी से दूर हैं। बेटी दादी व पिता के साथ गंगोत्री धाम के पास सुक्की गांव में रहती है।

> टीमों को टीकाकरण के लिए ऐसे स्थानों पर भी जाना पड़ रहा है, जहां पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ते तक नहीं हैं। उम्मीद है कि स्वास्थ्य टीम के जज्बे से 15 अगस्त तक जिले में 90 फीसद ग्रामीणों को वैक्सीन की पहली डोज लग जाएगी।
>
> – मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

# स्कूल न खोलना भी उतना ही खतरनाक, जितना उन्हें खोलना

▶ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर हो रहा नकारात्मक असर

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए स्कूलों को न खोलना भी कमोबेश उतना ही खतरनाक है जितना कि उनको खोलना। स्कूलों के नहीं खुलने से न केवल परिवार के भीतर का वातावरण बिगड़ रहा है, बल्कि बच्चों की घरेलू कामकाज में भागीदारी भी बढ़ रही है। इसके चलते वे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। यह बात विनय पी सहस्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, युवा, बच्चों और खेल पर गठित संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल से ज्यादा समय से स्कूलों की बंदी ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाला है। बड़े बच्चों का घर की चारदीवारी के भीतर लगातार रहना माता-पिता के साथ उनके रिश्तों पर असर डाल रहा है। माता-पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि खासकर लड़कियों की कम उम्र में शादी हो रही है या उन पर घर के कामकाज की जिम्मेदारी बढ़ रही है। इससे लड़कियों की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट रही है या फिर वे पढ़ाई में कमजोर हो रही हैं। आमतौर पर ऐसा निम्न मध्यमवर्गीय और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में देखने को मिल रहा है। इसलिए स्कूलों को खोलने के लिए होने वाली चर्चा में इन स्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए।

**जीवन के लिए टीका**

कोरोना को लेकर देशभर में वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है। राजस्थान के बीकानेर स्थित एक सेंटर पर वैक्सीन लेने के लिए कतार में खड़े लोग। एएनआइ

# शरत और मल्लिका की कुर्की को आज अर्जी देगी एसआइटी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में एसआइटी की पकड़ से बाहर चल रहे शरत पंत व मल्लिका पंत पर कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है। एसआइटी सोमवार को पति-पत्नी की संपत्ति कुर्क करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी।

हरिद्वार कुंभ 2021 में श्रद्धालुओं की कोविड जांच में हुए फर्जीवाड़े में हरिद्वार शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसकी जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर गठित एसआइटी कर रही है। पिछले दिनों एसआइटी ने भिवानी हरियाणा की डेलफिया लैब के मालिक आशीष वशिष्ठ को गिरफ्तार किया था। आशीष वशिष्ठ ने पूछताछ के दौरान बताया था कि कुंभ में कोरोना टेस्टिंग का काम लेने वाली फर्म मैक्स कारपोरेट सर्विसेज के पार्टनर व पति-पत्नी शरत पंत और मल्लिका पंत के कहने पर ही हरियाणा हिसार की नलवा लैब से समझौता किया था।

पुलिस ने आशीष के पास से जानकारी मिलने के बाद शरत पंत और उनकी पत्नी मल्लिका पंत को मुकदमे में नामजद कर लिया है। इसके बाद से ही दोनों पकड़ से बाहर चल रहे हैं और एसआइटी उनकी तलाश कर रही है। एसआइटी अब उन पर कानूनी शिकंजा कसने जा रही है।

## राष्ट्रीय फलक

# अवैध मतांतरण पर रोक को बने केंद्रीय कानून : आलोक कुमार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अवैध मतांतरण राष्ट्रीय अभिशाप है, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। इसके रोक के लिए 11 राज्यों में कानून बने हैं, लेकिन समस्या और षड्यंत्र राष्ट्रव्यापी है। इसके लिए केंद्रीय कानून बनना चाहिए, तभी इस अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों व वर्तमान परिस्थितियों से भी स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र को इस बारे में विलंब नहीं करना चाहिए। हमने हिंदू समाज से भी आह्वान किया है कि समाज विरोधी ताकतों व हिंदू द्रोही षड्यंत्रों पर सजग रहें और रोक लगाएं। आलोक कुमार दो दिवसीय गोरक्ष प्रांत की बैठक के बाद हरिश्चंद्र मिश्र पब्लिक स्कूल में मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से कहा कि एक केंद्रीय कानून बनाकर मठ-मंदिरों एवं धार्मिक संस्थाओं को सरकार नियंत्रण से मुक्त कर हिंदू समाज को सौंपा जाए। यह भी बताया कि अयोध्या में राममंदिर का निर्माण 2024 में पूरा हो जाएगा। रामजी गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। आमजन दर्शन कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के एक सप्ताह पूर्व से बाद तक स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। इसमें कोरोना से रक्षा, अवैध मतांतरण पर रोक व मठ-मंदिरों की मुक्ति का संकल्प शामिल होगा। एक सवाल के जवाब में कहा, विहिप किसी भी सियासी दल का समर्थन नहीं करता है, किंतु हम उसे वोट देने को जरूर कहेंगे जो हिंदू समाज के लिए काम करेगा। समर्पण निधि में घोटाले के आरोप पर कहा कि अंसारी व पाठक के बीच जमीन खरीद का मामला था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत से मामला सुलझ चुका है। कोई घोटाला नहीं हुआ है। पुलिस की जांच का सामना करने को हम तैयार हैं। जनसंख्या कानून पर कहा कि एक नहीं, बल्कि दो बच्चों पर कानून होना चाहिए।

# मां जानकी की भूमि भी अयोध्या की तरह हो विकसित : विहिप

जासं, सीतामढ़ी : विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्म विभूषण डा. रविंद्र नारायण सिंह ने कहा कि माता जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम जानकी मंदिर भी अयोध्या की तरह विकसित हो। केंद्र सरकार देश के सभी मठ-मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए कानून बनाए। वह बिहार के सीतामढ़ी में आयोजित विहिप की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम जब सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा तब स्वतंत्र न्यास का गठन कर अयोध्या की तरह मंदिर को विकसित करने की पहल की जाएगी। उन्होंने जानकी जन्मभूमि को रामायण सर्किट से जोड़कर विकसित करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। विहिप अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी नियंत्रण से सभी मठ-मंदिरों को मुक्त कर उसकी आमदनी लोक कल्याणकारी उपक्रमों पर खर्च हो।

# तीन तलाक कानून बनने से शरई अदालत में कम हुए मुकदमे

मुस्लेमीन, रामपुर

तत्काल तीन तलाक की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने दो साल पहले कानून बनाया था। इसके बाद से तीन तलाक के मामलों में बहुत कमी आई है। उप्र के रामपुर की शरई अदालत में अब तत्काल तीन तलाक का कोई मामला नहीं है। केवल जायदाद बंटवारे के मुकदमे ही चल रहे हैं। तत्काल तीन तलाक से पीड़ित महिलाएं अब कानून का सहारा ले रही हैं। उन्हें अगर तीन तलाक दिया जाता है तो वे सीधे थाने पहुंचती हैं और रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। जिले के थानों में दो साल में डेढ़ सौ से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने भी इन मामलों को गंभीरता से लिया है। तेजी से कार्रवाई करते हुए मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की। गंभीर मामलों में आरोपितों को गिरफ्तार भी किया है।

**शरई अदालत में नहीं कोई मुकदमा :** रामपुर शहर में लंबे समय से शरई अदालत में मुसलमानों के आपसी मामले शरीयत के हिसाब से सुलझाए जाते हैं। इस अदालत में संपत्ति विवाद और बंटवारे के साथ ही तीन तलाक के मामले भी आते रहे हैं, लेकिन अब इस अदालत में तीन तलाक के मामले आने बंद हो गए हैं। पीड़ित महिलाएं अब शरई अदालत में फरियाद लेकर नहीं पहुंच रही हैं।

> तीन तलाक कानून बनने के बाद से केवल दो मामले शरई अदालत में आए हैं। पहले हर माह 10 से 15 मामले आते थे। अब जायदाद बंटवारे के मामले ज्यादा पहुंच रहे हैं। इस समय दस मामले बंटवारे के चल रहे हैं। शरई अदालत में मुकदमों का निस्तारण अधिकतम तीन माह में हो जाता है।
>
> –मुफ्ती मकसूद, नायब सदर, शरई अदालत, रामपुर

> मेरे पास कोई तलाक पीड़ित महिला आती है तो उसे इंसाफ दिलाने का प्रयास करते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराकर चार्जशीट भी शीघ्र लगवाते हैं।
>
> –शगुन गौतम, पुलिस अधीक्षक, रामपुर

**शंकराचार्य मंदिर में पहुंची छड़ी मुबारक**

दशनामी अखाड़ा के महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक विश्राम स्थल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शंकराचार्य मंदिर के लिए रवाना हुई। गिरि ही पवित्र छड़ी मुबारक के संरक्षक हैं। एएनआइ

# लिम्का बुक में दर्ज होगा सहरसा के लाल का नाम

जागरण संवाददाता, सहरसा : बिहार के सहरसा जिला निवासी व विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डा. आरएन सिंह के पुत्र डा.आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह सम्मान उन्हें उत्तर बिहार में रोबोटिक विधि से कूल्हे व घुटने का प्रत्यारोपण के लिए मिलेगा। वर्तमान में यह रिकार्ड मेदांता हास्पिटल, गुरुग्राम के चिकित्सक के नाम है, जिन्होंने एक दिन में तीन प्रत्यारोपण किए थे। प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डा. आरएन सिंह के पुत्र डा. आशीष ने शुक्रवार को सात लोगों के कूल्हे व घुटने का प्रत्यारोपण किया। चिकित्सा जगत की यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

इस संबंध में डा. आशीष का कहना है कि यह देश में दूसरा मेडिकल रोबोट है। साथ ही यह दुनिया का सबसे आधुनिकतम तकनीक है। दूसरे देशों में इसका प्रयोग विगत दस वर्षों से हो रहा है। अब हमारे देश और खासकर इलाके के गरीब तबके के लोगों के लिए घुटना और कूल्हा बदलना सपना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गरीब तबके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना मेरे पिताजी और मेरा संकल्प है।

# झारखंड में 60 साल में 10 प्रतिशत कम हो गई जनजातीय समुदाय की आबादी

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में आदिवासी जनजातीय समुदाय की आबादी में निरंतर आ रही गिरावट चिंता का विषय बनी हुई है। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 60 साल में आदिवासियों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत कम हो गई है। वहीं आदिम जनजाति समूह में आने वाली जातियों की आबादी में कई गुना ज्यादा गिरावट आई है।

झारखंड में 32 आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। इनमें बिरहोर, पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरबा, बिरजिया, असुर, सबर, खड़िया और बिरजिया कुल नौ आदिम जनजाति समूह हैं। आदिम जनजातियों की संख्या लगातार तेजी से घटने के कारण ये विलुप्तप्राय जनजातियों की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। ये अपने खास रहन-सहन की वजह से जाने जाते हैं और किसी भी कीमत पर अपनी परंपरा, संस्कृति और जीवन जीने के तरीके में बदलाव को तैयार नहीं होते। गरीबी और अशिक्षा के कारण ये विकास की धारा से जुड़ नहीं सके हैं। इनके संरक्षण को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इन्हें बचाने और विकास से जोड़ने के लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है।

**ये हैं वजहें :** इनकी घटती संख्या की मुख्य वजहों में गरीबी, कुपोषण, दुर्गम क्षेत्रों में इनका निवास, स्वास्थ्य के प्रति इनका सचेत नहीं होना और शुद्ध पानी का अभाव आदि कारण गिनाए जाते रहे हैं। वहीं कुछ समाजशास्त्री और चिकित्सक अपने सीमित समूह तक ही इनके विवाह करने को भी इनकी बढ़ती मृत्यु दर का एक कारण बनाते हैं। 1951 की जनगणना के मुताबिक एकीकृत बिहार में झारखंड के हिस्से में रहने वाले आदिवासियों की जनसंख्या कुल आबादी का 35.8 प्रतिशत थी। 1991 में यह 27.66 प्रतिशत, 2001 में 26.30 प्रतिशत और 2011 में घटकर 26.11 प्रतिशत हो गया। यानी 60 साल में आबादी में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई। आदिम जनजातियों की बात करें तो 2001 में झारखंड में इनकी संख्या जहां 3,87,000 थी, जबकि 2011 में इनकी आबादी घटकर 2,92,000 हो गई। अब एक बार फिर जनगणना की तैयारी चल रही है। इसके बाद इनकी वर्तमान समय में वास्तविक आबादी का पता चल सकेगा।

**यूं घटी आबादी**

| वर्ष | प्रतिशत |
|---|---|
| 1951 | 35.8 |
| 1991 | 27.66 |
| 2001 | 26.30 |
| 2011 | 26.11 |

> आदिवासियों की घटती जनसंख्या चिंता का विषय है। खासकर आदिम जनजातियों की संख्या में गिरावट आना और भी चिंता का विषय है। इन्हें बचाने के लिए गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। जागरूकता की कमी और इन समूहों में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की बुरी स्थिति को बदलने की जरूरत है। बिखरे-बिखरे रहने के कारण आदिम जनजातियों की सही-सही गणना भी नहीं हो सकी है।
>
> –डा. हरि उरांव, विभागाध्यक्ष, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विवि, रांची

# स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत विक्रांत ने पूरी की पहली समुद्री यात्रा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत में निर्मित पहले विमानवाहक युद्धपोत विक्रांत ने पांच दिवसीय प्रथम समुद्री यात्रा रविवार को पूरी कर ली। 40 हजार टन के इस जहाज की अहम प्रणालियों का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया।

23 हजार करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस जहाज को बुधवार को अहम समुद्री परीक्षण के लिए रवाना किया गया था। उम्मीद है कि अगले साल अगस्त तक इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, 'विक्रांत ने पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। हम परीक्षण योजना के अनुसार आगे बढ़े और प्रणाली के मानक संतोषजनक साबित हुए।' नौसेना की दक्षिणी कमान के कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल एके चावला ने अंतिम दिन जहाज के प्रदर्शन की समीक्षा की।

मधवाल ने कहा कि विक्रांत को भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ (आजादी का अमृत महोत्सव) के उपलक्ष्य में होने वाले समारोहों के साथ नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा जा रहा है।

## श्रद्धा का महासावन

# शिवाभिषेक संग धराभिषेक

हिंदू कैलेंडर के चार सबसे पवित्र महीनों में चातुर्मास का पहला और सबसे शुभ, पवित्र, श्रेष्ठ एवं विशिष्ट महीना है श्रावण। श्रद्धालु व्रत, शिवाभिषेक, शाकाहारी भोजन के माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास, सद्भाव, आनंद व भगवान शिव की दिव्यता, सकारात्मकता और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पूरे माह साधना करते हैं। श्रावण माह भगवान शिव को समर्पित माह है। भगवान शिव तो संहारक के साथ सृजनकर्ता और नवनिर्माणकर्ता भी माने जाते हैं। शिव कल्याणकारी, सर्वसिद्धिदायक, सर्वश्रेयस्कर, कल्याणस्वरूप और कल्याणप्रदाता हैं। वह हमेशा योग मुद्रा में विराजमान रहते हैं और हमें जीवन में योगस्थ, जीवंत और जागृत रहने की शिक्षा देते है। शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल को कंठ में धारण कर पूरी पृथ्वी को विषाक्त एवं प्रदूषित होने से बचाया। विष शमन करने के लिए उन्होंने सिर पर चंद्रमा को धारण किया और सभी देवताओं ने गंगा का पवित्र जल उनके मस्तक पर डाला। ताकि उनका शरीर शीतल रहे और विष की उष्णता कम हो जाए। यह घटना श्रावण के दौरान हुई थी, इसलिए श्रावण में शिव को गंगा का पवित्र जल अर्पित कर उनका अभिषेक किया जाता है। शिवाभिषेक से तात्पर्य दिव्यता को आत्मसात कर आत्मा को प्रकाशित करना है। प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करने का उद्देश्य है हमारे अंदर की और वातावरण की नकारात्मकता दूर हो तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मकता का समावेश हो। श्रावण प्रकृति एवं पर्यावरण की समृद्धि, नैसर्गिक सुंदरता के संवर्धन और संतुलित जीवन का संदेश देता है। नैसर्गिक सुंदरता के संवर्धन के लिए शिवाभिषेक के साथ धराभिषेक (धरती का अभिषेक) नितांत आवश्यक है। वास्तव में देखें तो श्रावण प्रकृति को सुनने, समझने और प्रकृतिमय जीवन जीने का संदेश देता है।

**स्वामी चिदानंद सरस्वती**
परमाध्यक्ष, परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

# जिसका दाम उसी के नाम

बात 1985 की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ओडिशा के सूखाग्रस्त इलाके कालाहांडी के दौरे पर थे। वहीं पर उन्होंने कहा कि हम अगर एक रुपया भेजते हैं तो लाभार्थियों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचता है। इसी से आप सरकारी योजनाओं से जनकल्याण के स्तर को समझ सकते हैं। अब नए दौर का भारत है। इसके काम करने का अंदाज अलहदा है। डीबीटी सेवा के माध्यम से ऐसी तमाम योजनाओं का पैसा लोगों के सीधे खाते में भेजा जाने लगा। लेकिन यह भी नाकाफी साबित हुआ। लोगों को जिस मद में पैसा भेजा गया, वे उसका किसी और मद में इस्तेमाल कर लेते थे। इससे पूरी योजना का मकसद ही निष्फल होता दिखा। अब ऐसा नहीं होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ई-रुपी वाउचर की शुरुआत की। लाभार्थियों तक उनका हक पहुंचाने के लिए इसे क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को जिस काम के लिए पैसा दिया है, उसका उपयोग भी उसी काम के लिए होगा। इससे सरकारी योजनाओं में लक्षित, पारदर्शी और लीकेज फ्री डिलीवरी में मदद मिलेगी। कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी को किसी जरूरत के लिए ई-रुपी वाउचर देकर संतुष्टि हासिल कर सकेंगे। इस कदम से लाभार्थी के स्तर पर भी गड़बड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। ऐसे में देश के इस महत्वाकांक्षी कदम का लोगों के कल्याण पर पड़ने वाले सकारात्मक असर की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।

इलस्ट्रेशन : अवधेश

## व्यवस्था में होगा क्रांतिकारी बदलाव

डा. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु और वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

**ई-रुपी के लागू होने से लक्ष्य से आधा भी नतीजा नहीं दे पाने वाली सरकारी योजनाओं की शत प्रतिशत लक्ष्य केंद्रित बनाने की राह खुलेगी। अव्यवस्था की भेंट चढ़ने वाली हजारों करोड़ राशि का उद्देश्यपूर्ण तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा।**

जन कल्याण के लिए 1,000 से ज्यादा सरकारी योजनाओं के बावजूद देश में असमानता खत्म नहीं हो पाई है। सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपये के खर्च से भी उपयुक्त नतीजे नहीं मिलते हैं। योजनाएं 65 प्रतिशत परिणाम भी नहीं दे पाती हैं और लाभ लक्ष्य से आधे लोगों को भी नहीं मिल पाता है। योजनाओं की 50,000 करोड़ रुपये की राशि लीकेज की भेंट चढ़ जाती है। इस कारण गंवाए गए अवसरों का आकलन करें तो यह नुकसान और भी ज्यादा है।

इन आंकड़ों की चर्चा आज इसलिए जरूरी हो गई है, क्योंकि सरकार ने क्रांतिकारी पहल के तौर पर ई-रुपी वाउचर लांच किया है। सधे लक्ष्य के साथ उद्देश्य विशेष के लिए सहायता उपलब्ध कराने की ई-रुपी वाउचर जैसी व्यवस्था बिचौलियों का खेल खत्म करेगी। इससे एक ऐसी व्यवस्था बनेगी, जिसमें सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचेगा। ई-रुपी को समय के साथ सब्सिडी देने के वर्तमान तरीके की जगह लेनी चाहिए। मौजूदा व्यवस्था में लीकेज और भ्रष्टाचार की बहुत गुंजायश रह जाती है। इससे सहायता राशि का उचित मूल्य सामने नहीं आ पाता है। बहुत सी जन कल्याण की योजनाएं गलत तरीके से तैयार की गई हैं और उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था और भी खराब है। यह खामी सही लाभार्थी तक पूरा लाभ नहीं पहुंचने देती है। नतीजा समाज को भुगतना पड़ता है।

उदाहरण के तौर पर, हाशिए पर जी रहे किसानों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है। कर्ज माफी से गरीबों की कीमत पर धनी किसान लाभान्वित होते हैं। प्रवासी मजदूरों को सब्सिडी वाला राशन नहीं मिल पाता है। मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं बमुश्किल ही कहीं उपलब्ध होती हैं। न्यूनतम वेतन से मजदूरों को कोई लाभ नहीं होता। गरीब बच्चों के हिस्से का दूध कहीं और इस्तेमाल हो जाता है। निशुल्क प्राइमरी शिक्षा में बच्चे पढ़ने नहीं, बल्कि मिड डे मील लेने पहुंचते हैं। मुफ्त टीकाकरण की योजनाओं का लाभ भी कम लोगों को ही होता है।

**असल लाभार्थी को मिलेगा लाभ:** ई-रुपी वाउचर जिस व्यक्ति और जिस काम के लिए जारी होगा, उसी के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। इसमें लाभार्थी के पास बैंक खाता होना भी जरूरी नहीं है। यह लाभार्थी और लाभ देने वाले के बीच की कड़ी होगा। इससे उन 20 करोड़ भारतीयों तक जन कल्याण की योजनाएं पहुंचाना संभव होगा, जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। यह व्यवहारवादी अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ता कदम है, जिसमें आर्थिक नीतियों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का भी ध्यान रखा जाता है।

**सेस का रूप ले सकता है ई-रुपी:** 2020 में 26 हजार आयकर दाताओं के बीच अध्ययन में सामने आया कि अगर धन के खर्च में पारदर्शिता हो तो लोग ज्यादा टैक्स भरने से भी गुरेज नहीं करते हैं। लोग ऐसी व्यवस्था की उम्मीद करते हैं, जिसमें तरह-तरह के सेस भरने के बजाय कोई नागरिक किसी किसान को एक स्वास्थ्य बीमा खरीदने या किसी गरीब बच्चे की फीस भरने में सीधे मदद कर सके। उम्मीद है कि एक दिन सरकार विभिन्न सेस को ई-रुपी में बदलेगी। ई-रुपी उन बहुत सी चुनौतियों को एक झटके में पार कर लेता है, जिनके लिए सामान्यतौर पर बहुत निवेश की जरूरत होती।

**आर्थिक नहीं, सामाजिक कदम:** इसे मात्र तकनीक की मदद से उठाया गया शानदार आर्थिक कदम नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह व्यवहार में बदलाव लाने वाला कदम है। लोग यह तय कर सकेंगे कि उनका योगदान कहां खर्च हो रहा है। यह सरकार का भरोसा बढ़ाने वाला कदम होगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसी कई अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा माडल काम करता है।

**बड़ी सोच:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का दायरा बहुत बड़ा है। उनका लक्ष्य सीएसआर के माध्यम से कंपनियों को और साथ ही आम जनता को भी राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए सशक्त करना है। वह निश्चित तौर पर अपनी राजनीतिक क्षमता के दम पर विरोधियों को राजी करेंगे और कई जन कल्याण की योजनाओं को ई-रुपी के दायरे में लाएंगे। वह अपनी लोकप्रियता के दम पर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि हर व्यक्ति कम से कम किसी एक जरूरतमंद की सहायता के लिए आगे आए और देश का साथ दे। पीएम मोदी का लक्ष्य सब्सिडी की व्यवस्था को हमेशा के लिए बदलना है, जिससे अच्छे नतीजे मिलें और सरकार एवं जनता के बीच स्वस्थ संबंध बने। इस व्यवस्था के नतीजे स्थायी होंगे और जीडीपी में 16-17 फीसद तक का योगदान दे सकते हैं।

## ई-रुपी वाउचर: बड़े काम की चीज

ई-रुपी मूल रूप से एक डिजिटल प्रीपेड वाउचर है। किसी लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में यह वाउचर मिलेगा। जिस उद्देश्य के लिए इसे जारी किया जाएगा, उससे संबंधित अधिकृत केंद्र पर ही इसे भुनाया जा सकेगा। किसी एक सेवा के लिए मिले वाउचर का इस्तेमाल किसी अन्य सेवा में नहीं किया जा सकेगा। देश में यूपीआइ की व्यवस्था संभालने वाले नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) ने इसे विकसित किया है। यह कैशलेस और कांटैक्टलेस पेमेंट सिस्टम को बढ़ाने वाला कदम होगा। कुछ लोग इसे डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ता कदम भी मान रहे हैं।

### ऐसे करेगा काम

किसी भी सरकारी एजेंसी और कंपनी को अपने भागीदार बैंक के माध्यम से यह वाउचर जारी करने की अनुमति होगी। कंपनी किसी निश्चित कार्य के लिए निश्चित राशि का वाउचर बैंक के माध्यम से जारी करेगी। संबंधित सेवा या कार्य के बाद मूल्य चुकाते समय लाभार्थी वाउचर से भुगतान कर सकेंगे। वाउचर भुनाते ही वह राशि संबंधित केंद्र के खाते में पहुंच जाएगी। वाउचर के बदले में नकद नहीं मिलेगा।

### लाभार्थी का लाभ

बैंक खाता, स्मार्टफोन, इंटरनेट जैसी सुविधाओं के बिना ही विभिन्न प्रकार की सहायता पाना संभव होगा। जिस तरह से सरकार आने वाले दिनों में इसे विभिन्न सरकारी योजनाओं की सब्सिडी का माध्यम बनाने के बारे में सोच रही है, उससे किसी योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचाने का रास्ता खुलेगा। न किसी बिचौलिए की भूमिका रहेगी और न ही सब्सिडी के दुरुपयोग की आशंका।

### इन बैंकों से जारी होंगे वाउचर

एनपीसीआइ ने ई-रुपी लेनदेन के लिए 11 बैंकों से साझेदारी की है। इनमें एक्सिस बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक आफ इंडिया शामिल हैं। इसे स्वीकारने वाले एप्स में भारत पे, भीम बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, पीएनबी मर्चेंट पे और योनो एसबीआइ मर्चेंट पे शामिल हैं। जल्द ही इस प्रक्रिया में अन्य बैंक और एप को शामिल किए जाने की उम्मीद है।

### सबके लिए फायदे का सौदा

ई-रुपी वन टाइम यूज के लिए बना वाउचर है। कार्ड, डिजिटल पेमेंट एप और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा के बिना इसका उपयोग किया जा सकता है। यह सभी संबंधित पक्षों के लिए फायदे का सौदा है।

### मामूली शुल्क वसूलेंगे बैंक

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बैंक ई-रुपी वाउचर जारी करने के लिए मामूली शुल्क लेंगे। यह शुल्क 1,000 रुपये तक के वाउचर के लिए दो रुपये, एक से पांच हजार रुपये के लिए 10 रुपये और पांच से 10 हजार रुपये के लिए 20 रुपये हो सकता है।

### जारीकर्ता को सुकून

किसी लाभार्थी को वाउचर देने वाले के लिए यह व्यवस्था सुकून देनी वाली है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई व्यक्ति किसी की गंभीर बीमारी के इलाज के नाम पर सहयोग मांगने आता है और आप उसे 10 हजार रुपये की मदद करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी मदद संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंचाता या फिर उस सहायता राशि का इस्तेमाल किसी अन्य काम में करने का प्रयास करता है। ई-रुपी वाउचर से ऐसा संभव नहीं होगा। आप इलाज में मदद के लिए निर्धारित राशि का वाउचर दे सकते हैं, जिसे संबंधित अस्पताल में बिल के समय ही भुनाया जा सकेगा। इससे सहयोग करने वाले को यह भरोसा रहेगा कि मदद सही व्यक्ति तक पहुंची है।

### योजनाओं में नहीं लगेगी सेंध

सरकारी योजनाओं में मिलने वाली सब्सिडी में सेंध की बातें अक्सर सामने आती हैं। सरकार की तैयारी है कि विभिन्न योजनाओं में दी जाने वाली सब्सिडी को ई-रुपी वाउचर के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से भी एक कदम आगे की बात होगी। बिना बैंक खाते वाले लाभार्थी भी आसानी से इसका लाभ ले सकेंगे। इससे सुनिश्चित होगा कि जो पैसा जिस योजना के लिए है, उसका प्रयोग भी उसी में हो। सब्सिडी के तौर पर मिली राशि के अन्यत्र प्रयोग की खबरें आती रहती हैं।

### तुरंत भुगतान की गारंटी

सब्सिडी की राशि देर से मिलना भी कई बार समस्या का कारण बनता है। ई-रुपी वाउचर इस मुश्किल को दूर करेगा। योजना या संबंधित सेवा का लाभ लेने से पहले ही लाभार्थी को वाउचर मिल जाएगा। यह प्रीपेड वाउचर है, इसलिए जहां इसे भुनाया जाएगा, वहां वाउचर को स्कैन करते ही या एसएमएस में मिले नंबर के जरिये प्रक्रिया आगे बढ़ाते ही संबंधित पक्ष के खाते में पैसा पहुंच जाएगा।

### इस्तेमाल के लिए अनंत आकाश

अभी एनपीसीआइ ने 1,600 से ज्यादा अस्पतालों के साथ करार किया है, जहां ई-रुपी से भुगतान किया जा सकेगा। सरकार बाल कल्याण योजना, टीबी उन्मूलन, आयुष्मान भारत, टीकाकरण समेत कई अन्य योजनाओं के लिए इसका उपयोग करने की तैयारी में है। निजी कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए वाउचर जारी करने की सुविधा मिलेगी। भविष्य में शापिंग आदि के लिए भी इसे लेनदेन का जरिया बनाया जा सकता है।

### टीकाकरण बढ़ाने का भी बनेगा जरिया

ई-रुपी वाउचर जारी करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका लगवाने के लिए इसके इस्तेमाल की बात कही है। यह देश में टीकाकरण अभियान को गति देगा। उदाहरण के तौर पर, कोई कंपनी अपने कर्मचारियों का टीकाकरण स्पांसर करने के लिए संबंधित बैंक से संपर्क कर वाउचर जारी करा सकेगी। निर्धारित अस्पताल या टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर कर्मचारी टीका लगवाकर उसका भुगतान वाउचर से कर सकेंगे।

## जनमत

**क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कुछ दशक पहले सरकारों द्वारा दिए गए हर एक रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते थे?**

**क्या हालिया लांच हुए ई-रूपी वाउचर से नागरिकों को सरकारी योजनाओं में लक्षित, पारदर्शी और लीकेज फ्री डिलीवरी हासिल हो सकेगी?**

## आपकी आवाज

सरकारी योजनाओं का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने की बात बिलकुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि योजनाओं का आधे से ज्यादा पैसा वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। आजादी के बाद से अब तक जितना पैसा इन योजनाओं के मद में खर्च किया गया है, यदि वह सब सही जगह जाता तो लोगों की स्थिति में आमूलचूल बदलाव हो चुका होता। **रोहित ओझा**

ई-रुपी एक क्रांतिकारी कदम है। डीबीटी से सब्सिडी में होने वाली धांधली पर लगाम लगी। ई-रुपी इससे भी दो कदम आगे की व्यवस्था है। यह पैसे की उस लीकेज को बंद करेगी, जिसका शिकार हमारी ज्यादातर सरकारी योजनाएं हो जाती हैं। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को ई-रुपी के तहत लाए। **विकास तिवारी**

यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि हमारे ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक मंच पर स्वीकारा था कि योजनाओं के लिए भेजे गए 100 पैसे में से 15 पैसे ही अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आधार और जनधन खाते के जरिये इस बरबादी को रोकने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। ई-रुपी इसमें और सहायक होगी। **गौतम कुमार**

यह सच है कि हमारे यहां योजनाएं भ्रष्टाचार का शिकार होती रही हैं। यदि इनमें से भ्रष्टाचार को हटा दिया जाए, तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। योजनाओं का 85 फीसद पैसा लीक हो जाना भले ही सही न लगे, लेकिन यह तो सच है कि आधे से ज्यादा पैसा तो बरबाद ही होता है। इस बरबादी को रोकना किसी भी सरकार का पहला प्रयास होना चाहिए। **राकेश दीप**

## डीबीटी ने बचाए पौने दो लाख करोड़ रुपये

सरकारी योजनाओं में फर्जी लाभार्थी बड़ी समस्या रहे हैं। तकनीक ने ऐसे फर्जी लोगों को व्यवस्था से बाहर करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। जनधन खाता, आधार और मोबाइल (जेएएम) की तिकड़ी की मदद से फर्जी लोगों के नाम पर खपत हो जाने वाली हजारों करोड़ रुपये की राशि को बचाया गया है।

**₹12,95,468 करोड़** दिए गए सीधे लाभार्थियों के खाते में छह साल में

**₹1,70,377.11 करोड़** बचाए गए फर्जी लाभार्थियों को हटाकर

**5.55 लाख** फर्जी लोग हटाए गए मनरेगा से दिसंबर, 2019 तक

**₹24,162 करोड़** बचाने में मिली मदद

**98.8 लाख** फर्जी लोग पहचाने गए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं में

**₹1523.75 करोड़** बचाने में मिली मदद

### फर्जी लाभार्थियों का खेल

देश में सब्सिडी वाली रसोई गैस (एलपीजी) पाने वालों में कैसे फर्जी लाभार्थियों के खेल को इससे समझा जा सकता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2011 में सब्सिडी वाली एलपीजी इस्तेमाल करने वाले परिवारों की संख्या की तुलना में लाभ लेने वाले परिवारों की संख्या डेढ़ गुना थी।

### सरकारी योजनाओं में पौने दो लाख करोड़ की बचत

2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जेएएम की तिकड़ी की मदद से डीबीटी की ओर बढ़ते कदम से सरकार ने विभिन्न योजनाओं में पिछले छह साल में 1.70 लाख करोड़ की बचत की। डीबीटी नहीं होने से यह राशि फर्जी लोगों के नाम पर खर्च हो जाती थी। रिपोर्ट में 51 मंत्रालयों की 351 योजनाओं को शामिल किया गया, जिनमें सब्सिडी लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। इनमें मनरेगा, पीडीएस और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम शामिल हैं।

### एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले परिवारों की संख्या

(प्रतिशत में)

### सामाजिक सुरक्षा पर खर्च

1991 से 2018 के बीच सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण के मद में केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत बड़ी रकम खर्च की गई। 2016 से इस रकम में चार गुना का इजाफा हुआ है। 2018 में यह बढ़कर 1,62,683 करोड़ रुपये हो गई।

(आंकड़े अरब रुपये में)

| वर्ष | खर्च |
|---|---|
| 1991 | 24.48 |
| 2001 | 83.82 |
| 2008 | 247.09 |
| 2009 | 345.44 |
| 2010 | 400.53 |
| 2011 | 419.02 |
| 2012 | 270.66 |
| 2013 | 106.54 |
| 2014 | 393.43 |
| 2015 | 429.76 |
| 2016 | 1358.66 |
| 2017 | 1587.75 |
| 2018 | 1626.83 |

**₹66,896.87 करोड़** बचाए गए आधार और मोबाइल नंबर जोड़ने से राशन वितरण प्रणाली में छह साल में

**2.98 करोड़** फर्जी लाभार्थियों को पीडीएस प्रणाली से बाहर किया गया

## साहसिक स्वागतयोग्य कदम

भरत झुनझुनवाला
वरिष्ठ अर्थशास्त्री

**योजनाएं भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती हैं जिससे सरकार और लाभार्थी दोनों का ही मकसद अधूरा रहता है। इस दुष्चक्र से निजात पाने के लिए सरकार ने ई-रुपी वाउचर की व्यवस्था बनाई है। सरकार का यह कदम साहसिक, सही दिशा में और स्वागत योग्य है।**

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आजादी के बाद देश और लोगों का आर्थिक स्तर सुधरा है। और इस सुधार में सरकारी जनकल्याण योजनाओं की प्रभावी भूमिका है। सरकारी योजनाओं की सामान्य कार्यप्रणाली इस तरह से समझिए। टीबी के मरीजों के लिए सरकार दवा देना चाहती है। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग इन दवाओं को खरीदता है जिसमें कमीशन लेने की आशंका को कोई खारिज नहीं कर सकता है। इसके बाद सरकारीकर्मी इन दवाओं को विभाग से लेकर उन्हें ब्लैक में बेच सकते है। यदि दवा मरीज तक पहुंच भी गई तो वह भी उस दवा को बेच सकता है। रुपी वाउचर प्रणाली के तहत सरकार दवा की रकम को निर्धारित बैंक में जमा करा देगी। दवा को किन दुकानों से खरीदा जा सकता है यह निर्धारित कर देगी। इसके बाद मरीज के फोन पर एक कोड भेजेगी। मरीज उस कोड को अपनी मनपसंद दुकान को दिखाकर उससे दवा प्राप्त कर सकता है। अंत में दुकानदार उस कोड को बैंक को देकर उस दवा को प्राप्त कर सकता है।

इस नई व्यवस्था में भी रिसाव की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिले अनाज का हर गांव में एक असंगठित बाजार बन चुका है। प्रणाली से मिले सस्ते अनाज को लोग औने-पौने दाम पर बेच देते हैं। इसी प्रकार ई-रुपी वाउचर से मरीज द्वारा दुकानदार को कोड दे दिया जाएगा लेकिन मरीज द्वारा उससे दवा के स्थान नगद लिया जा सकता है, अथवा दूसरी दवा ली जा सकती है, 100 रुपये की दवा के एवज में दुकानदार मरीज को 70 रुपये दे देगा और स्वयं बैंक से 100 रुपये ले लेगा। फिर भी यह कदम साहसिक है। चूंकि भ्रष्टाचार कम होगा और जनता सबल होगी।

तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं इस आधार पर बनी हुई है कि जनता मूर्ख है। मरीज नहीं समझता है कि टीबी की दवा निरंतर लेना जरूरी है। इसलिए सरकारी कर्मी दवा खरीदेंगे और मरीज को देंगे। लेकिन सरकार मरीज को दवा दे सकती है, उसे दवा खिला नहीं सकती है। नतीजा यह कि मुफ्त मिली दवा को मरीज फेंक देता है। सरकार को चाहिए कि जनता को शिक्षित करे कि दवा निरंतर खाना क्यों जरूरी है।

जनता को मूर्ख मानने की विचारधारा लोकतंत्र की सोच के विपरीत है। लोकतंत्र में हम मानते हैं कि जनता ही सर्वभौमिक सत्ता की अधिकारी है। यदि जनता मूर्ख है तो उसे यह अधिकार क्यों दिया गया? इसलिए इन तमाम योजनाओं को समाप्त कर एक मुश्त रकम जनता के खाते में ट्रांसफर करना चाहिए जिससे जनता अपने सार्वभौमिक विवेक के अनुसार उस रकम का उपयोग कर सके। सरकार को जन शिक्षा में निवेश करना चाहिए जैसे मां अपने बच्चे को हर छोटी-बड़ी बात के लिए समझाती है, वैसे ही सरकार को जनता को समझाना चाहिए। वास्तव में जनता अपने हित को अच्छे से समझती है। गरीब लोग भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाने के लिए अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करने को तैयार रहते है। उन्हें अपना हित हासिल करना खूब आता है। इतना सही है कि एकमुश्त रकम को ट्रांसफर करने से 100 में से पांच लाभार्थी द्वारा रकम का दुरुपयोग किया जाएगा, लेकिन इन पांच लाभार्थियों के कारण 95 लाभार्थियों को मूर्ख घोषित करने का क्या औचित्य है? इस परिप्रेक्ष्य में ई-रुपी वाउचर सही दिशा में साहसिक कदम है। इतना माना गया कि मरीज केवल आधा मूर्ख है। दवा लेना जरूरी है यह मूर्ख मरीज नहीं जानता लेकिन दवा कहां से खरीदना है, यह विद्वान मरीज जानता है। जनता के प्रति इस आधे विश्वास को ई-रुपी वाउचर से पूरे में बदला जा सकता है। इसे तार्किक परिणाम पर ले जाने की जरूरत है। सभी योजनाओं पर व्यय संपूर्ण रकम को जनता को सीधे ट्रांसफर करने का अगला कदम उठाना चाहिए।

दैनिक जागरण

स्वप्न और लक्ष्य के बीच योजना ही निर्णायक सिद्ध होती है

# विपक्ष की शिकायत

यह हास्यास्पद है कि विपक्ष इस बात की शिकायत राष्ट्रपति से करने की तैयारी कर रहा है कि संसद में हंगामे के बीच विधेयक क्यों पारित हो रहे हैं? क्या विपक्ष को यह नहीं पता कि वही तो है जो संसद में हंगामा कर रहा है? आखिर वह राष्ट्रपति से किसकी शिकायत करेगा? क्या खुद अपनी? सवाल यह भी है कि इस मामले में राष्ट्रपति कर ही क्या सकते हैं? विपक्षी नेता इससे अनजान नहीं हो सकते और न ही उन्हें होना चाहिए कि राष्ट्रपति के पास जाने से उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं। राष्ट्रपति भवन तक उनकी दौड़ संसद के बाहर धरना-प्रदर्शन जैसी कवायद के अलावा और कुछ नहीं होगी। विपक्ष को क्षणिक प्रचार के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। उचित यह होगा कि विपक्ष इस पर विचार करे कि संसद किन कारणों से नहीं चल रही है? यदि वह इस सवाल पर थोड़ा भी विचार करेगा तो उसे अपनी गलती का अहसास अवश्य होगा, क्योंकि यदि संसद नहीं चल रही है तो उसके ही अड़ियल रवैये के कारण। उसे यह आभास होना चाहिए कि वह जिस पेगासस जासूसी मामले को तूल दे रहा है, वह बहुत ही कमजोर बुनियाद पर टिका है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इसकी पुष्टि तब हुई जब याचिकाकर्ता न्यायाधीशों के इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि आखिर इस मामले के प्रमाण कहां हैं?

समझना कठिन है कि विपक्ष यह क्यों नहीं देख पा रहा है कि वह उन ज्वलंत मसलों पर भी चर्चा कर पाने में नाकाम है, जिन्हें वह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बताता रहा है और जिन्हें संसद में उठाने की जोर-शोर से घोषणा भी करता रहा है। इससे इन्कार नहीं कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि, किसान संगठनों के आंदोलन और कोरोना से उपजी स्थिति पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए विपक्ष ही जिम्मेदार है। विपक्ष की इस आपत्ति का तो कोई मूल्य-महत्व ही नहीं कि हंगामे के बीच विधेयक क्यों पारित हो रहे हैं? क्या वह यह चाहता है कि उसकी तरह सरकार भी अपने दायित्वों को भूल जाए? संसद चल रही हो तो जरूरी विधेयक पेश और पारित कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी की अनदेखी करने का मतलब है देश के लिए आवश्यक कामों को रोक देना। यदि विपक्ष यह चाहता है कि इन कामों में उसकी भी भागीदारी हो तो फिर उसे ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि संसद में व्यापक विचार-विमर्श हो सके। क्या यह अजीब नहीं कि वह ऐसे हालात भी नहीं पैदा होने दे रहा है और विधेयकों के पारित होने पर आपत्ति भी जता रहा है?

# परीक्षाओं की पवित्रता

एक तरफ जब पूरा देश ओलिंपिक में हरियाणा के नीरज चोपड़ा के स्वर्णपदक लाने पर गौरवान्वित हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ नकल माफिया परीक्षाओं की पवित्रता को कलंकित करने में जुटा था। कोरोना संक्रमण के आक्रमण के कारण लंबे अरसे से हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं नहीं हुई थीं। स्थितियां सामान्य हुईं तो आयोग ने पुलिस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ की, लेकिन पहले ही दिन पुरुष कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के दौरान कैथल में ऐसे लोग पकड़े गए, जिनके पास उत्तर पुस्तिका भी मिली। इसके साथ ही आयोग ने भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी। स्पष्ट है कि इससे उन परीक्षार्थियों को अपार कष्ट हुआ होगा, जिन्होंने पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जमकर तैयारी की होगी। यद्यपि परीक्षा निरस्त करना भी आवश्यक था। यदि आयोग ऐसा न करता तो योग्य परीक्षार्थियों से अधिक अंक प्राप्त कर नकल करने वाले अभ्यर्थी चयनित हो जाते। विचारणीय है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हरियाणा का नकल माफिया यहां होने वाली हर परीक्षा की पवित्रता को भंग कर देता है। और तो और न्यायिक परीक्षाओं में भी वह अपनी कलुषित भूमिका निभाने से बाज नही आता। यह भी रेखांकित करने वाली बात है कि अब तक जो लोग नकल कराने के अपराध में पकड़े गए हैं, लगभग सभी कोचिंग सेंटर संचालकों से जुड़े हुए मिले। कोचिंग सेंटर संचालक परीक्षाओं में उत्तीर्ण कराने की गारंटी लेते हैं और इसके लिए मोटी रकम वसूलते हैं। हरियाणा के नकल माफिया का जाल केवल हरियाणा में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित दक्षिण भारत के प्रदेशों तक हरियाणा के लोग नकल कराने में संलिप्त पाए जा चुके हैं। इसी से समझा जा सकता है कि नकल माफिया का जाल कितना मजबूत और विशाल है। जिस हरियाणा के युवा अपने सरल स्वभाव और उत्कृष्ट शरीर सौष्ठव के लिए जाने जाते हैं, नकल माफिया उनसे इस तरह के अपकृत्य करा रहा है। जब तक सरकार नकल माफिया के जाल को ध्वस्त नहीं करेगी, परीक्षाएं अपवित्र होती रहेंगी। यह चिंताजनक है और प्रदेश सरकार को नकल माफिया का समूल नष्ट करने का संकल्प लेना होगा।

**कोई भी परीक्षा हो, हरियाणा का नकल माफिया उसे निष्कलंक नहीं रहने देता, यह चिंताजनक है**

# विपक्षी दलों की बेचैनी के निहितार्थ

सुरेंद्र किशोर

**अपनी गोलबंदी के जरिये विपक्ष सत्ता में बदलाव का डर दिखाकर जांच एजेंसियों पर दबाव डालने में लगा है कि उसके नेताओं के खिलाफ मामलों में तेजी न दिखाई जाए**

लोकसभा के अगले चुनाव में अभी ढाई साल से अधिक का समय है। फिर भी विपक्षी दल अभी से ही नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ गोलबंद होने की कोशिश करने लगे हैं। वे आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? सत्ता के प्रति उनमें कटुता की इतनी अधिक भावना क्यों है? इसके दो कारण नजर आ रहे हैं। एक तो अगले साल उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए प्रतिपक्ष को अपने पक्ष में माहौल बनाना है। प्रतिपक्ष के कई दलों के सामने एक और बड़ी समस्या है। वह यह कि उनके कई नेताओं एवं रिश्तेदारों के खिलाफ जारी भ्रष्टाचार के मुकदमों में उन्हें कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति ने यह स्थिति पैदा कर दी है।

हालांकि अतीत में भी भ्रष्टाचार के मुकदमे देश में दर्ज होते थे, किंतु तब जल्दी-जल्दी सरकारें बदल जाने के कारण मुकदमों को आमतौर पर दबा या दबवा दिया जाता था। एक गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री तो कहा करते थे कि एक खास राजनीतिक परिवार को नहीं 'छूना' है। मोदी सरकार में उस परिवार के साथ-साथ देश के अनेक नेताओं और घरानों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं। वे सुनवाई के विभिन्न स्तरों पर हैं। अगले 34 महीनों में पता नहीं कितने मुकदमों में क्या-क्या निर्णय हो जाएं। इनके आरोपितों को लगता है कि यदि वे भाजपा विरोधी प्रतिपक्ष को जल्द से जल्द एक करने में सफल हो गए तो अभी से केंद्रीय जांच एजेंसियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सकेंगे कि हम सत्ता में आने ही वाले हैं। इसलिए मामले में आप ज्यादा तेजी मत दिखाइए, लेकिन लोकसभा से पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। प्रतिपक्ष की कोशिश है कि उसके लिए भी मोदी विरोधी माहौल बनाना जरूरी है। उनके अनुसार लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि मोदी सरकार संसद चलाने में भी विफल है। हालांकि लोग देख रहे हैं कि संसद में व्यवधान कौन पैदा कर रहा है।

वैसे तो अगले ढाई साल में कौन-सी राजनीतिक, गैर-राजनीतिक घटना होगी, उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसका राजनीति और चुनाव पर कैसा असर पड़ेगा, किंतु आज की राजनीतिक स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी लगता है। मोदी के 40 प्रतिशत वोटों के खिलाफ प्रतिपक्ष के 60 प्रतिशत मतों की गोलबंदी विपक्षी कोशिशों के केंद्र में है। हालांकि यह दिवास्वप्न की तरह ही लगता है। पिछले चुनाव में कई राज्यों में राजग को

अवधेश राजपूत

50 प्रतिशत वोट मिल चुके हैं। कुछ अन्य राज्यों में राजग के खिलाफ प्रतिपक्ष की पूर्ण एकता असंभव जैसा लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश इसका एक उदाहरण है। बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 47.97 प्रतिशत और भाजपा को 38.09 प्रतिशत वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 43 प्रतिशत और भाजपा को 40 प्रतिशत वोट मिले थे। बंगाल के गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.94 प्रतिशत और माकपा को 4.72 प्रतिशत वोट मिले। एक कांग्रेसी नेता के अनुसार कांग्रेस समर्थक मुसलमानों ने आखिरी वक्त में तृणमूल के उम्मीदवारों को वोट दे दिए। माकपा के अधिकतर समर्थकों ने भी यही काम किया। अब सवाल है कि जितने मत माकपा और कांग्रेस को मिले, उनमें से कितने वोट अगले चुनाव में भी इन विलुप्त होते दलों को मिल पाएंगे? हारते हुए उम्मीदवारों को कितने लोग वोट देते हैं! यानी कांग्रेस एवं माकपा के बचे-खुचे वोट दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दलों तृणमूल और भाजपा के बीच बंट सकते हैं। कुछ अन्य राज्यों में भी यही हाल रहने वाला है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, किंतु इतना कहा जा सकता है कि राजग विरोधी दलों की आशावादिता का अभी कोई ठोस आधार नजर नहीं आ रहा है।

अब जरा दो विपरीत स्थितियों की कल्पना कीजिए। राजग यदि तीसरी बार जीत गया तो क्या होगा? दूसरी ओर राजग विरोधी गठबंधन जीत गया तो क्या-क्या होगा? राजग की जीत के बाद बड़े-बड़े नेताओं और व्यापारियों के खिलाफ जारी अधिकतर मुकदमों के फैसले नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में संभवतः आ जाएंगे। उनसे कई बड़े नेताओं और घरानों की राजनीति का अवसान संभव है। जाहिर है आरोपित नेता और व्यापारी गण आज अपने होशोहवास में नहीं होंगे। अब आप इसके विपरीत स्थिति की कल्पना कीजिए। यदि 2024 में देश में मिलीजुली सरकार बन जाएगी तो क्या होगा? उस सरकार का पहला काम तो यही होगा कि नेताओं और समर्थक व्यापारियों के खिलाफ जारी मुकदमों को या तो बंद किया जाए या फिर उन्हें कमजोर किया जाए। जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उनमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक और हरियाणा से बंगाल तक के नेतागण शामिल हैं। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ जारी मुकदमे जब कमजोर हो जाएंगे तो देश के शासन और राजनीति पर उसका कैसा असर पड़ेगा? भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद में तेजी आएगी या कमी?

सरकार बदलने पर मुकदमे कैसे कमजोर किए जाते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहां पेश हैं। कांग्रेस की मदद से केंद्र में 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी। जब उन्होंने संजय गांधी पर जारी मुकदमों पर पर्दा डालने से मना कर दिया तो कांग्रेस ने उनकी सरकार गिरा दी। 1980 में लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस सत्ता में आई। फिर सारे मुकदमे रफा-दफा कर दिए गए। नवंबर 1990 में कांग्रेस की मदद से केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार बनी थी। जब चंद्रशेखर ने बोफोर्स केस को बंद करने से मना कर दिया तो उनकी भी सरकार गिर गई। फिर 1991 में कांग्रेस की सरकार बनी, किंतु कांग्रेस के पास खुद का बहुमत नहीं था। इसलिए पीवी नरसिंह राव पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ सांसदों से सौदा किया। यानी इस देश की राजनीति का कुछ और पतन हुआ। साफ है यदि मोदी सरकार भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति पर लगातार चल पा रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलना था।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

# आंदोलन का सही मूल्यांकन आवश्यक

प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल

**भारत छोड़ो आंदोलन हिंसा और अहिंसा के विवाद से परे समग्र आजादी का आंदोलन था, जिस पर नेता जी की भी भरपूर छाप थी**

पूर्ण आजादी के प्रखर पैरोकार थे सुभाष चंद्र बोस। फाइल

जब देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है तब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा स्वाभाविक है। यह एक ऐसा आंदोलन था, जिसमें नेता जेलों में थे और जनता आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। जनता अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए उद्यत होकर सतारा से बलिया तक और हजारीबाग से लाहौर तक सर्वत्र सीधी और निर्णायक लड़ाई लड़ रही थी। आज जब इस घटना के 80 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं तब उसका मूल्यांकन होना आवश्यक प्रतीत होता है। 1942 का आंदोलन गांधी जी के जीवन का सबसे निर्णायक और बड़ा अभियान था। कांग्रेस कार्यसमिति ने 14 जुलाई, 1942 के अपने वर्धा प्रस्ताव में इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी, नेतृत्व, नियंत्रण और आगे की दिशा गांधी जी के हवाले कर दी थी। इस प्रस्ताव और उसके बाद की घटनाओं पर इतिहास में बहुत चर्चा हुई है, लेकिन 1942 का यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यसमिति में किन परिस्थितियों में आया था, इस पर नहीं के बराबर चर्चा हुई है। इसीलिए उस पर विमर्श आवश्यक है।

अभी देश ने आजाद हिंद फौज के 75 वर्ष धूमधाम से मनाए हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पर भी व्यापक चर्चा हुई थी, मगर 1942 के निर्णायक आंदोलन को इस मुकाम तक ले आने में सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव अभी तक मूल्यांकित नहीं हुआ है। कांग्रेस में 1942 के आंदोलन की जो धार है, वह सुभाष बाबू की आवाज है। करो या मरो, रास्ता चाहे जो हो, आजादी चाहिए। डोमेनियन स्टेट और उसके बाद स्वतंत्रता की क्रमशः विकसित होने वाली अवधारणा भारत को स्वीकार नहीं है। यह अवधारणा गांधी जी और कांग्रेस की अपेक्षा, सुभाष बाबू के विचारों के अधिक नजदीक थी। जुलाई 1942 में गांधी जी ने कांग्रेस कार्यसमिति के लिए जो मसौदा प्रस्तुत किया था, वह भारत की आजादी का मसौदा सुभाष-गांधी प्रतिरोध की छाया में है। इस मसौदे में गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि 'भारत की स्वतंत्रता इस तरह न केवल भारत के हित के लिए, बल्कि विश्व की सुरक्षा के लिए और नाजीवाद, फासीवाद, सैन्यवाद, साम्राज्यवाद और जिस किसी वाद का जापान प्रतिनिधित्व करता है, उसकी समाप्ति के लिए आवश्यक है।' गांधी जी द्वारा इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार करते समय जापान का उल्लेख केवल इसलिए नहीं है कि जापानी सेना तेजी से भारत की ओर बढ़ रही थी। जून 1942 में सुभाष बाबू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लीग का जापान में अधिवेशन संपन्न हुआ था और आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन प्रारंभ हो गया था। आजाद हिंद सरकार को दुनिया के कुछ देशों द्वारा मान्यता देने की तैयारी हो गई थी। ऐसे में कांग्रेस द्वारा जापान को भारत का विरोधी और शत्रु प्रतिपादित किया जाना इसकी ओर संकेत करता है कि कांग्रेस आजाद भारत की सत्ता को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। गांधी जी ने नौ जुलाई को अपना मसौदा जवाहरलाल नेहरू को भेजा था। नेहरू ने इसमें कुछ संशोधन किए थे। क्रिप्स मिशन की असफलता और भारत के आमजन में ब्रितानी सरकार के विरुद्ध उभर रहे आक्रोश तथा जापानी फौज की सफलता पर भारतीयों में संतोष के भाव की वृद्धि से जुड़ी पंक्तियां पंडित नेहरू ने जोड़ी थीं।

वर्ष 1942 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रतिनिधि कर्नल जानसन ने भारत से मित्र राष्ट्रों के साथ खड़ा होने की अपील करते हुए कहा था कि 'सदाशय भारतीयों, आप हम पर उसी प्रकार विश्वास रखिए, जैसे हम आप पर रखते हैं।' इन सभी बातों से एक बात निकलकर आती है कि युद्ध में जापान की लगातार बढ़त ने भारत की आजादी को अवश्यंभावी बना दिया था। आजादी के साधनों को लेकर नेता जी और गांधी जी के बीच जो विरोध था, वह भी भारत के आम जन की दृष्टि में बेमानी हो गया था। 1942 का आंदोलन हिंसा और अहिंसा के विवाद से परे केवल समग्र आजादी का आंदोलन था। यह बात दीगर है कि वायसराय लार्ड लिनलिथगो को पत्र लिखकर गांधी जी ने स्वयं को इस आंदोलन से अलग कर लिया था, किंतु समूची कांग्रेस और उसके नेताओं के समक्ष करो या मरो का प्रश्न खड़ा था।

मुंबई कांग्रेस महासभा की बैठक के बाद नौ अगस्त की सुबह से आंदोलन कांग्रेस की पकड़ से बाहर हो गया था। यह जनता का आंदोलन हो गया था, जिसने अपने नए नेता बना लिए थे। अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, राममनोहर लोहिया से लेकर चित्तू पांडे तक ऐसे नेता उभरकर सामने आए, जिन्हें डोमेनियन स्टेट की अवधारणा पर विश्वास नहीं था। जिन्हें अंग्रेजों के जाने के बाद भारत का क्या होगा, इसकी चिंता अंग्रेज करें, यह गवारा नहीं था। इन सबके पीछे कोई उद्दीपक शक्ति थी तो वह थी आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज तथा सुभाष चंद्र बोस का आह्वान कि 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।' 1939 से 1943 तक भारत और दुनिया में भारत को लेकर जो कुछ घटित हो रहा था, उस पर सुभाष चंद्र बोस का बड़ा प्रभाव रहा।

भले ही साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, सैन्यवाद का प्रतिनिधित्व करने वाली उस काल की साम्यवादी शक्तियां नेता जी को 'तोजो का कुत्ता' जैसी गालियां दे रही हों, मगर नौ जुलाई से लेकर नौ अगस्त, 1942 तक गांधी, नेहरू और कांग्रेस के वैचारिक विमर्श में जिस प्रकार से ब्रितानियों से बड़ा शत्रु जापान को साबित करने की कोशिश की जा रही थी, वह नेता जी के प्रभाव को दर्शाती है, क्योंकि इसी समय सुभाष बाबू जापान में इंडियन नेशनल लीग और आजाद हिंद फौज के गठन के प्रयास कर रहे थे। उसका भारत के आमजन पर गहरा प्रभाव था। उसके प्रभाव में ही 1942 में क्रमिक आजादी की अवधारणा को नकार दिया गया और संपूर्ण आजादी की हुंकार भरी गई।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं)

response@jagran.com

## क्षमा

जब हम कभी छुट्टियों का आनंद ले रहे होते हैं तब हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ बिताते हैं। उस समय हमारा पूरा ध्यान खुशी, प्रेम और उनकी देखभाल पर केंद्रित होता है। इस प्रेम और खुशी के माहौल को हमें अपने परिवार और मित्रों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि समस्त संसार को प्रभु का एक कुटुंब मानते हुए सभी में इसे बांटना चाहिए।

आज सारे संसार में उथल-पुथल मची हुई है। अशांति और हिंसक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई बार लोगों को दुख में घिरा देखकर हम भी दर्द से भर जाते हैं। ऐसे समय में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये सब झगड़े-फसाद, संघर्ष, हिंसा और युद्ध आदि खत्म हों। दरअसल इन सभी समस्याओं का समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हम सबके भीतर मौजूद है। अगर हममें से प्रत्येक अपने अंतर में ध्यान-अभ्यास द्वारा शांति को प्राप्त कर ले, तब हम इसे औरों में भी फैला सकेंगे। इससे हममें से प्रत्येक व्यक्ति शांति का एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा और फिर धीरे-धीरे संपूर्ण विश्व में सुख-शांति फैल जाएगी।

संसार में शांति फैलाने के तरीकों में से एक है क्षमा। इसके लिए हमें बदले की भावना से ऊपर उठना होगा और दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखना होगा। संसार की बहुत सी समस्याएं बदले की भावना से शुरू होती हैं। इसमें एक व्यक्ति दूसरे को दुख पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उससे बदला लेना चाहता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। जब तक प्रतिशोध की यह भावना खत्म नहीं होगी और हम दूसरों को माफ करना नहीं सीखेंगे, तब तक विश्व में शांति की कामना नहीं कर सकते। प्रतिशोध की इस भावना को केवल क्षमा द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। ऐसा होने पर संसार में प्रेम और शांति का जीवन फिर से लौट सकता है। आइए क्षमा के इस गुण को हम अपने भीतर धारण करें, ताकि यह संसार शांति और प्रेम से भर जाए।

संत राजिंदर सिंह जी महाराज

# बेटियों की सुरक्षा का सवाल

नृपेंद्र अभिषेक नृप

**दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध से देश को मुक्ति दिलाने के लिए कानून और समाज दोनों को ही आगे आना होगा**

दिल्ली में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या का मामला सामने आया है। इस बार भी कुछ दल घटना को राजनीतिक और जातीय रूप देने लगे हैं। जब भी दुष्कर्म होता है, एक महिला के साथ होता है जाति और धर्म के साथ नहीं। ऐसे में चर्चा सिर्फ दुष्कर्म की होनी चाहिए जिससे कि भारत में दुष्कर्म मुक्त समाज की स्थापना हो सके। एनसीआरबी के अनुसार पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म का खतरा 44 फीसद तक बढ़ गया है। 2010 से 2019 के बीच भारत में दुष्कर्म के कुल 3,13,289 के मामले दर्ज हुए हैं। इससे देश में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को देखा जा सकता है। हाल में दुष्कर्म की घटनाओं पर गौर करें तो इसमें एक बात नई दिख रही है। अत्यधिक में साक्ष्य मिटाने के लिए लड़कियों को जलाया जा रहा है या उन्हें मारा जा रहा है। यह सब निर्भया कांड के बाद से ज्यादातर दिख रहा है। इसका कारण कानून में हुए बदलाव को माना जा रहा है। ऐसा दुष्कर्मी सुबूत मिटाने और खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। साफ है सिर्फ कठोर कानून इस समस्या का इलाज नहीं है।

मनोविज्ञानियों के अनुसार हमारे दिमाग की बनावट इस तरह की है कि बार-बार पढ़े, देखे, सुने या किए जाने वाले कार्यों और बातों का असर हमारी चिंतनधारा पर होता है। साथ ही यह हमारे निर्णयों और कार्यों का स्वरूप भी तय करता है। इसलिए पोर्न या सिनेमा और अन्य डिजिटल माध्यमों से परोसे जाने वाले साफ्ट पोर्न का असर हमारे दिमाग पर होता है। यह हमें यौन-हिंसा के लिए मानसिक रूप से तैयार और प्रेरित करता है। इसलिए अभिव्यक्ति या रचनात्मकता की नैसर्गिक स्वतंत्रता की आड़ में महिलाओं का वस्तुकरण करने वाली चीजों की वकालत करने से पहले हमें थोड़ा सोचना होगा। हमें अपने सामाजिक ताने-बाने को बदलने की भी जरूरत है। इसके लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों में महिलाओं के प्रति इज्जत का भाव बचपन से ही आए। सही शिक्षा और स्वस्थ माहौल तैयार करके ही हम उन्हें भविष्य के लिए एक बेहतर नागरिक के तौर पर तैयार कर सकते हैं।

आज अदालतों में केसों का अंबार लगा है। देश में न्याय की प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि पीड़ित हताश होने लगे हैं। हमें न्याय की प्रक्रिया को भी आसान करना होगा, तभी हर व्यक्ति को समय से न्याय मिल पाएगा। कोर्ट में दुष्कर्म के हजारों मामले दबे पड़े हैं। इनको जल्द-से-जल्द निपटाने की जरूरत है। मामलों में सजा सुनाई जाने लगेगी तो फिर अपराधियों में कानून का एक खौफ हो जाएगा। वे गुनाह करने से पहले सौ बार सोचेंगे। साफ है दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध से देश को मुक्ति दिलाने के लिए कानून और समाज दोनों को ही आगे आना होगा। एकजुट प्रयास से ही इस घृणित अपराध पर रोक लगाई जा सकती है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### हिंदी-अंग्रेजी दोनों की जरूरत

'अंग्रेजी के आगे भी भविष्य है' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भाषा की वकालत की है। देखा जाए तो वर्तमान में देश में हिंदी सिर्फ गर्व का विषय बनकर ही रह गई है। यह कामकाज और राष्ट्र की भाषा नहीं बन पाई है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की पढ़ाई हिंदी सहित 11 अन्य भाषाओं में होने की बात हो रही है, पर यह आधा सच है। बीटेक कोर्स का स्वरूप चार वर्ष का होता है। इनमें सिर्फ प्रथम वर्ष में पढ़ाई ही हिंदी में होगी, न कि पूरे चार वर्ष की। प्रथम वर्ष में इंजीनियरिंग का कोई कोर विषय नहीं होता। सभी ट्रेड के लिए लगभग समान विषय ही होते हैं, जो काफी हद तक 12वीं कक्षा के विषयों से मेल खाते हैं। इंजीनियरिंग के कोर विषयों की पढ़ाई द्वितीय वर्ष से शुरू होती है। इनकी पढ़ाई हिंदी में होनी जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि और हिंदी माध्यम से पढ़े छात्रों की असल दिक्कत तब शुरू होती है जब वे चैप्टर समझ तो जाते हैं, पर अंग्रेजी में लिख नहीं पाते। यहां तक कि सिविल सेवा की परीक्षा में भी हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। देश में न्याय भी अंग्रेजी में ही आता है। फिर लोग हिंदी की ओर क्यों भागेंगे जब सब कुछ अंग्रेजी से ही होना है। यही कारण है कि गांव में भी अब अंग्रेजी पर खास जोर दिया जाने लगा है। हालांकि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मातृ भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल है, जिसका स्वागत होना चाहिए। इससे हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं को जीवनदान मिलेगा। बहरहाल आज हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों की जरूरत है। अगर कोई भी एक कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। हिंदी की ओर झुकाव कम हुआ तो हम अपनी महान संस्कृति से दूर होंगे और अंग्रेजी से दूर हुए तो वैश्विक पहचान बनाने और विश्व स्तर पर अपनी बात रखने में दिक्कत होगी। इस कारण दोनों को साथ लेकर चलना होगा।

देवानंद राय, देवरिया

### चमकता सितारा नीरज

नीरज चोपड़ा ने वही किया है, जिसके लिए देश लंबे समय से इंतजार और दुआ कर रहा था। भारत के राष्ट्रगान और फहराए गए तिरंगे ने स्टेडियम में और बाहर भी हर भारतीय के दिल को गौरव से भर दिया। हर दिन के पसीने और संघर्ष की कहानी आखिरकार सफलता पर पहुंचकर ही रुकती है। भारत ने कुल सात पदक जीतकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार लड़कियों ने अपनी प्रतिभा का गजब का प्रदर्शन किया और दिखाया कि वे किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। भारोत्तोलन में मीरा बाई चानू से लेकर पीवी सिंधू तक महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य और रवि कुमार दहिया को रजत पदक मिला है। हम भी अपने कर्मों से इतिहास बना सकते हैं। जरूरत है कि हम कितना अपने लक्ष्य को लेकर समर्पित और गंभीर हैं।

अमन जायसवाल, दिल्ली

### खेलों में स्वर्णिम काल का आगाज

टोक्यो ओलंपिक में जाने से पहले और अपनी खेल प्रतियोगिताओं को खेलने के बाद चाहे हार हुई हो या जीत, प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों के साथ सकारात्मक संवाद निश्चित ही मनोबल को सातवें आसमान पर पहुंचाया है। इसी तरह चंद्रयान-2 मिशन की सितंबर 2019 में क्रैश लैंडिंग के बाद भी उदासी व भावुक क्षणों में प्रधानमंत्री का इसरो के चेयरमैन डा. के सिवन को न केवल ढांढस बंधाया, बल्कि विक्रम मिशन के लिए हौसलाअफजाई भी की। निःसंदेह देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री का सकारात्मक संवाद भविष्य की योजनाओं को और ताकत प्रदान करेगा। आज प्रधानमंत्री का खेलो इंडिया अभियान खिलाड़ियों में नई शक्ति का संचार पैदा कर रहा है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर का ट्वीट भारतीय खेलों का उपहास उड़ाता नजर आया। नीरज चोपड़ा का स्वर्णिम भाला फेंकना भारत में खेलों के लिए स्वर्णिम काल का आगाज है। नीरज चोपड़ा ने मेडल को फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। खेलों में राजनीति का प्रवेश पूर्णतया निषेध होना चाहिए जिससे खिलाड़ी हतोत्साहित न हो सकें।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए ... नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

**2005** में उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य देशभर में मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निपटारा करने के लिए समुचित पहल करना था।

मूल निवासी दिवस

# संस्कृति के विस्तार से आत्मनिर्भर होगा देश

**हमारा देश आर्थिक प्रगति की राह पर तेजी से अवश्य आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी विसंगति यह है कि हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें अपनी मूल संस्कृति से फिर से जुड़ना होगा जिससे हम धीरे-धीरे दूर होते गए हैं। साथ ही समाज में हाशिये पर खड़े लोगों को आर्थिक विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए हमें अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटना होगा और उसी अनुरूप कार्ययोजना तैयार करनी होगी, ताकि सभी को आत्मनिर्भर बनाया जा सके**

डा. अमृत कुल्लू
असिस्टेंट प्रोफेसर, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची

जब कभी आदिवासियों के विकास की बात होती है तब यह कहा जाता है कि आदिवासी संस्कृति में बदलाव कर उन्हें विकास की धारा से जोड़ा जा सकता है। ऐसे विचार आदिवासी विकास और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से हमें भटका रहे हैं। वास्तव में आदिवासी संस्कृति के विस्तार से ही आत्मनिर्भरता का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।

प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता है। प्रकृति के सान्निध्य में अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेना आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनाता है। पश्चिमी मुनाफाखोरी प्रवृत्ति के दबाव में अधिकांश आदिवासी समाज का नकारात्मक चित्रण कर आदिवासी समाज की विशिष्टता को हतोत्साहित कर सीमित करने का प्रयास किया गया है। आज अधिकांश लोगों के पास आदिवासी संस्कृति के सहभागी अवलोकन का अनुभव नहीं है तथा भ्रमित द्वितीयक सामग्री पर आधारित प्राप्त सूचना के आधार पर लोग आदिवासी संस्कृति में बदलाव कर उन्हें विकास की धारा से जोड़ने की बात करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि आदिवासी संस्कृति विकास की मुख्यधारा है तथा इसे अपना कर ही देश के विकास और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।

पूर्व तथा वर्तमान में विभिन्न सरकारों द्वारा विकास संबंधी कई योजनाओं का निर्माण किया गया, लेकिन आत्मनिर्भरता का लक्ष्य आज तक पूरा नहीं हो सका। ऐसे में इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि आदिवासी समाज तक सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की पहुंच अन्य समाज के मुकाबले न्यूनतम है। इसके बावजूद अन्य समाज की तुलना में आदिवासी समाज में आत्मनिर्भरता सर्वाधिक है। इसका मुख्य कारण आदिवासी संस्कृति की वह विशिष्टता है जिसके अंतर्गत विकास की रणनीति बाह्य पारिस्थितिकी तंत्र से प्रभावित न होकर स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र, सर्वसम्मति, स्वशासन और प्रकृति संवर्धन से प्रभावित होकर बनाई जाती है। अपनी संस्कृति में स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन को शामिल करना आदिवासी समाज को सतत विकास के साथ जोड़कर रखता है जिस कारण से वैश्विक आर्थिक मंदी जैसी स्थिति भी आदिवासी क्षेत्रों में न्यूनतम प्रभावी या अप्रभावी हो जाता है।

भारत में आत्मनिर्भरता का स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन समय के साथ बाह्य प्रभावों के कारण आत्मनिर्भरता धीरे-धीरे खत्म होती गई। वर्तमान स्थिति तो ऐसी हो गई है कि परिवार के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानीय सामाजिक संस्कृति नगण्य होती जा रही है, जबकि पश्चिमी संस्कृति ज्यादा प्रभावी रूप से दिखने लगी है। हमें यह समझना चाहिए कि संस्कृति ही किसी समाज को आत्मनिर्भर बनाती है तथा जिस किसी भी क्षेत्र में स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित संस्कृति की तुलना में बाह्य संस्कृति का ज्यादा प्रभाव होगा, उन क्षेत्रों में सरकार लगातार विकास की योजनाओं में आर्थिक निवेश कर भी आत्मनिर्भरता नहीं ला सकती है।

संस्कृति के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सांस्कृतिक तत्वों का संचार होता है तथा अगली पीढ़ी भी प्रकृति के सान्निध्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है। आदिवासी समाज में सांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया काफी प्रभावशाली रही है। आदिवासी समाज के कई ऐसे संस्थान हैं जिनके माध्यम से सांस्कृतिक संचार प्रभावी तरीके से किया जाता है। इन्हीं में से एक है- धुमकुड़िया। यह एक ऐसा मंच या संस्थान है जहां युवा शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से परिचित होते हैं। जब सांस्कृतिक गतिविधियों की बात होती है तो उसके अंतर्गत यहां आर्थिक गतिविधियां भी शामिल हैं। सामाजिक महत्व के विभिन्न विषयों पर चर्चाएं होती हैं। नृत्य और गायन भी इसका एक पक्ष है। यह सांस्कृतिक रूप से चली आ रही व्यवस्था है। सामाजिक सहयोग से यह संस्था चलती आ रही है। ऐसी संस्थाओं के माध्यम से समाज में एकता भी बढ़ती है, संस्कृति से युवाओं का परिचय भी होता है तथा आत्मनिर्भरता भी आती है। एक साथ बैठकर सामाजिक विषयों पर बातचीत करना तथा विकास से संबंधित अपने विचारों को प्रस्तुत करना युवाओं को अपने समाज से जोड़कर रखता है।

कुल मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र, समाज और स्वास्थ्य जैसे विषयों का अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त युवा किसी सरकार से मदद मांगने की बजाय स्वयं आत्मनिर्भर होने का गुण प्राप्त कर लेता है। अगर हम आदिवासी संस्कृति के धार्मिक स्थलों की विशिष्टता पर चर्चा करें तो आज भी यह समाज प्रकृति के ज्यादा नजदीक है। बड़े-बड़े विशालकाय भवनों के मुकाबले इस समुदाय में घने जंगल, पेड़, नदी और पहाड़ आदि को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सभी प्राकृतिक विरासतों का संवर्धन धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है।

सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो आदिवासी समाज की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। अगर नदी, जंगल, पहाड़ को पूजनीय माना गया है तो केवल इनकी पूजा ही नहीं की जाती, इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन भी प्रतिबद्धता के साथ किया जाता है। आदिवासी आंदोलनों के इतिहास को अगर पढ़ा जाए तो इन आंदोलनों में प्रकृति को बचाने से संबंधित आंदोलन प्रमुखता से सामने आते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आदिवासियों ने व्यक्तिगत स्वार्थ से ज्यादा प्रकृति को महत्ता दी जिससे पारिस्थितिकी तंत्र की परिधि में रहने वाला हर प्राणी आत्मनिर्भर हुआ।

आदिवासी संस्कृति से शिक्षा प्राप्त कर सरकार के द्वारा विकास संबंधी योजनाएं बनाई जाएंगी, तभी हमारा देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा देश में आर्थिक प्रगति तो हो सकती है, लेकिन आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है।

आदिवासी संस्कृति से आत्मनिर्भरता के मंत्र को सीखकर अन्य समाज में उसी अनुकूल तैयार की जाए बदलाव की रूपरेखा। फाइल

## यथार्थ के धरातल पर मूल निवासी दिवस

प्रवीण गुगनानी
वरिष्ठ स्तंभकार

भारतीय दलित और जनजातीय समाज में इन दिनों एक शब्द चलाया जा रहा है- मूल निवासी दिवस। दरअसल नौ अगस्त मूलतः पश्चिम के तथाकथित बुद्धिजीवी और प्रगतिशील समाज द्वारा किए गए बर्बर नरसंहार का दिन है, जिसे उसी पीड़ित व दमित जनजातीय समाज द्वारा गौरव दिवस रूप में मनवा लेने का षड्यंत्र है यह। आश्चर्य यह है कि पश्चिम जगत अपने विमर्श गढ़ लेने में माहिर छद्म बुद्धिजीवियों के भरोसे जनजातीय समाज के नरसंहार के इस दिन को जनजातीय समाज द्वारा ही गौरव दिवस के रूप में मनवाने के आपराधिक अभियान में सफल भी होता दिख रहा है।

आज का दिन अमेरिका, जर्मनी, स्पेन सहित उन सभी पश्चिमी देशों में बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा पश्चाताप, दुख और क्षमाप्रार्थना का दिन होना चाहिए। इस दिन यूरोपीय आक्रमणकारियों को उन देशों के मूल निवासियों से क्षमा मांगनी चाहिए जिनको उन्होंने बर्बरतापूर्वक नरसंहार करके उन्हें उनके मूल निवास से खदेड़ दिया था। पश्चिमी बौद्धिक जगत का प्रताप देखिए कि हुआ ठीक इसके विपरीत, उन्होंने इस दिन के मंतव्य व आशय को ही पूरी तरह से उलट दिया। हम भारतीय भी इस थोथे विमर्श में फंस गए। आज जिस 'वर्ल्ड इंडीजेनस डे' का आयोजन किया जाता है, उसका हमसे तो कोई सरोकार ही नहीं है। यदि जनजातीय दिवस मनाना ही है तो हमारे पास हजारों ऐसे जनजातीय योद्धाओं का समृद्ध इतिहास है जिन्होंने हमारे समूचे भारतीय समाज के लिए कई गौरवमयी अभियान चलाए। वस्तुतः इस पूरे मामले की जड़ बाबा साहब आंबेडकर के मत परिवर्तन के समय दो मतों- इस्लाम एवं ईसाई में व वामपंथ में उपजी निराशा में है। उन्होंने अपने अनुयायियों को इस्लाम व ईसाई मत से दूर ही रहने को कहा। किंतु आज मूल निवासीवाद के नाम पर भारत का दलित और जनजातीय समाज पश्चिमी व इस्लामिक षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। एकमुश्त मत परिवर्तन की आस में बैठे ईसाई मत प्रचारक व मुस्लिम नेता तक बहुत हताश हो गए थे, जब बाबा साहब आंबेडकर ने भारतीय भूमि पर जन्मे व भारतीय दर्शन आधारित धर्म में ही जाने का निर्णय लिया था। पश्चिमी ईसाई धर्म प्रचारकों के इसी षड्यंत्र का अगला क्रम है मूल निवासीवाद का जन्म! भारतीय दलितों व आदिवासियों को पश्चिमी अवधारणा से जोड़ने व भारतीय समाज में विभाजन के नए केंद्रों की खोज इस मूल निवासीवाद के नाम पर प्रारंभ कर दी गई है। इस पश्चिमी षड्यंत्र के कुप्रभाव में आकर कुछ दलित व जनजातीय नेताओं ने अपने आंदोलनों में यह कहना प्रारंभ कर दिया है कि भारत के मूल निवासियों (दलितों) पर बाहर से आकर आर्यों ने हमला किया और उन्हें अपना गुलाम बनाकर हिंदू वर्ण व्यवस्था को लागू किया। यह मूल निवासी दिवस मनाने का चलन उपजा क्यों व कहां से? यह दिवस पश्चिम के गोरों की देन है। कोलंबस दिवस के रूप में भी मनाए जाने वाले इस दिन को अंग्रेजों के अपराध बोध को स्वीकार करने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका से वहां के मूल निवासियों को बर्बरतापूर्वक समाप्त कर देने की कहानी के पश्चिमी पश्चाताप दिवस का नाम है मूल निवासी दिवस। इस दिवस के मूल में अमेरिका के मूल निवासियों पर जो बर्बर और पाशविक अत्याचार हुए और उनकी सैकड़ों जातियों को जिस प्रकार समाप्त कर दिया गया, वह मानव सभ्यता के शर्मनाक अध्यायों में शीर्ष पर है।

यह सिद्ध तथ्य है कि भारत में जो भी जातिगत विद्वेष और भेदभाव चला वह जाति व जन्म आधारित है, क्षेत्र आधारित नहीं। वस्तुतः इस मूल निवासी के फंडे पर आधारित यह नई विभाजनकारी रेखा एक नए षड्यंत्र के तहत भारत में लाई जा रही है जिससे भारत को पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है।

खरी-खरी

## ओलिंपिक से उपजा दर्शन

डा. अतुल चतुर्वेदी

वो ओलिंपिक से लौटे थे। ओलिंपिक में पसीना बहाने की थकान उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। हालांकि पसीना हमेशा की तरह खिलाड़ियों ने बहाया था, परंतु थकान ओढ़ना अधिकारी का दस्तूर होता है। मैंने कहा- इस बार तो थोड़ा ठीक रहा प्रदर्शन। वे बोले- हां। मैंने कहा- फिर इतना निराश क्यों दिख रहे हैं आप? हाकी में काफी सुधार हुआ है।

इस बार वो उत्साह से भर कर बोले हर टीम को चाहिए एक पुरुषोत्तम नवीन। अब कारपोरेट भी क्रिकेट भक्ति छोड़ें तो बात बने। मैंने कहा- लगता है भारतीय हाकी का स्वर्ण युग लौटेगा? वो हंसे, कहने लगे- अभी तो कांस्य युग लौट रहा है। आज के प्रतियोगी परिवेश में यह क्या कम है? पास में ही तीरंदाजी के खिलाड़ी खड़े थे। आप लोग कैसे चूक गए? वे शर्माए, चूके कहां? थोड़ा हाथ हिल गया बस... कुछ हवा भी तेज थी, और मन भी एकाग्र कम हो पाया। मैंने चुटकी ली- अर्जुन और कर्ण के देश में तीर के निशाने चूकना कुछ कम जमता है। जबकि हमारे यहां तो निशानेबाजी का अद्भुत माहौल है। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, कुछ उनसे ही प्रेरणा ले लेते। खिलाड़ी सकुचा कर बोला- उनसे क्या प्रेरणा लें, उनके तीर कहीं होते हैं, निशाना कहीं और। हमारी स्पर्धाएं स्वस्थ होती हैं, वहां मनोविकार नहीं होता।

मैं मुक्केबाज जी की तरफ मुखातिब हुआ... आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस घूंसे मुंह पर नहीं लगे और फिटनेस का लेवल हमारा कमजोर था दूसरों से। वो कहने लगा, खिलाड़ी हैं सर, नेता नहीं। प्रदर्शन में सुधार करते हैं दूसरों को टंगड़ी नहीं मारते। गिरा के दौड़ जीती तो क्या, हरा कर जीतो। मैं खिलाड़ी के दर्शन से प्रभावित हुआ। इस बीच अधिकारी जी हस्तक्षेप करते हुए कहने लगे- भाईसाहब आप तो जानते हो मेहनत तो हमारे बच्चे बहुत करते हैं, लेकिन क्षेत्रीयतावाद और राजनीति की खरपतवार के कारण हौसले पस्त हो जाते हैं। अब देखिए न लोग सिंधु और चानू की जाति टटोल रहे हैं जैसे कोई उनसे रिश्ते जोड़ने हों। जबकि हमारे यहां तो पहले ही कहा गया है जाति न पूछो साधु की। फिर भी लोग मानते नहीं हैं।

## ट्वीट-ट्वीट

भारतीय सेना ने देश को कभी भी निराश नहीं किया है। मेजर ध्यानचंद से लेकर सूबेदार नीरज चोपड़ा तक इसकी उम्दा मिसाल हैं।
गौरव सी सावंत@gauravcsawant

जीतने वालों को नकदी प्रोत्साहन अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने ओलिंपिक में भाग लिया और पदक नहीं जीत पाए, उन्हें और उनके कोचों को भी नकद प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि उनका हौसला न टूटे।
विजेंदर सिंह@boxervijender

विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भारत की बढ़ी मौजूदगी और कई मौकों पर मामूली अंतर से पदक चूकना भारत के लिए खेलों में बेहतर भविष्य की ओर संकेत करता है। इससे लाखों बच्चे प्रेरित होंगे। खेलो इंडिया।
प्रो. शमिका रवि@ShamikaRavi

हमने पहले दिन मीराबाई चानू की चांदी से आगाज किया तो समापन नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक स्वर्ण के साथ। भारतीय खेलों में इस महान अवसर का साक्षी बनकर अच्छा महसूस हुआ। सभी खिलाड़ियों का आभार।
विजय लोकपल्ली@vijaylokapally

अब तमाम ब्रांड हमारे खिलाड़ियों की सफलता भुनाने को आतुर हैं जबकि कुछ गिने-चुने नाम ही ऐसे होंगे, जिन्होंने संघर्ष के दौरान इन खिलाड़ियों की मदद की होगी। ऐसे में जरूरत है कि कंपनियां और ब्रांड शुरुआती स्तर से ही खिलाड़ियों की सहायता के लिए आगे आएं।
अरविंद गुप्ता@buzzindelhi

## जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या पूर्वी लद्दाख के गोगरा में सैन्य गतिरोध हल होने के बाद चीन पर भरोसा किया जा सकता है?**

**आज का सवाल**

टोक्यो ओलिंपिक के प्रदर्शन से देश में एक नई खेल संस्कृति विकसित होने की उम्मीद बंधी है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

## जनपथ

अच्छा है जो हो रही पैसों की बरसात,
लेकिन होनी चाहिए एक नई शुरुआत।
एक नई शुरुआत ढूंढ़िए नए खिलाड़ी,
करिए उस पर खर्च सभी मिल बारी-बारी।
तभी चैंपियन रूप धरेगा बच्चा-बच्चा,
अरु मेडल का बोर्ड लगेगा सचमुच अच्छा!
- ओमप्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश डायरी

# मुफ्त राशन दे परिवारों को बिखरने से बचाया

राजू मिश्र
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मासिक चक्र के शुभारंभ पर पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इस योजना के जरिये करीब 15 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रत्येक परिवार को हर माह पांच किलो चावल/गेहूं दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में उचित दर की 80 हजार दुकानें चिन्हित की गई हैं। इसका मकसद गरीबों और मजदूरों को समय पर और पर्याप्त रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें परेशानियों से मुक्त किया जा सके।

इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के पांच लाभार्थियों से संवाद भी किया। संवाद का मकसद यह जानना भी था कि प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है या नहीं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की बदामी देवी से जानकारी चाही तो उन्होंने साफ कहा कि सब सुविधाएं मिल रही हैं। मड़ई (छप्पर) से पक्का घर हो गया। हर महीने राशन मिल रहा है। बिजली, गैस भी प्राप्त हो रही है। सहारनपुर की कमलेश ने भी कहा कि उन्हें राशन लगातार मिल रहा है। इसी तरह झांसी के पंकज सहगल ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना ने आर्थिक रूप से परेशान कर दिया, लेकिन सरकार ने मुफ्त राशन देकर परिवार को बिखरने से बचाया है। सुलतानपुर की बबीता और कुशीनगर की अमलावती का भी कुछ ऐसा ही कहना था। सभी ने सरकार के प्रयास को सराहा।

अन्न महोत्सव के जरिये राशन बांटने की जो शुरुआत की गई है, वह सराहनीय है। इसकी वजह यह है कि कोरोना की इस महाविपत्ति के समय पर सबसे ज्यादा कहर मजदूर पेशा वर्ग पर ही टूटा है, जिनके लिए रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीने जैसी स्थिति है। वे न तो लंबे समय के लिए घर में राशन का इंतजाम कर सकते हैं और न ही इतना पैसा होता है कि जब जो जरूरत हो उसे खरीद लें, ऐसे में सरकार की ओर से वितरित निशुल्क राशन ही इनका सबसे बड़ा सहारा बना है। समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंच कर सरकार ने जो प्रयास किया है निश्चित रूप से उससे करोड़ों लोगों के घरों में चूल्हा जलने का इंतजाम किया गया है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली से भेजे गया हर दाना आज लाभार्थियों की थाली तक पहुंच रहा है। पूर्व की सरकारों के समय प्रदेश में गरीबों के अनाज के साथ जो लूट मचती थी, अब वह रास्ता बंद हो चुका है। लाभार्थियों की संख्या न केवल बढ़ी है, बल्कि उन्हें राशन भी समय से उपलब्ध होने लगा है। अब जो अन्न महोत्सव शुरू हुआ है, वह गरीबों के लिए लाभकारी साबित होगा।

वाराणसी के भीषमपुर में निशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आनलाइन संवाद करतीं बदामी देवी। उत्तम राय चौधरी

**बड़े काम का सिटीजन चार्टर :** प्रदेश जल्द ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है। यहां 15 अगस्त से 58,189 ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू होने जा रहा है। सिटीजन चार्टर लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, ग्रामीणों को तमाम सेवाएं समयबद्ध ढंग से मिलने लगेंगी। ये ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए पहले ग्रामीणों को न केवल महीनों लग जाते थे, बल्कि संबंधित अफसरों, कर्मचारियों की रिश्वतखोरी का भी शिकार होना पड़ता था। 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार-जनसेवाएं हमारे द्वार' अभियान से सरकार के इस प्रयास को और गति मिलेगी। पंचायत विभाग ने जो माडल सिटीजन चार्टर तैयार कराया है, उसमें अभी 39 जनसुविधाओं का उल्लेख है, जिसे पंचायतें अपने संसाधनों के हिसाब से लागू करेंगी, लेकिन यदि यह पूरी तरह से सफल रहा है तो जनसुविधाओं की सूची और लंबी हो सकती है। इन सारी कवायद का एक ही मकसद है गांव की सरकार को आमलोगों के प्रति जवाबदेह बनाना। समस्या का निस्तारण निर्धारित अवधि के भीतर करना मजबूरी हो जाने से भ्रष्टाचार के अवसर काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। सरकार ने आमजन के हित में जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, वे निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी हैं, लेकिन व्यवहार में देखा यही गया है कि चाहे जितनी भी पुख्ता व्यवस्था सरकार कर ले, भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर उसमें भी कोई न कोई रास्ता खोज लेते हैं। इन सारे रास्तों को बंद करना पड़ेगा। इसका एक तरीका यह है कि इन मामलों में भ्रष्टाचार करने वालों को कठोर दंड निर्धारित कर दिए जाएं ताकि उनके सामने बचाव का कोई रास्ता न हो। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए आम जनता को अपना व्यथा बताने के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाए, साथ ही उन समस्याओं का निस्तारण भी प्रभावी और समयबद्ध ढंग से हो।

मंथन

# पंचायती मध्यस्थता की राजनीति

**विवादों को निपटाने में आम तौर पर पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। लिहाजा त्वरित और निशुल्क न्याय की इस परंपरा से सामान्य जन का सरोकार बना रहेगा**

कौशल किशोर
सामाजिक मामलों के जानकार

मीडिया की चकाचौंध से दूर रहने वाले न्यायमूर्तियों को बीती सदी के ब्रिटेन के जाने-माने न्यायाधीश लार्ड अल्फ्रेड डेनिंग ने सबसे बेहतर बताया था। उनकी इस उक्ति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना एक किताब के विमोचन समारोह के दौरान उद्धृत करते हैं। यह और बात है कि मीडिया की सुर्खियों से उन्हें कितना लगाव है। उन्होंने दावा किया है कि देश के लोगों को भरोसा है कि न्यायपालिका से उन्हें राहत और न्याय मिलेगा। इसी के साथ लोकतंत्र का संरक्षक होने के नाते जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट लोगों के साथ खड़ा होता है। पिछले साल लाकडाउन के बाद राहत व न्याय की आशा में देश की राजधानी के श्रमिक यदि सुप्रीम कोर्ट का रुख करते तो इन पर कोई आपत्ति भी नहीं करता। हैरत होती है कि वक्त गंवाए बगैर अपने गांवों की ओर पैदल कूच करने वाले लाखों लोगों की व्यथा का स्वतः संज्ञान लेने वाला न्याय के इस मंदिर में कोई नहीं था। एक ऐसे दौर में जब न्याय के बदले फैसले को वरीयता मिलती हो, पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन की बात स्मृति पटल पर उभरती है। उन्होंने न्याय के मंदिर को ईबादतघर न मानकर जुआखाना कहा था। पिछले दो दशकों में न्यायालयों की दशा सुधर गई हो, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ऐसी दशा में यही प्रतीत होता है कि न्यायपालिका के सर्वोच्च आसन पर बैठ कर साधनविहीन श्रमिकों को देश की परिधि से ही बाहर कर दिया गया।

इस कड़ी में जस्टिस रमना द्वारा विभिन्न अवसरों पर मध्यस्थता के माध्यम से विवाद निस्तारण की बात पर विमर्श आवश्यक है। उन्होंने भारत-सिंगापुर मीडिएशन समिट में मध्यस्थता के माध्यम से वाद निस्तारण की पहल पर बल दिया था। इस नीति को अमल में लाने के लिए ही 2005 में उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष कमेटी का गठन किया था। पिछले एक दशक से यह मध्यस्थों के प्रशिक्षण का काम भी करती है। एक संबंधित कार्यक्रम के दौरान हाल में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित उस मिथक पर प्रहार किया, जो यह बताता है कि न्याय की प्राप्ति काले कोट और लंबी चौड़ी जिरह के बिना संभव नहीं है। इसी मौके पर उन्होंने अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में प्रचलित मध्यस्थता की रीति का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाला कल मध्यस्थता के नाम है।

मुगलों और अंग्रेजों के आगमन से पहले भारतवर्ष में न्याय हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार रहा। न्याय की भारतीय परंपरा को पंचायत के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था में सत्य और गुण-धर्म की परख करने में सक्षम पांच लोग मिल कर न्याय सुनिश्चित करते हैं। इनमें पक्षकारों द्वारा नामित सदस्य विवाद से जुड़े तथ्यों से वाकिफ मध्यस्थ ही होते हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लेने की इस परंपरा का उद्भव इसी जमीन पर हुआ। इसलिए इसे भारतीय न्याय व्यवस्था कहते हैं। पंचायत का नाम लिए बगैर मध्यस्थता की भारतीय परंपरा की पैरवी करने वाले अपनी राजनीति स्वयं ही उजागर कर देते हैं।

न्याय व्यवस्था की खामियों का ही परिणाम है कि निचली अदालतों के फैसले पर अपील की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय तक पहुंच जाती है। इसके लिए जहां न्याय के बदले फैसले की नीति जिम्मेदार है, वहीं विवाद निस्तारण में होने वाली देरी का एक कारण यह भी है। देशभर के न्यायालयों में लंबित मुकदमों की बात भी किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रख कर सामाजिक-आर्थिक मजबूरी का जिक्र कर विवाद निस्तारण के लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाने की बात कही जो तीव्र हो और कम खर्च पर सहज ही सुलभ होती हो। आम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने का हरसंभव प्रयास करते हैं। इन्हीं लोगों के बीच न्याय पंचायत की स्वदेशी परंपरा आज भी शेष बची हुई है।

पंचायत की मध्यस्थता का वर्णन हमारी लोक कलाओं और साहित्य में भी मिलता है। फाइल

न्यायपालिका की जिन खामियों को दूर करने के लिए उन्होंने मध्यस्थता की पैरवी की है, पश्चिम में न्याय की भदेस संस्कृति की उदारता का जिक्र करने वाले इन्हीं खूबियों को चिन्हित करते रहे हैं। न्याय की इस पवित्र परंपरा की खिलाफत करने वाले लोग वस्तुतः कानून को धनोपार्जन का जरिया मानते हैं। कुदरत का कानून इस व्यवस्था से पृथक है। न्याय की पंचायती परंपरा में यह मौलिक भेद है। वृक्ष की घनी छांव में जमा होकर पंचों को न्याय करने हेतु किसी भवन तक की जरूरत नहीं पड़ी। न्याय की उदात्त परंपरा के कारण पंच को परमेश्वर तक माना गया। इस परंपरा से सामान्य जन का सरोकार मिटने वाला नहीं है।

यह व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के युग में सिकुड़ती प्रतीत होती है। विकास के लिए नेहरू द्वारा बनाए गए ब्लाक की व्यवस्था को केंद्र में रखकर तब पंचायत की नई परिभाषा गढ़ी गई थी। लोकतंत्र की आधुनिक अवधारणा और पंचायत की पुरानी परंपरा दो विपरीत ध्रुवों पर है। बीसवीं सदी से ही इसका राजनीतिक दर्शन भी मौजूद है। इसे समझने के लिए महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया 'हिन्द स्वराज' पढ़ना चाहिए।

जस्टिस रमना अपने उद्बोधन के समापन में गांधी को उद्धृत करते हैं। दो दशकों की वकालत के दौरान गांधीजी ने सैकड़ों मुकदमे का समाधान मध्यस्थता के जरिये से किया। दोनों पक्षकारों के बीच की खाई को पाटने का काम वकील की वास्तविक जिम्मेदारी है।

### अगले हफ्ते आएंगे चार आइपीओ

नई दिल्ली : अगले हफ्ते बाजार में चार कंपनियों के आइपीओ आएंगे। इनसे कुल 14,628 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास रहेगा। इनमें नुवोको विस्तास कारपोरेशन, कारट्रेड टेक, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस और केमप्लास्ट सनमार शामिल हैं। चार कंपनियों देवयानी इंटरनेशनल, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, बिंडलास बायोटेक एवं एक्सारो टाइल्स ने पिछले हफ्ते आइपीओ के जरिये 3,614 करोड़ जुटाए थे। (प्रेट्र)

ओएनजीसी अपने अनूठे सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत हथकरघा को प्रोत्साहित कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दे रही है। कौशल आधारित प्रशिक्षण देश में हाशिए पर जी रहे वर्ग को सशक्त करने की दिशा में अहम है।
– तरुण कपूर, पेट्रोलियम सचिव

# डिस्काम को 90,000 करोड़ का नुकसान

## कोरोना का दुष्प्रभाव : नीति आयोग की सिफारिश, डिस्काम को मिलनी चाहिए पूरी स्वायत्तता

राजीव कुमार • नई दिल्ली

पहले से ही वित्तीय दबाव में चल रही राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) का नुकसान कोरोना के कारण लगातार बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक, इस साल मार्च तक विभिन्न डिस्काम का नुकसान 90,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। इस नुकसान के चलते डिस्काम बिजली उत्पादक कंपनियों का बकाया चुकाने में असमर्थ हैं। मार्च के अंत तक विभिन्न डिस्काम पर बिजली उत्पादक कंपनियों का 67,917 करोड़ रुपये का बकाया था। हालात यह है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य सरकारों की तरफ से संचालित डिस्काम पर छह लाख करोड़ रुपये के कर्ज हो जाएंगे। कोरोना की वजह से उपभोक्ता एवं व्यावसायिक बिजली की मांग में कमी आई और पहले से बकाया राशि की भी वसूली नहीं हो पा रही है। इससे बिजली वितरण कंपनियों का घाटा बढ़ता गया। डिस्काम पर नीति आयोग की रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई है। हालांकि निजी डिस्काम का प्रदर्शन बेहतर है।

नीति आयोग ने कहा है कि डिस्काम की सफलता तभी संभव है, जब उसे वित्तीय व संचालन दोनों मामलों में स्वायत्तता दी जाए। डिस्काम और सरकार के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। आयोग ने डिस्काम की सफलता के लिए फ्रेंचाइजी माडल भी अपनाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी और ओडिशा में फ्रेंचाइजी माडल से डिस्काम के नुकसान को कम करने में सफलता मिली है। इसके अलावा एक इलाके में कई डिस्काम के लिए लाइसेंस जारी करने, उनके बीच आपस में प्रतिस्पर्धा से बिजली खरीद की लागत को कम करने की सिफारिश भी की गई है।

डिस्काम की संचालन लागत में 77% लागत बिजली खरीद की है। राज्यों की डिस्काम पुराने समय से चले आ रहे पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के तहत बिजली की खरीद कर रही हैं, जबकि पावर एक्सचेंज पर सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध होती है। रिपोर्ट में यह भी कहा है कि भारत के बिजली सेक्टर को विश्व के सबसे बड़े और जटिल सेक्टर में शुमार किया जाता है। ऐसे में, बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए घरेलू स्तर पर विकसित लचीले उपाय करने होंगे, जिसे राज्य और केंद्र की राजनीतिक इच्छाशक्ति का समर्थन हो।

**कहीं फायदा, कहीं नुकसान :** नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, निजी इकाइयों द्वारा संचालित डिस्काम लाभ कमा रही हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में दिल्ली की तीनों निजी डिस्काम के साथ सूरत की डिस्काम ने लाभ अर्जित किया। वहीं इस अवधि में बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल की सरकारी डिस्काम ने भारी नुकसान उठाया। हालांकि गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों की डिस्काम को इस अवधि में मुनाफा हुआ।

**68,000**
करोड़ रुपये बकाया हैं राज्यों के डिस्काम पर बिजली उत्पादक कंपनियों के

**सरकारी डिस्काम पर बिजली उत्पादक कंपनियों का बकाया**

| राज्य | बकाया |
|---|---|
| तमिलनाडु | 14,123 करोड़ |
| राजस्थान | 10,261 करोड़ |
| महाराष्ट्र | 10,021 करोड़ |
| उत्तर प्रदेश | 5,685 करोड़ |
| तेलंगाना | 5,000 करोड़ |
| जम्मू-कश्मीर | 4,827 करोड़ |
| आंध्र प्रदेश | 4,771 करोड़ |
| झारखंड | 4,349 करोड़ |
| कर्नाटक | 3,246 करोड़ |
| मध्य प्रदेश | 1,515 करोड़ |
| अन्य राज्य | 4,118 करोड़ |

**राज्यों का एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लास** (एटीएंडसी लास) (वित्त वर्ष 2018-19)

| राज्य | लास |
|---|---|
| बिहार | 30.9 फीसद |
| उत्तर प्रदेश | 33.2 फीसद |
| मध्य प्रदेश | 36 फीसद |
| राजस्थान | 28.3 फीसद |
| पंजाब | 11.3 फीसद |
| दिल्ली | 9.2 फीसद |
| उत्तराखंड | 16.2 फीसद |
| झारखंड | 28.6 फीसद |
| हरियाणा | 18.1 फीसद |

स्रोत : नीति आयोग की रिपोर्ट

## रेडी टु कुक इडली, डोसा, दलिया मिक्स पर 18 फीसद जीएसटी प्रभावी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पाउडर के रूप में बिकने वाली रेडी टू कुक डोसा, इडली, दलिया मिक्स जैसी खाद्य वस्तुओं पर 18 फीसद जीएसटी लगेगा। बैटर के रूप में बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं पर दर पांच फीसद होगी। अथारिटी फार एडवांस रूलिंग (एएआर) की तमिलनाडु पीठ ने यह व्यवस्था दी है। कृष्णा भवन फूड्स एंड स्वीट्स ने एएआर के समक्ष याचिका दी थी, जिसमें किसी ब्रांड नाम के तहत बेचे जाने वाले बाजरा, ज्वार, रागी व मल्टीग्रेन दलिया मिक्स जैसे 49 उत्पादों पर लागू जीएसटी दर को लेकर फैसले की अपील की गई थी। एएआर ने कहा, कंपनी द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद चूर्ण के रूप में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। डोसा मिक्स और इडली मिक्स को पैक करके मिक्स के रूप में बेचा जाता है। यह पाउडर के रूप में होता है, बैटर नहीं। सभी 49 उत्पाद जिनके लिए फैसला सुनाने की मांग की गई है, सीटीएच 2106 के तहत वर्गीकृत हैं। इन पर लागू होने वाली दर नौ फीसद केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और नौ फीसद राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) है।'

# नौ कंपनियों का एम-कैप 2.22 लाख करोड़ बढ़ा

सबसे ज्यादा फायदा टीसीएस को, बजाज फाइनेंस के बाजार मूल्यांकन में गिरावट आई

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले हफ्ते घरेलू शेयर बाजारों में जबर्दस्त उछाल के दम पर शीर्ष 10 में से नौ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) में बढ़त दर्ज की गई। इन कंपनियों का एम-कैप संयुक्त रूप से 2,22,591.01 करोड़ रुपये बढ़ गया। केवल बजाज फिनसर्व के एम-कैप में गिरावट दर्ज की गई।

आंकड़ों के मुताबिक, टीसीएस का एम-कैप सर्वाधिक 52,766.97 बढ़कर 12,24,441.49 करोड़ हो गया। एचडीएफसी बैंक का एम-कैप 37,563.09 करोड़ बढ़कर 8,26,332.67 करोड़, एचडीएफसी का 34,173.81 करोड़ रुपये बढ़कर 4,74,912.16 करोड़ रुपये, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) का 34,011.11 करोड़ बढ़कर 13,24,341.36 करोड़, कोटक महिंद्रा का 24,585.18 करोड़ बढ़कर 3,52,708.11 करोड़, इन्फोसिस का 17,078.94 करोड़ बढ़कर 7,02,898.22 करोड़, आइसीआइसीआइ बैंक का एम-कैप 10,181.46 बढ़कर 4,83,030.92 करोड़ रुपये और एचयूएल का पूंजीकरण 8,705.23 करोड़ रुपये बढ़कर 5,57,111.01 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बीते हफ्ते बजाज फाइनेंस का बाजार मूल्यांकन 344.05 करोड़ रुपये गिरकर 3,75,628.83 करोड़ रुपये पर आ गया। शीर्ष 10 कंपनियों में क्रमशः रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचयूएल, आइसीआइसीआइ बैंक, एचडीएफसी, स्टेट बैंक आफ इंडिया, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक के नाम शामिल हैं।

एचडीएफसी बैंक का एम-कैप 37,563.09 करोड़ रुपये बढ़कर 8,26,332.67 करोड़ पर पहुंच गया • फाइल फोटो

# आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी बाजार की नजर

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस हफ्ते घरेलू शेयर बाजारों की चाल कंपनियों के तिमाही नतीजों, वृहद आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक ट्रेंड पर निर्भर करेगी। जून के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े और जुलाई की महंगाई दर की रिपोर्ट इस हफ्ते जारी होनी है। पिछले दिनों अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई का अनुमान 5.1 फीसद से बढ़ाकर 5.7 फीसद कर दिया था।

सैमको सिक्युरिटीज की इक्विटी रिसर्च हेड निराली शाह ने कहा, 'इस हफ्ते सबकी नजरें कुछ अहम आर्थिक आंकड़ों और कंपनी नतीजों पर रहेंगी। हालांकि बाजार में तेजी का रुख बने रहने की उम्मीद है।' इस हफ्ते एमआरएफ, एमटेक आटो, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ल्यूपिन, आयशर मोटर्स, टाटा स्टील, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, एनबीसीसी और ओएनजीसी के तिमाही नतीजे आने हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, 'इस हफ्ते महंगाई दर और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े दो बड़े कारक हैं, जिन पर निवेशकों की निगाह रहेगी।' विदेशी संस्थागत निवेशकों का रुख, कच्चे तेल की कीमतें और डालर के मुकाबले रुपये की कीमत भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित करेगी। पिछले हफ्ते बीएसई का सेंसेक्स 1,690.88 अंक बढ़कर 54,277.72 पर बंद हुआ था। इससे पहले पांच अगस्त को यह अपने सर्वोच्च स्तर पर बंद हुआ था। जानकारों का कहना है कि शिखर पर चल रहे बाजारों में इस हफ्ते उठापटक देखने को मिल सकती है।

**शेयर समीक्षा**

- एमआरएफ और जिंदल स्टील समेत कई बड़ी कंपनियां जारी करेंगी नतीजे
- औद्योगिक उत्पादन व महंगाई के आंकड़े भी निवेशकों की धारणा करेंगे प्रभावित

### एफपीआइ ने भारतीय बाजारों में डाले 1,210 करोड़ रुपये

विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों में भरोसा बढ़ा है। अगस्त के पहले पांच करोबारी सत्र यानी दो से छह अगस्त के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने इक्विटी बाजार में 975 करोड़ रुपये और डेट सेग्मेंट में 235 करोड़ रुपये डाले। इस तरह अगस्त में अब तक एफपीआइ 1,210 करोड़ रुपये के शुद्ध निवेशक रहे हैं। जुलाई में एफपीआइ ने 7,273 करोड़ रुपये की निकासी की थी।

## नियमों के उल्लंघन के 94 नए मामलों में सेबी ने जांच शुरू की

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वित्त वर्ष 2020-21 में सिक्युरिटीज से जुड़े नियमों के उल्लंघन के 94 नए मामलों की जांच शुरू की। यह आंकड़ा इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 42 फीसद कम है। सेबी की ताजा वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ये मामले बाजार में गड़बड़ी और कीमतों से छेड़छाड़ से जुड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2020-21 ऐसे 140 मामलों की जांच पूरी हुई और 94 नए मामलों की जांच शुरू की गई। 2019-20 में 161 नए मामलों की जांच शुरू हुई थी तथा 170 मामलों की जांच पूरी की गई थी। बीते वित्त वर्ष में कुल नए मामलों में 43.6% बाजार में गड़बड़ी तथा कीमतों से छेड़छाड़ के थे। 31% मामले भेदिया कारोबार और तीन फीसद मामले अधिग्रहण नियमों के उल्लंघन के थे।

# चार लाख तक पहुंच गया ब्रिटेन का हवाई किराया

आइएएस ने की शिकायत, डायरेक्टरेट जनरल आफ सिविल एविएशन ने कंपनियों से मांगी जानकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना काल में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रूट पर फ्लाइट टिकट के दाम आश्चर्यजनक रूप से बढ़े हैं। 26 अगस्त के लिए दिल्ली से लंदन तक इकोनामी क्लास में ब्रिटिश एयरवेज का एक तरफ का किराया 3.95 लाख रुपये पहुंच गया है। ट्विटर पर आइएएस अधिकारी संजीव गुप्ता की शिकायत के बाद विमानन नियामक डायरेक्टरेट जनरल आफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने कंपनियों से किराए की जानकारी मांगी है। आमतौर पर दिल्ली से लंदन इकोनामी क्लास का किराया 70 से 80 हजार रुपये रहता है।

गृह मंत्रालय के इंटर-स्टेट काउंसिल सेक्रेटरिएट के सचिव संजीव गुप्ता ने शनिवार को शिकायत करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश एयरवेज एक तरफ के लिए 3.95 लाख दिखा रहा है। विस्तारा और एयर इंडिया भी 26 अगस्त के लिए 1.2 लाख से 2.3 लाख के बीच किराया वसूल रहे हैं। यह भारी भरकम किराया ऐसे समय में वसूला जा रहा है, जब ब्रिटेन के कालेजों में प्रवेश शुरू हो गए हैं। अपने मेरिट के दम पर वहां किसी कालेज में प्रवेश के लिए चुने गए छात्र के लिए भारी-भरकम किराया किसी सजा जैसा है। डीजीसीए के अधिकारी ने बताया कि नियामक ने विमानन कंपनियों से भारत-ब्रिटेन के बीच की फ्लाइट टिकट की विस्तृत जानकारी देने को कहा है। घरेलू उड़ानों के लिए पिछले साल 25 मई को न्यूनतम और अधिकतम हवाई किराए की सीमा तय कर दी गई थी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

### विस्तारा ने कहा, मांग और आपूर्ति से तय होता है किराया

दिल्ली-लंदन और मुंबई-लंदन रूट पर फ्लाइट संचालित करने वाली विस्तारा ने किराए के सवाल पर कहा, 'टिकट का दाम आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। अभी भारत-ब्रिटेन के बीच हफ्ते में मात्र 15 उड़ानों की अनुमति है। जैसे-जैसे उड़ानें बढ़ेंगी और ज्यादा क्षमता के साथ उड़ान की अनुमति मिलेगी, किराए नीचे आ जाएंगे।' भारत में पिछले साल 23 मार्च से शेड्यूल्ड अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं। जुलाई, 2020 से ब्रिटेन समेत दो दर्जन से ज्यादा देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत सीमित उड़ानें संचालित की जा रही हैं। एयर बबल दो देशों के बीच की वह व्यवस्था है, जिसमें वे एक-दूसरे के यात्रियों को हवाई यात्रा की अनुमति देते हैं।

### कोरोना काल में केंद्र बनाए ट्रैवल बुकिंग रिफंड पालिसी

देश में 90 फीसद लोग मानते हैं कि कोरोना काल में ट्रैवल बुकिंग कैंसलेशन पर रिफंड के मामले में सरकार पालिसी बनाए। आनलाइन प्लेटफार्म लोकल सर्किल्स के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। 359 जिलों में 37 हजार से ज्यादा लोगों के बीच यह सर्वेक्षण किया गया। बहुत से ट्रैवल एजेंट, होटल और विमानन कंपनियां यात्रा रद कराने पर कोई रिफंड नहीं देते हैं। सर्वेक्षण में शामिल 95 फीसद लोगों ने कहा कि कंपनियों की मौजूदा नीतियां उपभोक्ता के हित में नहीं हैं। लोगों का कहना है कि कम से कम महामारी के इस दौर में नागरिक उड्डयन, पर्यटन, रेलवे या गृह मंत्रालय इस संबंध में नीति बनाएं।

## राष्ट्रीय फलक

# ओलिंपिक में हरियाणा के पदक दूसरे राज्यों को करेंगे प्रोत्साहित

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

टोक्यो ओलिंपिक में पदकों की उपलब्धि में हरियाणा के खिलाड़ी काफी आगे रहे हैं। 127 सदस्यीय भारतीय दल में सबसे ज्यादा 31 खिलाड़ी हरियाणा के थे, जिन्होंने आठ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। देश को मिले सात पदकों में व्यक्तिगत स्पर्धा में तीन पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। एकमात्र स्वर्ण पदक भी इसी राज्य के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता है। पुरुष हाकी टीम में दो खिलाड़ी सुरेंद्र सिंह और सुमित कुमार हैं तो महिला टीम की सात खिलाड़ी यहां से हैं।

इस शानदार प्रदर्शन के पीछे खिलाड़ियों की मेहनत व समर्पण के साथ-साथ उन्हें प्रोत्साहित करने वाली हरियाणा की खेल नीति को अहम माना जा रहा है। राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मानते हैं कि इस उपलब्धि में राज्य की खेल प्रोत्साहन नीति एक बड़ा कारक है। वे कहते हैं हम केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष भी यह प्रस्ताव रखेंगे। रोहतक से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस तरह की नीति केंद्रीय स्तर पर बने।

खेल में बेहतर अवसर : दुष्यंत चौटाला। फाइल फोटो/इंटरनेट मीडिया

**यह है पुरस्कार राशि**

| पदक | राशि |
|---|---|
| स्वर्ण पदक | 6 करोड़, |
| रजत पदक | 4 करोड़ |
| कांस्य पदक | 2.5 करोड़ |
| चौथा नंबर | 50 लाख |

**खेल में प्रदर्शन के आधार पर मिलती हैं सरकारी नौकरियां :** हरियाणा में गत वर्ष खेल बजट में 202 फीसद की बढ़ोतरी की गई। ओलिंपिक, पैरा ओलिंपिक, यूथ ओलिंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, पैरा एशियन, यूथ एशियन गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, के पदक विजेताओं को नकद राशि के अलावा सरकारी नौकरी भी दी जाती है।

### गरीबी और सुविधाओं की कमी बड़ी बाधा : संदीप सिंह

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़ : भारतीय हाकी टीम के कप्तान रहे और वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह राज्य के खिलाड़ियों के ओलिंपिक में प्रदर्शन से बहुत ही उत्साहित हैं। विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी जीत हासिल करने के जज्बे के साथ ही मैदान में उतरता है। भारतीय टीम का कप्तान रहने की वजह से खिलाड़ियों की भावनाओं और उनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकता हूं। गरीबी और सुविधाओं की कमी खिलाड़ियों की प्रोग्रेस में बहुत बड़ी बाधा होती है, लेकिन हरियाणा सरकार ने प्रैक्टिस के समय ही खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बना रखी है। ओलिंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के खाते में पहले ही पांच-पांच लाख रुपये डाल दिए गए थे। पहले चरण में कम 200 नए कोच रखने जा रहे हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के स्टेडियम के बेहतरीन रखरखाव के लिए बजट प्रस्ताव बनकर तैयार है। एक्सीलेंस सेंटर आफ एथलेटिक्स बनाने का प्रस्ताव है, जिसके मुखिया नीरज चोपड़ा होंगे।

# उत्तराखंड ने वंदना को बनाया महिला सशक्तीकरण विभाग का ब्रांड अंबेसडर

राज्य ब्यूरो, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टोक्यो ओलिंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हाकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया उत्तराखंड में महिला4 सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड अंबेसडर बनाने की घोषणआ की है।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने 22 महिलाओं को राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार व 22 आंगनबाड़ी कार्यकताओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए।

उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। हाकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ओलिंपिक में उनका प्रदर्शन दिल को छूने वाला रहा है। सरकार ने उन्हें तीलू रौतेली सम्मान दिया है। साथ ही 25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया है।

### समारोह में नहीं पहुंच पाई वंदना

समारोह में हाकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को भी तीलू रौतेली पुरस्कार प्रदान किया जाना था, मगर वह अभी स्वदेश नहीं लौटी हैं। उनके परिवार का भी कोई सदस्य समारोह में नहीं पहुंच पाया। अलबत्ता, खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने हरिद्वार में वंदना के घर जाकर स्वजन से मुलाकात की। साथ ही सरकार की ओर से वंदना को महिला सशक्तीकरण एवं खेल विभाग का ब्रांड अंबेसडर बनाने संबंधी पत्र सौंपा।

## एनआइए ने बांग्लादेशी मानव तस्करों के ठिकानों पर मारे छापे

बेंगलुरु, प्रेट्र : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के अधिकारियों ने कर्नाटक के बेंगलुरु में बांग्लादेशी मानव तस्करों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को बताया कि एनआइए ने शनिवार को एक संदिग्ध के दो ठिकानों पर छापेमारी की, जो बांग्लादेशी मानव तस्करों के लिए फर्जी पहचान पत्र बनाने में संलिप्त था। छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, हार्ड डिस्क समेत छह डिजिटल डिवाइस व मोबाइल फोन बरामद हुए। फर्जी दस्तावेज बनाने में इस्तेमाल होने वाले इन उपकरणों को जब्त कर लिया गया है।'मामला एक महिला से संबंधित है, जिसे मानव तस्करों का समूह नौकरी का झांसा देकर भारत ले आया था।

## खेल जागरण

# पांचवें दिन नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद, टेस्ट ड्रा

जेएनएन, नई दिल्ली

बारिश ने भारत से इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत हासिल करके पांच टेस्ट की सीरीज में बढ़त लेने का मौका छीन लिया। नाटिंघम में खेले गए पहले टेस्ट के पांचवें व अंतिम दिन रविवार को लगातार बारिश होती रही, जिसके चलते दिनभर में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। पहले दो सत्र में जब बिलकुल भी खेल नहीं हो सका तो अंपायरों ने हालात को देखते हुए स्थानीय समयानुसार दोपहर 3:49 बजे मैच ड्रा के रूप में समाप्त करने की घोषणा कर दी। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त से लार्ड्स में खेला जाएगा।

पहले टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी 183 रन पर समेटने के बाद भारत ने 278 रन बनाकर 95 रन की बढ़त हासिल की थी। इसके बाद कप्तान जो रूट (109) के शतक के बावजूद इंग्लैंड की दूसरी पारी 303 रन पर सिमट गई थी, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 64 रन देकर पांच विकेट अपने नाम किए थे। भारत को मैच जीतने के लिए 209 रन का लक्ष्य मिला था। चौथे दिन का खेल खत्म होते तक भारत ने एक विकेट पर 52 रन बना लिए थे। अंतिम दिन उसे जीत के लिए सिर्फ 157 रन की जरूरत थी और उसके नौ विकेट बाकी थे। ऐसे में भारत की जीत पक्की नजर आ रही थी, लेकिन बारिश ने उसे जीत हासिल करने का मौका नहीं दिया।

पांचवें दिन बारिश की वजह से पिच को कवर करते हुए मैदानकर्मी। एएफपी

## मेरे देश की धरती सोना उगले पर झूमे गावस्कर

जेएनएन, नई दिल्ली : टोक्यो ओलिंपिक में शनिवार को जैसे ही भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता तो करोड़ों भारतीय प्रशंसक खुशी से झूमने लगे। इस ऐतिहासिक स्वर्ण की जीत का जश्न मनाने से खुद को भारत क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज व पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी नहीं रोक सके। 100 से भी अधिक साल बाद एथलेटिक्स का पहला पदक स्वर्ण आने पर गावस्कर 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती' गाना गाकर झूमने लगे। जब गावस्कर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह दिल से निकला था। भारत व इंग्लैंड के बीच खेले पहले टेस्ट के दौरान उनके साथ कमेंट्री कर रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा भी झूमते हुए नजर आए।

## मेसी बार्सिलोना के विदाई समारोह में भावुक हुए

मैड्रिड, एपी : स्पेन के बार्सिलोना क्लब के लिए पिछले 21 वर्षों से खेलते आ रहे दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी जुदाई की घड़ी आई तो अपने सुनहरे सफर को यादकर रोने लगे। बार्सिलोना क्लब की ओर से आयोजित विदाई समारोह में मेसी भावुक हो गए। मेसी ने कहा, 'मेरे लिए इतने वर्षों, लगभग पूरी जिंदगी यहां बिताने के बाद टीम छोड़ना काफी मुश्किल है। मुझे विश्वास था कि मैं क्लब के साथ बना रहूंगा, जो मेरे घर जैसा है। यह सुनकर दुख हुआ कि वित्तीय नियमों के कारण नया अनुबंध करना असंभव हो गया है। जिन रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि मैंने 30 प्रतिशत अधिक रकम मांगी थी वो सभी झूठ हैं, बल्कि मैंने बार्सिलोना में बने रहने के लिए अपने करार की रकम आधी भी कर दी थी।' मालूम हो कि साल 2017 में बार्सिलोना ने मेसी के साथ 550 मिलियन यूरो (करीब 438 करोड़ रुपये) का करार किया था, जो इस साल 30 जून को खत्म हो चुका है। अब मेसी के पेरिस सेंट जर्मन जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

विदाई समारोह के दौरान भावुक मेसी। एपी

# किपचोगे ने मैराथन में लगातार जीता दूसरा स्वर्ण

**ओलिंपिक डायरी**

टोक्यो, एपी : केन्या के इलियुड किपचोगे ने आखिरी 12 किमी में अपनी गति बढ़ाकर ओलिंपिक खेलों की पुरुष मैराथन प्रतियोगिता का बचाव करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। किपचोगे ने गर्मी और उमस भरे मौसम में सापोरो की सड़कों पर दौड़ते हुए दो घंटे, आठ मिनट, 38 सेकेंड में मैराथन पूरी करके स्वर्ण पदक जीता। नीदरलैंड्स के अब्दी नगीये ने दो घंटे, नौ मिनट, 58 सेकेंड से रजत पदक व बेल्जियम के बाशिर अब्दी ने दो घंटे 10 मिनट के समय के साथ कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता के साथ ओलिंपिक खेलों की ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं का भी समापन हुआ। किपचोगे ओलिंपिक पुरुष मैराथन में एक से अधिक स्वर्ण जीतने वाले तीसरे धावक बन गए हैं। इससे पहले अबेदे बिकिला (1960 और 1964) व वाल्देमर सीरपिन्स्की (1976 और 1980) ने यह कारनामा किया था।

**खेलों को हटाने के लिए आइओसी को मिले अधिक अधिकार :** अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) को किसी खेल को ओलिंपिक कार्यक्रम से हटाने के लिए अधिक अधिकार दिए गए हैं। इस मसले पर भारोत्तोलन व मुक्केबाजी के अफसरों के साथ लंबे समय से जुड़े मुद्दों को देखते हुए आइओसी के सदस्यों ने मतदान करके खेलों की सर्वोच्च संस्था को यह अधिकार दिए। अब यदि कोई खेल आइओसी के कार्यकारी बोर्ड के फैसलों का पालन नहीं करता है या ऐसे काम करता है जिससे ओलिंपिक आंदोलन की छवि धूमिल होती हो तो आइओसी उसे ओलिंपिक कार्यक्रम से हटा सकती है। भारोत्तोलन को लंबे समय से चले आ रहे डोपिंग मसलों व संचालन संबंधी मामलों के कारण पेरिस ओलिंपिक 2024 से हटाया जा सकता है। टोक्यो खेलों की मुक्केबाजी को 2019 में ही अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नियंत्रण से हटा दिया गया था।

इलियुड किपचोगे। एपी

**2016** रियो ओलिंपिक में भी केन्या के इलियुड किपचोगे ने जीता था स्वर्ण

### कनाडा की केल्सी मिशेल ने साइकिलिंग स्प्रिंट में स्वर्ण जीता

टोक्यो : कनाडा की केल्सी मिशेल ने रविवार को यहां वेलोड्रोम में यूक्रेन की ओलेना स्टारिकोवा को पछाड़ते हुए ट्रैक साइकिलिंग में महिलाओं की स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मिशेल ने सेमीफाइनल में जर्मनी की मौजूदा विश्व चैंपियन एम्मा हिंज और स्टारिकोवा ने 2019 की विश्व चैंपियन ली वाई सेज को पछाड़कर उलटफेर किया था। इस स्पर्धा में हांगकांग की सेज ने जर्मनी की हिंज को हराकर कांस्य पदक जीता।

### अमेरिका को पहली बार महिला वालीबाल स्पर्धा का स्वर्ण

टोक्यो, एपी : अमेरिका ने ब्राजील को रविवार को 3-0 से हराकर पहली बार ओलिंपिक में महिला वालीबाल प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता। अमेरिका की टीम ने 25-21, 25-20, 25-14 से जीत दर्ज की। वर्ष 1984 में पहली बार महिला वालीबाल का पदक जीतने के बाद अमेरिकी टीम ने तीन रजत और दो कांस्य पदक जीते लेकिन टोक्यो खेलों से पहले कभी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाई थी। अमेरिका को 2008 और 2012 में ब्राजील के खिलाफ ही शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जोर्डन लारसन के शाट को मैच प्वाइंट पर ब्राजील की खिलाड़ी वापस नहीं लौटा पाई, जिससे अमेरिका ने जीत दर्ज की। लारसन इससे पहले 2012 में रजत और पांच साल पहले रियो खेलों में कांस्य जीतने वाली अमेरिका की टीम का हिस्सा रह चुकी हैं।

**40** हजार अफगानियों को जान बचाकर ईरान जाना पड़ा है अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष की वजह से। यह बात संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन फार माइग्रेशन (आइओएम) की रिपोर्ट में सामने आई है।

# तीन दिन में तीसरी प्रांतीय राजधानी पर तालिबान का कब्जा

**अफगान संकट** ▸ कुंदुज की सरकारी इमारतों पर आतंकियों का नियंत्रण

### अफगान सेना के हवाई हमले तेज, 572 आतंकी मरे, अमेरिका ने तालिबान के कब्जे के बाद शबरगान पर बरसाए बम

**काबुल, एएनआइ :** अफगानिस्तान में तालिबान ग्रामीण क्षेत्रों पर कब्जे के बाद अब प्रांतीय राजधानियों में भी तेजी से घुस रहा है। लगातार तीसरे दिन तालिबान ने तीसरी प्रांतीय राजधानी पर भी कब्जा कर लिया। उसके आतंकी कुंदुज पर कब्जा करने में सफल हो गए हैं। अन्य प्रांतीय राजधानियों पर कब्जे को लेकर भीषण संघर्ष चल रहा है। अफगान सेना तालिबान का कब्जा हटाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। शबरगान में 200 आतंकियों को मारने के साथ ही सेना ने पूरे अफगानिस्तान में 572 आतंकियों को मारने का दावा किया है।

**अमेरिकी सेना के विमानों ने किए हवाई हमले :** तालिबान ने पूर्व में ही जौजान प्रांत की राजधानी शबरगान और निमरुज की राजधानी जरंज पर कब्जा कर लिया है। अब कुंदुज शहर पर भी उसका कब्जा हो गया है। इस लड़ाई में तालिबान आतंकियों ने कई नागरिकों की भी हत्या कर दी। शबरगान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी सेना के बी 52 लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में 200 आतंकी मारे गए, इनके सौ से ज्यादा वाहन नष्ट हो गए। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में विभिन्न प्रांतों में सेना ने 572 आतंकियों को मार दिया है। सेना के हमले में 309 आतंकी घायल हुए हैं।

एपी के अनुसार हेलमंद प्रांत में हवाई हमलों में एक स्कूल और क्लीनिक को भी नुकसान पहुंचा है।

**कुंदुज में सरकारी इमारतों पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा :** रायटर के अनुसार कुंदुज में सरकारी इमारतों पर तालिबान का पूरी तरह कब्जा हो गया है। इसके अलावा सर ए पोल शहर की सरकारी इमारतों में भी तालिबान आतंकी घुस गए हैं।

अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ाई और तेज हो गई है। राजधानी काबुल के पश्चिम में स्थित हेरात शहर में कुछ हिस्सों पर नियंत्रण के बाद टैंकों के साथ गश्त करते अफगान के सुरक्षाकर्मी। उधर, तालिबान ने कुंदुज में सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। एपी

#### हिंसा बढ़ने के कारण ईरान ने बार्डर किया बंद

एएनआइ के अनुसार ईरान ने अफगानिस्तान से लगी सीमा को पूरी तरह सील कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हिंसा बढ़ने के कारण उसने अपने बार्डर को बंद कर दिया है।

#### शहरों पर तालिबान के कब्जे की अमेरिका ने की निंदा

एएनआइ के अनुसार, अमेरिका के काबुल स्थित दूतावास ने प्रांतीय राजधानियों पर कब्जे की निंदा की है। अमेरिका ने कहा है कि तालिबान को युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए।

#### मस्जिद के लाउडस्पीकर पर लड़कियों को सौंपने का एलान कर उनसे जबरन शादी कर रहे आतंकी

आइएएनएस के अनुसार, तालिबान के कब्जे वाले जिलों और शहरों में हालात खराब हैं। कब्जा करने वाले स्थानों पर तालिबान आतंकी मस्जिद के लाउडस्पीकर पर लड़कियों को सौंपने का एलान करते हैं। फिर उनको वहां से ले जाकर जबरन शादी कर रहे हैं। तालिबान आतंकी नागरिकों से अपने घर में मौजूद महिलाओं की संख्या और उम्र पूछ रहे हैं। कई स्थानों पर तो तालिबान आतंकियों के डर से लोग अपने घर की महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार के साथ ही लूटपाट भी की जा रही है।

## तालिबान समर्थक देशों को भारत का कड़ा संदेश

- तिरुमूर्ति बोले, अफगानिस्तान में आतंकियों की सप्लाई चेन हो बंद
- टेरर फंडिंग करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराए अंतरराष्ट्रीय समुदाय

**न्यूयार्क, प्रेट्र :** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभालने के तुरंत बाद अफगानिस्तान पर बैठक बुलाकर भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि वह सदैव विश्व शांति के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता रहेगा। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने नाम न लेते हुए पाकिस्तान, चीन और तुर्की जैसे आतंक का समर्थन कर रहे देशों को भी कड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का अतीत उसका भविष्य नहीं हो सकता। इस क्षेत्र में आतंकवादियों की पनाहगाह और अभ्यारण्यों को तुरंत नष्ट करना चाहिए। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवादियों की सप्लाई चेन को भी तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। अब समय आ गया है कि सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान में हिंसा की समाप्ति के लिए ठोस कदम उठाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में या पड़ोसी देशों को आंतकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ का तो खतरा नहीं है। आतंकवाद को प्रश्रय देने या फंडिंग करने वालों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

ज्ञात हो कि पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी। उन्होंने अफगानिस्तान में हिंसा पर एक आपातकालीन सत्र बुलाने के संबंध में चर्चा की थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद बैठक आयोजित कर क्षेत्र में शांति के इरादों को स्पष्ट कर दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 अगस्त से ही अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है।

दो टूक : संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति। जागरण आर्काइव

## अफगानिस्तान को कमजोर बनाए रखना चाहता है पाक

**इस्लामाबाद, एएनआइ :** पाकिस्तान आतंकवादियों को हर संभव मदद कर रहा है। उसके देश से अफगानिस्तान की सीमा में आतंकवादी बेधड़क प्रवेश कर रहे हैं। इसके पीछे पाक की सोची-समझी साजिश है। वह अफगानिस्तान को हमेशा कमजोर और विभाजित रखना चाहता है। सेंटर आफ पालिटिकल एंड फारेन अफेयर के प्रेसिडेंट फेबियन बासार्ट ने टाइम्स आफ इजरायल में इस पर विस्तार से जानकारी दी है। अपने लेख में बासार्ट ने कहा है कि पाक अफगानिस्तान को हमेशा हिंसाग्रस्त देखना चाहता है। उसको अपना फायदा इसी में दिखाई देता है। यही वजह है कि वह अब भी तालिबान व अन्य आतंकी संगठनों को समर्थन ही नहीं, पूरा संरक्षण भी दे रहा है।

शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत गुलाम इसकजई ने तो यहां तक कह दिया कि अफगानिस्तान की सरकार सुरक्षा परिषद को इस बात के पूरे सुबूत सौंपने को तैयार है कि पाक तालिबान की सप्लाई चेन बना हुआ है। अफगान अधिकारियों कहना है कि पाक तालिबान को हवाई सीमा में भी समर्थन कर रहा है। पिछले महीने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने सीधे आरोप लगाया था कि पाक खुफिया एजेंसी आइएसआइ आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रही है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने खुद यह बात कही है कि पाक सीमा से 10 हजार विदेशी आतंकी अफगानिस्तान में घुसकर सेना से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेख में कहा गया है कि अफगानिस्तान में शांति के लिए पहले पाक की साजिशों को रोकना होगा।

## क्वाड की ताकत बन रही चीन के लिए परेशानी

- विदेश विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, साल भर पहले तक इस संगठन का मजाक उड़ाता था बीजिंग

**बीजिंग, एएनआइ :** वर्ष 2017 में क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान और आस्ट्रेलिया) की पहली बैठक के समय चीन ने इसका उपहास किया था, लेकिन अब चीन के लिए क्वाड चिंता का विषय बन गया है।

मार्च, 2021 में जब क्वाड के शीर्ष नेताओं की पहली बैठक हुई तो चीन ने निष्कर्ष निकाला कि अगले एक साल में चीनी महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही संगठन होगा।

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबी ने क्वाड को चार देशों के एक साथ काम करने की क्षमता वाला बताया है। विदेश मामलों की रिपोर्ट के मुताबिक, क्वाड चीनी रणनीति के लिए एक नए किस्म की परेशानी है। बहुआयामी गठबंधन एक मकसद से एक हो रहे हैं। इस गठबंधन से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की पूरी एक कड़ी मजबूत हो रही है और भविष्य में यह क्षेत्र और सशक्त हो सकता है।

चीन के राष्ट्रपति का आत्ममंथन इस बात को जानने के लिए शुरू हो गया है कि क्वाड क्या इतने व्यापक स्तर पर चीन के खिलाफ प्रभावी संतुलन बना लेगा। इसके बाद यह फैसला होगा कि चीन वैश्विक प्रभुत्व पर कायम रह पाएगा या नहीं।

फिलहाल चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि क्वाड के सदस्य देश चीनी बाजार पर निर्भरता खत्म करने के लिए कवायद कर रहे हैं, लेकिन चीन भी क्वाड की चुनौती को प्रभावी जवाब देने में लगा हुआ है।

विदेश मामलों की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने सितंबर के अंत में भारत, जापान और आस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं की पहली निजी तौर पर शामिल होने वाली बैठक प्रस्तावित की है।

इस बैठक से हिंद और प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच चीन की वैक्सीन कूटनीति विफल होने की संभावना है। चूंकि चीन विकासशील देशों को मुफ्त में अपनी वैक्सीन देकर उन पर अहसान जता रहा है।

## धरती पर ऊब गए हैं तो मंगल की सैर करिए

**जेएनएन, नई दिल्ली :** अगर आप धरती पर रहते-रहते ऊब गए हैं और कुछ नयापन चाहते हैं तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा आपको सुनहरा मौका दे रही है। नासा पहले मानव मंगल मिशन की तैयारी में है और इसके लिए अमेरिकी एजेंसी ने धरती पर मंगल ग्रह के वातावरण जैसा एक विशेष निवास स्थान तैयार किया है। इसमें एक साल के लंबे मिशन के लिए चालक दल के चार सदस्यों की भर्ती कर रहा है और इसके लिए इच्छुक लोगों से शुक्रवार से आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है।

अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित जानसन स्पेस सेंटर की एक इमारत में 3डी-प्रिंटर से 1,700 वर्ग फीट का यह मंगल ग्रह जैसा निवास स्थान तैयार किया गया है। 'मार्स ड्यून अल्फा' नाम के इस विशेष निवास में चार लोगों को एक साल तक रखा जाएगा। इस दौरान मंगल ग्रह के वातावरण में मानव पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा, ताकि असली मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने से पहले इन चुनौतियों से निपटने के उपाय तलाशे जा सकें।

अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि मंगल पर भावी मिशन की वास्तविक चुनौतियों की तैयारी में, नासा यह अध्ययन करेगी कि अत्यधिक उत्साहित व्यक्तियों पर जमीन पर तैयार किए गए मंगल ग्रह जैसे कठोर वातावरण में लंबे समय तक रहने पर क्या प्रभाव पड़ता है।

**भावी मानव मंगल मिशन में आने वाली दिक्कतों और उनके समाधान की खुलेगी राह :** नासा ने यह भी कहा है कि इसमें सीमित संसाधनों, उपकरणों की विफलता, संचार में देरी और पर्यावरण संबंधी अन्य दबावों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें चालक दल के सदस्यों को अंतरिक्ष में चहलकदमी, वैज्ञानिक शोध, वर्चुअल वास्तविकता और रोबोटिक नियंत्रण का उपयोग और संचार का आदान-प्रदान जैसे कार्य सौंपे जा सकते हैं। इससे भावी मानव मंगल मिशन में आने वाली दिक्कतों और उनके समाधान को विकसित करने में मदद मिलेगी।

#### मंगल बुला रहा है

- अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने लाल ग्रह के जैसे वातावरण में रहने के लिए मांगे आवेदन
- ह्यूस्टन के जानसन स्पेस सेंटर में बने इस विशेष निवास स्थान में चार लोगों पर साल भर किया जाएगा अध्ययन

विज्ञानियों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहा है मंगल ग्रह। फाइल फोटो

## मंदिर तोड़ने वालों के पक्ष में उतरा पाक के कट्टरपंथियों का गठबंधन

- घटना की निंदा करने से किया इन्कार
- खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित

**इस्लामाबाद, आइएएनएस :** पाकिस्तान के रहीम यार खान में गणेश मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन कट्टरपंथी अपनी अलग राह पर चल रहे हैं। मिल्ली याकजेहती परिषद (एमवाइसी) मंदिर तोड़ने वालों के समर्थन में उतर आई है। यह परिषद पाकिस्तान में 22 कट्टरपंथी धार्मिक व राजनीतिक संगठनों से मिलकर बनी हुई है। इस परिषद के हर तीन वर्ष बाद चुनाव होते हैं। इस बार चुनाव में जमीयत उलेमा ए पाकिस्तान के अबुल खैर जुबैर को अध्यक्ष चुनाव गया है। चुनाव के बाद प्रेस वार्ता में जब उनसे रहीमयार खान में हिंदू मंदिर तोड़े जाने के बारे में पूछा गया तो पहले वह अनजान हो गए और बाद में हैदराबाद की किसी घटना का जिक्र करने लगे। उन्होंने इस घटना की निंदा करने से इन्कार कर दिया। गठबंधन के अध्यक्ष ने कट्टरपंथियों की पैरवी करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होने का मतलब ये नहीं है कि बहुसंख्यकों के हितों को नजरंदाज कर दिया जाए।

इधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की विधान सभा ने पंजाब प्रांत में हिंदू मंदिर तोड़े जाने के संबंध में निंदा प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव अल्पसंख्यक विधायक रवि कुमार ने सदन में रखा। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सभी सदस्यों ने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी की निंदा की। विधान सभा में अल्पसंख्यक मामलों में एक कमीशन की स्थापना का भी प्रस्ताव पारित किया गया।

#### 150 पर एफआइआर, 50 हुए हैं गिरफ्तार

ज्ञात हो कि बीते दिनों पाक के रहीमयार खान जिले भोंग में गणेश मंदिर पर सैकड़ों कट्टरपंथियों ने हमला बोलकर तोड़फोड़ की थी। इस घटना का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बाद में 150 कट्टरपंथियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई। 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

## नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन ने साझा कार्यक्रम घोषित किया

- कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख का मसला भी सुलझाया जाएगा

**काठमांडू, प्रेट्र :** नेपाल में पांच दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन ने रविवार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसमें सभी नागरिकों को कोविड से बचाव की वैक्सीन मुफ्त लगाए जाने, महामारी से मुश्किल में आए उद्योगों को राहत देने, कमजोर तबके के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं से भ्रष्टाचार खत्म करने और राजनीतिक शांति प्रक्रिया पूरी किए जाने की घोषणा की गई है।

14 पन्नों का यह दस्तावेज नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के समन्वयक पूर्ण खडका ने सार्वजनिक किया। इस सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड, जनता समाजवादी पार्टी के चेयरमैन उपेंद्र यादव और राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी मौजूद थे। साझा कार्यक्रम में संतुलित विदेश नीति का वादा किया गया है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने, राष्ट्रहित के खिलाफ पूर्व में किए गए सभी समझौतों की समीक्षा करने और पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझाने की घोषणा की गई है। जिन सीमा विवादों को सुलझाने की बात कही गई है उनमें भारत के कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख इलाके भी शामिल हैं। केपी शर्मा ओली सरकार ने इन तीनों इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताते हुए उन्हें नेपाल के आधिकारिक मानचित्र में शामिल कर लिया था। इससे भारत के साथ नेपाल के संबंधों में तनाव आ गया था। भारत ने नेपाल की इस हरकत की निंदा करते हुए उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। साझा कार्यक्रम में सीमा पर होने वाली तस्करी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की घोषणा भी की गई है।

## चीन में बढ़ा कोरोना, बीजिंग आने पर लगी रोक

- जापान में नहीं थम रहा वायरस का कहर, टोक्यो में रिकार्ड मरीज
- राजधानी से 15 शहरों के लिए जाने-आने वाली फ्लाइट बंद

**बीजिंग, एएनआइ :** दुनिया को कोरोना महामारी देने वाले चीन में संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। चीन के कई प्रांतों में तेजी से मरीज मिलने के बाद अब राजधानी बीजिंग को संक्रमण से बचाने के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं।

सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार प्रांतों से राजधानी बीजिंग आने वालों पर रोक लगा दी गई है। ये उन क्षेत्रों के नागरिकों पर रोक है, जहां कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। उच्च और मध्यम खतरे वाले क्षेत्रों से आने के लिए यात्रियों को हवाई और रेल टिकट दिए जाने पर रोक लगा दी गई है। यात्रा के लिए हेल्थ कोड जारी किए गए हैं। केवल ग्रीन हेल्थ कोड के लोगों को ही यात्रा में राहत दी गई है। बीजिंग एयरपोर्ट से 15 शहरों के लिए जाने-आने वाली फ्लाइट बंद कर दी गई हैं।

जापान में कोरोना वायरस के मामले रिकार्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 15753 नए मरीज मिले हैं। टोक्यो, जहां ओलिंपिक खेल हुए हैं, वहां भी एक दिन में 4066 नए मरीज मिले हैं। यह संख्या जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है।

**ब्राजील :** रायटर के अनुसार, यहां हर रोज 990 लोगों की मौत हो रही है। एक दिन में 43 हजार से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं।

**आस्ट्रेलिया :** सबसे ज्यादा आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और क्वींसलैंड में डेल्टा वैरिएंट के कारण मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

**ईरान :** नवंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 39600 नए मरीज मिले हैं। मरने वालों की संख्या 542 है।

ताकि भारी न पड़ जाए लापरवाही...: मेक्सिको में कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। हाल के दिनों में इसे लेकर सरकारी स्तर पर चेतावनी जारी करते हुए लोगों से पहले की तरह सतर्कता बरतने की अपील की गई थी। बावजूद इसके लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए घूमते देखे जा रहे हैं। मेक्सिको सिटी में संक्रमण के खतरे को लेकर सरकारी स्तर पर अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाथ में पोस्टर लेकर लोगों के हाथों को सैनिटाइज करता एक कर्मचारी। रायटर

## पीएम जानसन की ऋषि सुनक को डिमोट करने की धमकी

- कोविड यात्रा नियमों में ढील पर पत्र लीक होने पर ब्रिटिश पीएम हुए आगबबूला

**लंदन, प्रेट्र :** ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जानसन उन मीडिया रिपोर्ट से आगबबूला हैं जिनमें पिछले हफ्ते दावा किया गया कि चांसलर ऋषि सुनक ने पत्र लिखकर अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 यात्रा मानकों में ढील देने की सिफारिश की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मूल के वित्त मंत्री ने अपने बास को पत्र लिखकर कहा था कि कोरोना वायरस के यात्रा मानकों के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए इन यात्रा मानकों में ढील दी जानी चाहिए।

संडे टाइम्स के अनुसार, जानसन ने गुस्से में लाल होते हुए सुनक का डिमोशन कर उन्हें वित्त मंत्रालय से स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभालने को कहा है। जानसन को इस बारे में पहली बार तब पता चला जब मीडिया में रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ सूत्र के अनुसार तब जानसन ने एक दर्जन अधिकारियों की मौजूदगी में कहा कि वह बदलाव करने की सोच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब सुनक को अगला स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। वह वहां अच्छा काम कर सकते हैं। फिर उसी बैठक में उन्होंने कहा कि चांसलर को मंत्रिमंडल के अगले फेरबदल में डिमोट किया जाएगा। अखबार में इंगित किया गया कि जानसन बेलाग बोलने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि डाउनिंग स्ट्रीट ने निजी वार्तालाप पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। सुनक का पूरा ध्यान ब्रिटेन की आर्थिक बदहाली दूर करने पर है जो कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके साथ ही वह नई नौकरियां सृजित करने और पुरानी सुरक्षित करने के प्रयास करेंगे। इस बीच, सुनक एक कड़ा बजट लाने की तैयारी कर रहे हैं।

बोरिस जानसन व ऋषि सुनक की फाइल फोटो। इंटरनेट मीडिया

## भारत व यूएई की नौसेनाओं ने अबूधाबी तट पर किया अभ्यास

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** भारत व संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की नौसेनाओं ने शनिवार को संयुक्त अभ्यास किया। सैन्य सहयोग बढ़ने के मद्देनजर दोनों देशों की नौसेनाओं ने अबूधाबी तट पर कौशल व तकनीकी दक्षता साझा की। अधिकारियों ने बताया कि अभ्यास जायेद तलवार में भारतीय नौसेना का युद्धपोत आइएनएस कोच्चि व दो एमके 42बी हेलीकाप्टर तथा यूएई की ओर से अल-धफरा मिसाइल व एक एएस-565बी पैंथर हेलीकाप्टर ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास ओमान तट पर लगभग हफ्ते भर पहले इजराइली कंपनी के तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले में ब्रिटिश व रोमानिया के एक-एक नागरिकों के मारे जाने के बाद खाड़ी क्षेत्र में उपजे तनाव के बीच किया गया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, 'जहाजों ने दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए क्षितिज लक्ष्यीकरण, खोज एवं बचाव तथा इलेक्ट्रानिक युद्ध का अभ्यास किया।' उन्होंने बताया कि इस अभ्यास में हेलीकाप्टरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया।

### अत्याचारों के खिलाफ इथियोपिया में प्रदर्शन

राजधानी अदीस अबाबा में मेस्केल स्क्वायर पर हजारों लोगों ने टाइगर लिब्रेशन फ्रंट (टीपीएलएफ) के विरोध में रैली निकाली। इस मौके पर लोग 'आइ मार्च टू सेव इथियोपिया' का बैनर लेकर शामिल हुए और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा बल (ईएनडीएफ) के सैनिकों की प्रशंसा की और उनके समर्थन में नारे भी लगाए। इस रैली में घुड़सवारों के दस्ते भी शामिल हुए थे। लाखों वर्ष पुराने इस अफ्रीकी देश में लोग टीपीएलएफ के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं। तिगरे इलाके में कुछ माह पहले घरों में घुसकर पांच सौ से अधिक महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले भी सामने आए थे। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस घटना की निंदी की थी। एपी

## विमानों और हेलीकाप्टरों से बुझाई जा रही है ग्रीस की आग

**एथेंस, एपी :** ग्रीस में अग्निशमन दल के सैकड़ों लोगों ने विमानों, हेलीकाप्टरों और अन्य देशों से भेजी गई मदद के जरिये जंगल में लगी भीषण आग बुझाने की कोशिश की है। हालांकि रविवार को जंगल में आग लगी रही। वर्षों में पहली बार इस देश में इतनी भीषण गर्मी पड़ी है।

प्राधिकारियों ने चार प्रमुख स्थानों पर लगी भीषण आग को बुझाने में अपने सारे संसाधन लगा दिए। इसमें से एक आग ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े द्वीप इविया में लगी थी। यहां जंगल पिछले पांच दिनों से जल रहा था।

यह आग एक तट से दूसरे और एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक बढ़कर पहुंचती चली गई। और तीसरे द्वीप दक्षिणी पेलोपोनीज क्षेत्र में पहुंच गई।

**आग लगने के कारणों की चल रही जांच :** उत्तरी एथेंस में यह पांचवीं सबसे भीषण आग है। दर्जनों घरों और कारोबारों को जलाने के बाद जंगल की आग माउंट परनीथा नेशनल पार्क में पहुंच गई। जंगल की आग में बिजली का एक खंभा गिरने की वजह से अग्निशमन दल के एक कर्मी की सिर पर चोट लगने से मौत हो गई। आग में झुलसने वाले करीब 20 लोगों का इलाज चल रहा है। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। शुक्रवार को इस संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ग्रेटर एथेंस क्षेत्र में केंद्रीय व दक्षिणी ग्रीस यह आग भड़कना शुरू होने का अंदेशा है।

ग्रीस में लगी जंगलों की आग अब भयावह हो गई है। देश के दूसरे सबसे बड़े द्वीप इविया में आग गांव तक पहुंच गई है। इस पर काबू पाने के लिए हेलीकाप्टरों की भी मदद ली जा रही है। एएफपी

# सुधरे हालात तो बनी बात

पीवी सिंधु • ट्विटर

**पदक तालिका**

| नंबर | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अमेरिका | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | चीन | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | जापान | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | ग्रेट ब्रिटेन | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | आरओसी | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | आस्ट्रेलिया | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7 | नीदरलैंड्स | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | फ्रांस | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9 | जर्मनी | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10 | इटली | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 48 | भारत | 1 | 2 | 4 | 7 |

आरओसी (रूसी ओलिंपिक समिति)

टोक्यो नेशनल स्टेडियम में समापन समारोह के साथ 32वें ओलिंपिक का अंत हुआ • प्रेट्र

बजरंग पूनिया • एपी

## खिलाड़ियों को मिली सुविधाएं तो हुआ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, कुछ खिलाड़ी नहीं चूकते तो दहाई में पहुंचता आंकड़ा

**पीवी सिंधु : कांस्य पदक**

टोक्यो 2020 के लिए सिंधू को पहले से पदक का मजबूत दावेदार माना जा रहा था और उन्होंने कांस्य पदक जीतकर किसी को निराश नहीं किया। इस 26 साल की खिलाड़ी ने इससे पहले 2016 रियो ओलिंपिक में रजत पदक जीता था। वह ओलिंपिक में दो पदक जीतने वाली देश की पहली महिला और कुल दूसरी खिलाड़ी हैं। टोक्यो खेलों में उनके प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेमीफाइनल में ताई जू यिंग के खिलाफ दो गेम गंवाने से पहले उन्होंने एक भी गेम में हार का सामना नहीं किया था। हैदराबाद की शटलर ने 2014 में विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई।

**पीवी सिंधू पर इन्होंने खर्च की राशि**

| टाप्स | एसीटीसी | कुल |
|---|---|---|
| ₹51,28,030 | ₹3,46,51,150 | ₹3,97,79,180 |

**लवलीना बोरगोहाई पर इन्होंने खर्च की राशि**

| टाप्स | एसीटीसी | कुल |
|---|---|---|
| ₹11,30,300 | ₹7,00,215 | ₹18,30,515 |

टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम (टाप्स)

एनुअल कैलेंडर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन (एसीटीसी)

**लवलीना बोरगोहाई : कांस्य पदक**

लवलीना ने अपने पहले ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह विजेंदर सिंह और मेरी कोम के बाद मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। 23 साल की लवलीना का खेलों के साथ सफर असम के गोलाघाट जिले के बरो मुखिया गांव से शुरू हुआ। ओलिंपिक की तैयारियों के लिए 52 दिनों के लिए यूरोप दौरे पर जाने से पहले वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई, लेकिन उन्होंने 69 किग्रा वर्ग में चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन निएन-शिन चेन को मात दी।

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

टोक्यो ओलिंपिक में खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करके भारत को पहली बार इस खेल महाकुंभ में सात पदक दिलाए। भारत ने इस बार एक स्वर्ण, दो रजत, चार कांस्य सहित कुल सात पदक अपनी झोली में डाले। हालांकि यह नंबर और भी बढ़ सकता था। इस बार के ओलिंपिक इसलिए भी खास थे क्योंकि खेल मंत्रालय, अधिकतर खेल महासंघों ने खिलाड़ियों को पूरा समर्थन किया। खिलाड़ियों ने विदेश में अभ्यास के साथ जो भी मांग की वह पूरी की गई। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों ने अपना ज्यादातर समय विदेश में ही तैयारियों में व्यतीत किया। खिलाड़ियों के लिए फिजियो, और विदेशी कोच जैसी सभी सुविधाओं का ध्यान दिया गया।

अगर हमारे निशानेबाज, तीरंदाज और कुछ खिलाड़ी नहीं चूकते तो भारत पहली बार पदकों की संख्या दहाई में पहुंचा देता। पहलवान दीपक पूनिया कांस्य पदक का मुकाबला आखिरी 10 सेकेंड में हार गए। महिला गोल्फर अदिति अशोक आखिरी दौर में चौथे स्थान पर रहीं। महिला हाकी टीम भी कांस्य पदक के मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन से हार गई। छह बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मेरी कोम, विश्व नंबर एक मुक्केबाज अमित पंघाल और महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी भी पदक नहीं जीत पाईं। स्वर्ण पदक की दावेदार महिला पहलवान विनेश फोगाट भी पदक नहीं जीत पाईं। ये पदक आते तो संख्या दो नंबर में होते हुए 14 हो जाती और अगर तीरंदाज व निशानेबाज निराश नहीं करते तो यह संख्या 14 से भी ज्यादा होती। टोक्यो में पदकों को दहाई में पहुंचाने का लक्ष्य 2014 में रखा गया था। तब खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम (टाप्स) का आगाज किया था। इस स्कीम में उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है तो ओलिंपिक में पदक के दावेदार होते हैं और यह स्कीम खिलाड़ियों को आर्थिक मदद करती है। इसके अलावा एनुअल कैलेंडर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन (एसीटीसी) ने खिलाड़ियों के ट्रेनिंग और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने में मदद की। कोरोना और लाकडाउन ने भी तैयारियों पर असर डाला लेकिन फिर भी साई और मंत्रालय ने सभी जरूरी कदम उठाए। अगर खिलाड़ियों को इसी तरह विदेशों में खेलने का मौका मिलता रहेगा तो उम्मीद की जा सकती है कि जब 2024 में पेरिस ओलिंपिक होंगे तो भारत के पदकों की संख्या दोगुनी होगी।

**पुरुष हाकी टीम : कांस्य पदक**

भारतीय टीम ने कांस्य पदक मुकाबला जीतकर इस खेल में 41 साल के सूखे को खत्म किया। ग्रुप चरण में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-7 से हारने के बाद टीम ने शानदार वापसी की। सेमीफाइनल में बेल्जियम से हराने के बाद टीम ने कांस्य पदक प्ले आफ में जर्मनी को 5-4 से मात दी। पूरे टूर्नामेंट के दौरान मनप्रीत की प्रेरणादायक कप्तानी के साथ अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने शानदार प्रदर्शन किया।

**मीराबाई चानू : रजत पदक**

मणिपुर की छोटे कद की इस खिलाड़ी ने टोक्यो 2020 में प्रतिस्पर्धा के पहले दिन 24 जुलाई को ही पदक तालिका में भारत का नाम अंकित करा दिया था। उन्होंने 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीतकर भारोत्तोलन में पदक के 21 साल के सूखे को खत्म किया। इंफाल से लगभग 20 किमी दूर नोंगपोक काकजिंग गांव की रहने वाली मीराबाई छह भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं। उनका बचपन पास की पहाड़ियों में लकड़ियां काटते बीता।

मीराबाई चानू • ट्विटर

**नीरज चोपड़ा : स्वर्ण पदक**

भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ओलिंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। नीरज को तीन वर्षों से ओलिंपिक में पदक का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणवी किसान के बेटे नीरज वजन कम करने के लिए खेलों से जुड़े थे। जब उन्होंने स्टेडियम में कुछ खिलाड़ियों को भाला फेंक का अभ्यास करते देखा तो उन्हें इस खेल से प्यार हो गया। वह 2016 जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर के अंडर -20 विश्व रिकार्ड के साथ ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वह इस साल (2016) भारतीय सेना में चार राजपूताना राइफल्स में सूबेदार के पद पर नियुक्त हुए। उनकी अन्य उपलब्धियों में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक शामिल हैं। उन्होंने 2017 एशियाई चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया था।

**2016** से अभी तक 32 ओलिंपिक निशानेबाजों पर टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम के तहत खर्च - 44.41 करोड़ रुपये

**2017** से और अतानु व तरुणदीप राय को 2018 से प्रशिक्षण दे रहे हैं। सरकार ने प्रशिक्षण के लिए टोक्यो जैसी सुविधा सुनिश्चित की और इसके लिए फंड दिया

**2019** के बाद से भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने लगातार अभ्यास कैंप कराए। इसके साथ ही तीरंदाजों को साई ने 2019 में टाप्स की कोर (प्रमुख) टीम में जगह भी दी

**2019** विश्व चैंपियनशिप से सरकारी खर्चे पर टीम के साथ मनोचिकित्सक जाता रहा

**2019** से अभी तक भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा एनुअल कैलेंडर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन (एसीटीसी) के तहत किया गया खर्च-55 करोड़ रुपये

**2019** से टीम को मेंटल ट्रेनर दिया गया जो दीपिका को

**बजरंग पूनिया : कांस्य पदक**

इन खेलों से पहले बजरंग को स्वर्ण पदक का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। सेमीफाइनल में हार के बाद वह स्वर्ण पदक के सपने को पूरा नहीं सके, लेकिन कांस्य पदक जीतकर उन्होंने देश का नाम ऊंचा जरूर किया। वह बचपन से ही कुश्ती को लेकर जुनूनी थे और आधी रात के बाद दो बजे ही उठ कर अखाड़े में पहुंच जाते थे। कुश्ती का जुनून ऐसा था कि 2008 में खुद 34 किलो के होते हुए 60 किलो के पहलवान से भिड़ गए और उसे चित कर दिया।

रवि दाहिया • एपी

**रवि दाहिया : रजत पदक**

हरियाणा के रवि ने पुरुषों के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीत कर अपनी ताकत और तकनीक का लोहा मनवाया। रवि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में प्रशिक्षण लेते हैं जहां से पहले ही भारत को दो ओलिंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त मिल चुके हैं। उनके पिता राकेश कुमार ने उन्हें 12 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम भेजा था। उनके पिता रोज अपने घर से 60 किमी दूर छत्रसाल तक दूध और मक्खन लेकर पहुंचते थे। उन्होंने 2019 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य और फिर 2020 में दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता। उन्होंने अलमाटी में इस साल खिताब का बचाव किया।

**ये पदक से चूके**

**महिला हाकी टीम :** रियो 2016 में आखिरी पायदान पर रहने वाली टीम ने टोक्यो में चौथा स्थान हासिल कर सबको चौंका दिया। महिला टीम कांस्य पदक के प्ले-आफ में ग्रेट ब्रिटेन से 3-4 से हार गई, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उसने गजब का जज्बा दिखाया।

**दीपक पूनिया :** दीपक पूनिया कुश्ती के 86 किग्रा के सेमीफाइनल में हारने के बाद कांस्य पदक के मुकाबले में अच्छी स्थिति में थे, लेकिन आखिरी 10 सेकेंड में विरोधी पहलवान ने उन्हें मात दे दी।

**अदिति अशोक :** महिला गोल्फ में 200वीं रैंकिंग की खिलाड़ी अदिति अशोक ओलिंपिक में अपने खेल के आखिर तक पदक की दौड़ में बनी हुई थी, लेकिन वह दो शाट से इसे चूक गईं और चौथे स्थान पर रहीं। रियो ओलंपिक में वह 41 वें स्थान पर रही थीं, लेकिन टोक्यो में उन्होंने शानदार खेल के दम पर देश का दिल जीत लिया।

## मराठाओं से नीरज का नाता, अपने भाले से जीती दुनिया

**इतिहास**

- रोड़ मराठा हैं नीरज, पानीपत में शहीद हुए थे चोपड़े सरदार
- पानीपत की जंग के बाद छिपे हुए मराठा ही बाद में रोड़ कहलाए

**जागरण संवाददाता, पानीपत :** जनवरी 1761, इतिहास के पन्नों में दर्ज पानीपत की तीसरी लड़ाई की गाथा। वीर मराठों ने हिंदुस्तान को गुलामी से बचाने के लिए पानीपत के मैदान पर अपना लहू बहाया। जंग नहीं जीत सके, पर अब्दाली भी दोबारा लौटकर नहीं आया। उन्हीं मराठा वंशज से खुद को जोड़ने वाले रोड़ समाज के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में अपने भाले से देश को स्वर्ण पदक दिला दिया।

नीरज के दादा धर्म सिंह गर्व से कहते हैं कि मराठे इतिहास रचते हैं। तीसरी लड़ाई में अपना लहू बहाया, पोते ने बरसों बाद भाले से ही जंग जीती। यह भी दिलचस्प है कि नीरज चोपड़ा ने पानीपत के शिवाजी स्टेडियम से भाला फेंकने का अभ्यास शुरू किया था। वही, छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नीरज खुद सेना में राजपूताना राइफल्स में सूबेदार हैं। यानी, खून और कर्म से वह योद्धा ही हैं, विजय तो निश्चित ही थी। दादा धर्म सिंह कहते हैं, महाराष्ट्र के मराठी हमारे भाई हैं। वो हमारा मान सम्मान करते हैं। हमारा उनसे वर्षों पुराना नाता है। पिता सतीश चोपड़ा ने जागरण से कहा, 'रोड़ और मराठा भाई हैं।'

**रोड़ खुद को इस तरह मराठों से जोड़ते हैं :** मराठा इतिहास के जानकार बसताड़ा गांव के रामपाल मूले का कहना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों की तलाश की जा रही थी। इनका सिर लाने वालों पर इनाम रखा गया था। तब मराठे जंगल में छिप गए। अपने गोत्र में कुछ बदलाव भी किया। जैसे दाबाड़े अब दाबड़ा, मूले अब मूल्यवान, तोरणे अब टूर्ण, टरके अब तुर्का, कादे अब कादियान, जुड़े अब जूड, रूल्ले अब रूल्हयाण हो गए हैं। इसी तरह चोपड़े यहां चोपड़ा हैं। महाराष्ट्र के सतारा और अकोला में चोपड़े गोत्र के परिवार रहते हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा और इतिहासकार वसंतराव मोरे ने सबसे पहले यह उजागर किया था कि रोड़ समाज मराठा वंशज है। हालांकि राजा रोड़ सेवा दल के लोग इसका खंडन करते हैं।

**यहां बसे हैं रोड़ मराठा :** पानीपत से कुरुक्षेत्र तक ही रोड़ मराठा बसे हैं। इसी क्षेत्र के बीच ही मराठे छिपे थे। पानीपत शिमला मौलाना, खंडरा, करनाल के कैमला, बुढ़ा, बसताड़ा, झिमरहेड़ी, कुटेला, बजीदा, झिंझाड़ी, दादूपुर, शामगढ़, रायपुर रोढ़ान, बराना, कुरुक्षेत्र के उमरी और अमीन तक बसे हैं रोड़। इस क्षेत्र में इनकी आबादी करीब आठ लाख है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बीए के पाठ्यक्रम में हरियाणा का इतिहास पढ़ाया जाता है। इसमें लिखा है कि 1761 से पहले रोड़ जाति नहीं थी। कुरुक्षेत्र का अमीन इस जाति का प्रमुख केंद्र रहा है। पानीपत की लड़ाई में पुणे से आए कई सरदार शहीद हुए। उन्हीं में से एक थे नरसिंगराव चोपड़े। रघुनाथ यादव लिखित पानिपतची बखर में इन शहीदों का वर्णन है। करनाल के बांभरहेड़ी के जगबीर मराठा कहते हैं कि महाराष्ट्र के चोपड़े ही हरियाणा के रोड़ चोपड़ा हैं।

**बाजीराव-मस्तानी के वंशज बोले, योद्धा कभी युद्ध नहीं भूलता :** पानीपत की तीसरी लड़ाई का गवाह है काला अंब। यहीं पर बाजीराव-मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर शहीद हुए थे। शमशेर बहादुर के वंशज भोपाल के शादाब बहादुर ने कहा कि नीरज रोड़ मराठा हैं। योद्धा कभी अपनी युद्ध शैली नहीं भूलता है। मराठों ने 1761 में भी भाला फेंका था। आज जो भाला फेंका था, वो दुनिया को जीत लिया है। बाजीराव और मस्तानी, दोनों बहुत अच्छा भाला फेंकते थे। भाला हमारा रायल लोगो भी है।

नीरज चोपड़ा • एएनआइ

**87.58** मीटर दूर भाला फेंककर भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीता था

**88.07** मीटर दूरी तक भाला फेंका था नीरज ने टोक्यो ओलिंपिक से ठीक पहले मार्च में पटियाला में आयोजित इंडियन ग्रांप्रि में। यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है

> ये भाला तो वीर शिवा का और रणभेदी राणा का है,
> भारत मां का सपूत नीरज बेटा तो हरियाणा का है।
> आज तिरंगा ऊंचा चढ़ते देख सीना चौड़ा है,
> और राष्ट्रगान की धुन पर अपना लहू रगों में दौड़ा है।
> याद करें जिस युद्ध ने बरसों गहरा घाव छोड़ा है,
> उसी पानीपत के छोरे ने आज इतिहास को मोड़ा है।
> – देवेंद्र फड़नवीस, पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

### 90 मीटर तक भाला फेंकने की चाहत

**टोक्यो, प्रेट्र :** नीरज चोपड़ा ने आगामी प्रतियोगिताओं में 90 मीटर भाला फेंकने को अपना अगला लक्ष्य बनाया है। नीरज तो शनिवार को ही ओलिंपिक के रिकार्ड (90.57 मीटर) को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। चोपड़ा ने कहा, 'भाला फेंक एक तकनीकी स्पर्धा है और काफी कुछ दिन की फार्म पर निर्भर करता है इसलिए मेरा अगला लक्ष्य 90 मीटर की दूरी तय करना है। मैं इस साल केवल ओलिंपिक पर ध्यान दे रहा था। अब मैंने स्वर्ण जीत लिया है तो मैं भावी प्रतियोगिताओं के लिए योजनाएं बनाऊंगा। भारत लौटने के बाद मैं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विदेशों के वीजा हासिल करने की कोशिश करूंगा।'

**104.80** मीटर की दूरी तक भाला फेंकने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं नीरज के पूर्व जर्मन कोच उवे हान। उन्होंने 1984 में एक टूर्नामेंट में इतनी दूरी तक भाला फेंका था

**98.48** मीटर दूरी का विश्व रिकार्ड चेक गणराज्य के जैन जेलेजनी ने 1996 की विश्व चैंपियनशिप में बनाया था

**90.57** मीटर दूरी का भाला फेंक स्पर्धा में ओलिंपिक रिकार्ड है। यह भाला नोर्वे के आंद्रेआस थोर्किल्सेन ने 2008 बीजिंग ओलिंपिक में फेंका था

**2** करोड़ रुपये आनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाली कंपनी बायजूस स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को देगी। अन्य पदक विजेता खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

## नीरज-बजरंग ने दिया जश्न मनाने का मौका

साक्षी मलिक
कलम से

मुझे पूरी उम्मीद थी कि बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा दोनों ही पदक के साथ लौटेंगे। इसके साथ ही भारत की लंदन 2012 की तालिका को पीछे छोड़ते हुए हमने ओलिंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बजरंग पर मेरा विश्वास इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि उन्होंने कजाखस्तान के पहलवान को हाल ही में हराया था। मुझे भरोसा था कि वह कांस्य पदक के मुकाबले में शुरुआत से ही अधिक आक्रामक होकर खेलेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि बजरंग जब मुकाबले के लिए मैट पर पहुंचे तो उन्होंने घुटने का ब्रेस नहीं पहनने का संदेश दिया। मुझे लगता है कि उन्हें फिटनेस की कोई समस्या नहीं है। मेरे हिसाब से वह पदक जीतने को लेकर काफी आश्वस्त थे और मुकाबले के लिए उतरने के बाद ही उन्होंने घुटने का ब्रेस पहना।

ये बात आसानी से देखी जा सकती थी कि उन्होंने इस मुकाबले से पहले की रात को अच्छी तरह हैंडल किया। उस रात उन पर कोई दबाव था भी तो उन्होंने मैट पर इसे बिलकुल भी खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनके चेहरे पर शांति और आश्वस्तता का भाव था और उन्हें अच्छी तरह पता था कि कांस्य पदक हासिल करने के लिए क्या करने की जरूरत है। बजरंग ने इस मुकाबले में आसानी से जीत हासिल की और जैसे ही उनकी बढ़त बढ़ती गई हमारे अखाड़े का उत्साह भी बढ़ता चला गया। सभी युवा पहलवानों ने ट्रेनिंग रोक दी और मन में बजरंग की जीत की चाहत लिए मुकाबला देखने लगे। उनकी जीत के साथ ही टोक्यो में रवि दहिया के बाद कुश्ती में भारत को दूसरा पदक मिल गया। (टीसीएम)



**राय** दिग्गज हाकी खिलाड़ियों ने माना कि टोक्यो में जीता कांस्य पदक भविष्य में बेहतर करने की प्रेरणा देगा

## भारतीय हाकी में नई जान फूंकने वाला साबित हुआ ओलिंपिक

उमेश राजपूत • नई दिल्ली

हाकी में भारत को चार दशक के बाद ओलिंपिक पदक हासिल हुआ। मनप्रीत की अगुआई वाली पुरुष हाकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता तो रानी रामपाल की अगुआई वाली महिला टीम बेशक पदक जीतने से चूक गई, लेकिन उसने दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिग्गज भारतीय हाकी खिलाड़ियों का मानना है कि टोक्यो ओलिंपिक भारतीय हाकी में नई जान फूंकने वाला साबित हुआ। अब यहां से मेहनत की जाए तो भारतीय हाकी फिर से अपना पुराना गौरव और स्वर्णिम दौर वापस पा सकती है।

1964 टोक्यो ओलिंपिक में भारतीय हाकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। उस टीम में खेलने वाले गुरबक्श सिंह अब 85 साल के और हरबिंदर सिंह 78 साल के हो चुके हैं। गुरबक्श कहते हैं, '40 साल से ज्यादा से हम ना तो विश्व कप और ना ही ओलिंपिक में कोई पदक जीत सके थे, लेकिन अब यह इंतजार खत्म हुआ। यह जीत हमारी हाकी को काफी ऊंचाई पर ले जाएगी। यह जीत हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी और हमारी हाकी बेहतर से बेहतर होती जाएगी।' वहीं, हरबिंदर ने कहा, 'टोक्यो एक बार फिर भारत के लिए भाग्यशाली साबित हुआ। यह पदक देश के बच्चों को हाकी के प्रति आकर्षित करेगा और इस टीम को और अच्छा करने की प्रेरणा देगा।'

1975 विश्व कप विजेता भारतीय हाकी टीम के कप्तान अजित पाल सिंह ने कहा, 'बहुत मेहनत और मुश्किल से कई वर्षों के इंतजार के बाद यह पदक आया है। यह अहसास ही पुराने दिनों की याद दिलाने वाला है। 2008 बीजिंग ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं करने के बाद से भारतीय हाकी में काफी मेहनत हुई है, लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना चाहिए। अब कांस्य आ गया है, लेकिन स्वर्ण का इंतजार बना हुआ है और ये इंतजार भी खत्म हो, इसके लिए कुछ और क्षेत्र हैं जिन पर काम होना जरूरी है।' 1975 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य अशोक ध्यानचंद ने कहा, 'यकीनन भारतीय हाकी के पुराने दिन लौट आए हैं। इस पदक ने हमें भारतीय हाकी का सुनहरा दौर लाने के लिए एक मंच दिया है और अब हमें यहां से इसे आगे ले जाना है।' म्यूनिख ओलिंपिक 1972 की कांस्य विजेता भारतीय टीम के सदस्य 70 वर्षीय अजित सिंह ने कहा, 'मैं तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा हूं। आखिरी मिनटों में ऐसी हालत हो गई थी कि लग रहा था कि दिल का दौरा ना पड़ जाए, लेकिन अब मैं 10 साल ज्यादा जीऊंगा। इस पदक ने भारतीय हाकी के पुराने दिनों को लौटाने की शुरुआत कर दी है। यह जीत सिर्फ इस टीम की नहीं है, बल्कि उन सभी को भी उसका श्रेय मिलना चाहिए, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में इस टीम के साथ मेहनत की है। अब चाहें वे खिलाड़ी हों, पूर्व कोच हों या सहयोगी स्टाफ। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की इसमें बड़ी भूमिका है, जिन्होंने हाकी का तब साथ दिया जब उसे कोई स्पांसर नहीं मिल रहा था।'

1975 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य एजजेएस चिमनी ने कहा, 'इस पदक से यह साबित होता है कि इस टीम में अपनी काबिलियत को साबित करने का दमखम है। इस पदक से ना सिर्फ इस टीम का मान बढ़ा है, बल्कि देश का गौरव भी बढ़ा है।'

**प्रभातफेरी/ बंशीधर शुक्ल**

# उठो सोने वालो सबेरा हुआ है

उठो सोने वालो, सबेरा हुआ है।
वतन के फकीरों का फेरा हुआ है।

जगो तो निराशा निशा खो रही है,
सुनहरी सुपूरब दिशा हो रही है,
चलो मोह की कालिमा धो रही है,
न अब कौम कोई पड़ी सो रही है।

तुम्हें किसलिए मोह घेरा हुआ है?
उठो सोने वालो सबेरा हुआ है।

जवानों उठो कौम की जान जागो,
पड़े किसलिए देश की शान जागो,
तुम्हीं दीन की आस-अरमान जागो,
शहीदों की सच्ची सुसंतान जागो!

चलो दूर आलस अंधेरा हुआ है,
उठो सोने वालो सबेरा हुआ है।

उठो देवियों वक्त खोने न देना,
कहीं फूट के बीज बोने न देना,
जगें जो उन्हें फिर से सोने न देना,
कभी देश अपमान होने न देना।

मुसीबत से अब तो निबेरा हुआ है,
उठो सोने वालो सबेरा हुआ है।

नई कौमियत मुल्क में उग रही है,
युगों बाद फिर हिंद मां जग रही है,
खुमारी लिए जान को भग रही है,
दिलों में निराली लगन लग रही है।

शहीदों का फिर आज फेरा हुआ है,
उठो सोने वालो सबेरा हुआ है।

(यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में लोकप्रिय प्रभातफेरी रहा है)

punarnava@knp.jagran.com

# नई डगर पर

**गीत**

राजकुमारी 'रश्मि'
ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

नई डगर पर आज बढ़ रहे,
आजादी के पांव।
थामी है पतवार भीष्म ने,
खेने अब यह नाव।

हर संभव हो रहे प्रयासों,
से है, मिटा अंधेरा।
तृप्ति मिली प्यासे प्राणों को,
झांका नया सवेरा।
दूर हो रहे, धीरे-धीरे,
चिंता और अभाव।

सौर ऊर्जा से गांवों में,
होने लगा उजाला।
पिंजरे से सब बाहर आए,
खोल दिया हर ताला।
होने लगे ठीक अब मन के,
बहुत पुराने घाव।

यही कामना है, अब इस पर,
कोई आंच न आए।
अपना भारत फिर से,
सोने की चिड़िया कहलाए।
राष्ट्र प्रेम ही सर्वोपरि हो,
सत्य, शिवम् हो भाव।

at.atul@gmail.com

# जीवन अमृत

**गीत**

डा. राज सिंह
नई दिल्ली

तुम मन को पीड़ित मत करना
जीवन को किलित मत करना
आशाओं के दुर्ग मीनारों को
भय से जर्जरित नहीं करना।।

ओसान लगे जीवन तो क्या
विषपान लगे मधुघट तो क्या
तुम सिंह ब्रह्म के वंशज हो
गुणशील धर्म के रक्षक हो।।

खम ठोक खेल दो विपदा को
दुविधा को त्याग कठोर बनो
भक्षण कर लो उस भक्षक को
हो सूक्ष्म नहीं विराट बनो।।

हर युग में ऐसा होता है
सत्य को दबाया जाता है
खूनी खंजर शमशीरों से
स्वाभिमान मिटाया जाता है।।

बदलो तुम जन के पीरो को
बदलो तुम अब तस्वीरों को
अब कालखंड के माथे पर
तुम खींचो नवल लकीरों को।।

जीवन विष है तो अमृत भी
जो परपीड़क वह पीड़ित भी
तुम धीरज धर्म नहीं खोना
राहों से विचलित मत होना।।

जीवन है तो संकट भी
राहें हैं तो कंटक भी
सांसें जो उर्ध्व हुईं तो क्या
दुःख है तो दुःखभंजक भी हैं।।

expresstodrrajvaishnav@gmail.com

**काकोरी दिवस आज**

देश की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत देशभक्तों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने को संगठित हुए युवा वर्ग और काकोरी कांड के बाद गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारियों की शहादत को संक्षेप में बयान करता आलेख...

# अप्रतिम था उनका बलिदान

राजेन्द्र नाथ बक्शी
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 90 वर्षों तक राज किया। इस दौरान जब देश के युवा वर्ग ने अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होकर उनके विरुद्ध आवाज उठाई तो अंग्रेज सतर्क होकर उन पर नजर रखने लगे थे। इसी दौरान 10 क्रांतिकारियों ने, धन की व्यवस्था के लिए 9 अगस्त, 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन रोककर, गार्ड वैन से सरकारी खजाना लूट लिया था। काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी प्रारंभ हुई और 18 क्रांतिकारियों के विरुद्ध काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे के आगे बढ़ जाने के बाद अशफाकउल्ला खां दिल्ली से सन् 1926 में गिरफ्तार कर लिए गए तथा सबसे अंत में शचीन्द्र नाथ बक्शी सन् 1927 में भागलपुर में गिरफ्तार हो गए थे।

काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे का फैसला 6 अप्रैल, 1927 को स्पेशल सेशन जज ए. हैमिल्टन ने दिया था, जिसमें तीन क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी तथा अन्य लोगों को विभिन्न अवधि की सजाएं दी गई थीं। फैसला देने के बाद जज के बारे में किसी को कुछ भी मालूम न हो सका था।

दिनांक 6 अप्रैल, 1927 को स्पेशल सेशन जज ए. हैमिल्टन, फैसला सुनाने के बाद चुपचाप कोर्ट से निकलकर सीधे चारबाग स्टेशन पहुंचे तथा वहां से बंबई (अब मुंबई) जाने वाली ट्रेन में बैठे और सीधे बंबई निकल गए तथा बंबई से लंदन के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि उन्हें भय था कि तीन क्रांतिकारियों को फांसी देने के कारण जेल से बाहर रह रहे क्रांतिकारी कहीं उन्हें गोली का निशाना न बना दें।

काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में जिन लोगों को सजा दी गई थी उन सभी को विभिन्न जिलों की जेलों में रखा गया था। जिन तीन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी उन्हें अलग-अलग जेलों में रखा गया था। रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को 19 दिसंबर, 1927 को फांसी दे दी गई, जबकि राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी को निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व 17 दिसंबर, 1927 को ही फांसी दे दी गई। इसका कारण यह रहा कि अंग्रेजों को गुप्त रूप से सूचना मिली कि राजेन्द्र लाहिड़ी बाहर रह रहे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जेल से भागने का षड्यंत्र रच रहे हैं।

काकोरी षड्यंत्र के पूरक केस में अशफाकउल्ला खां को फांसी व शचीन्द्र नाथ बक्शी को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अशफाकउल्ला खां को फैजाबाद जेल में रखा गया था तथा 19 दिसंबर, 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था।

फांसी से पहले तीनों क्रांतिकारियों ने जेल में रहते हुए तथा फांसी देने के पूर्व अपने मन की भावनाओं को विभिन्न रूपों से प्रगट किया था।

अशफाकउल्ला खां ने फांसी के तीन दिन पहले 16 दिसंबर को पोस्ट कार्ड पर एक पत्र शचीन्द्र नाथ बक्शी की दीदी को लिखा था, जो उस समय बनारस में थीं। दरअसल अशफाकउल्ला खां का बनारस में बक्शी के घर आना-जाना था तथा बक्शी की दीदी से भी उनकी जान-पहचान हो गई थी। पत्र में वह लिखते हैं, 'आई एम नाट गोइंग टू डाई बट गोइंग टू लिव फार एवर'। आज भी लोग अशफाक को याद करते हैं। सोचिए जरा, अशफाक फांसी पर चढ़ने जा रहे थे और उनके मन में था कि मैं मरने नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जीने जा रहा हूं।

रामप्रसाद बिस्मिल ने फांसी से दो-तीन दिन पूर्व अपने से संबंधित जानकारियां लिखकर गुप्त रूप से जेल से बाहर श्री बनारसीदास चतुर्वेदी को भिजवाई थीं, जो बाद में अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा नाम से पुस्तक में प्रकाशित हुईं। इसी तरह रोशन सिंह ने अपने भाई को लिखे एक पत्र में बहुत ही भावुक बातें लिखीं। रोशन सिंह को अपनी फांसी का कोई दुख न था, बल्कि अपने गांव का नाम रोशन करने का उन्हें गर्व था।

किस प्रकार तथा किन विषम परिस्थितियों में इन लोगों ने देशहित में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, इसके दो ज्वलंत उदाहरण संक्षेप में निम्नवत हैं:

-अलीपुर षड्यंत्र केस में उल्लासकर दत्त व बारीन्द्र कुमार घोष को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी तथा गणेश दामोदर सावरकर को भी एक अन्य केस में आजीवन कारावास की सजा मिली थी, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए मदनलाल धींगरा ने लंदन के इम्पीरियल इंस्टीट्यूट में सर विलियम कर्जन वायली को 1 जुलाई, 1909 को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गढ़ में किसी उच्च अधिकारी की हत्या करनेवाले वह प्रथम भारतीय थे। उन पर मुकदमा चला और जज ने 23 जुलाई, 1909 को उन्हें मृत्युदंड दिया।

-जतीन्द्र नाथ दास क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहने के कारण जून, 1929 में गिरफ्तार कर लाहौर जेल ले जाए गए। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त पहले से ही जेल में थे और राजनैतिक बंदियों से सम्मानजनक व्यवहार के लिए, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी।

उन्हीं दिनों देश में विशाल जन आंदोलन होने लगा। अंग्रेज सरकार ने आंदोलन के उग्र रूप धारण करने के पहले ही, झुकने का फैसला लिया और राज बंदियों के साथ अच्छे व्यवहार का आश्वासन दिया। मांग पूरी होने पर, जतीन्द्र के साथ के अन्य आंदोलनकारियों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, किंतु जतीन्द्र का अनशन जारी रहा। दिन-ब-दिन जतीन्द्र की हालत नाजुक होती गई। अनशन के 63वें दिन, 13 सितंबर, 1929 को, उनकी सांस काफी तेजी से चल रही थी। तभी उन्हें एक हिचकी आई और प्राण साथ ले गई। युवावस्था में जीवन से हारकर भी अंग्रेजों से जंग जीत चुके थे जतीन्द्र नाथ दास।

ऐसे ही अनगिनत देशभक्तों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे और तब अंग्रेज भारत से पलायन को तैयार हुए और देश 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ।

meetabakshi@gmail.com

# चंद्रशेखर हो गए पहले यहां आजाद

किशोरावस्था में भारतीय क्रांतिकारी दल के सदस्य बनने वाले चंद्रशेखर के 'आजाद' बनने के पीछे की गाथा और देश की स्वतंत्रता के लिए उनके राष्ट्रप्रेम को दर्शाता आलेख...

सुधीर विद्यार्थी
बरेली, उत्तर प्रदेश

असहयोग आंदोलन के उथल-पुथल भरे दिनों में बनारस की सड़कों से पकड़कर खरेघाट मजिस्ट्रेट के सामने एक किशोर को पेश किया गया। अदालत में पूछा गया, 'क्या नाम है तुम्हारा?'

वह बोला, 'आजाद।'

-'पिता का नाम?'

-'स्वतंत्र।'

-'घर कहां है?'

-'जेलखाना।'

मजिस्ट्रेट सुनकर हैरान रह गया। उसे 15 बेंतों की सजा दी गई। बेंत के हर प्रहार पर वह बालक 'भारत माता की जय' का उद्घोष करता। छूटने के बाद शहर के ज्ञानवापी में उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ और उसी समय से चंद्रशेखर नाम का यह 14 वर्षीय बालक 'आजाद' बन गया।

23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा में जन्मे आजाद जल्दी ही भारतीय क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में लखनऊ के निकट काकोरी में रेल रोककर सरकारी खजाना लूटने के अभियान में 10 क्रांतिकारियों के हिस्सेदारी करने के बाद भी आजाद सरकार की गिरफ्त में नहीं आए। उस कठिन समय में वह छिपकर दल का नया ताना-बाना बुनते रहे।

1928 में क्रांतिकारियों ने 'हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ' का गठन किया आजाद इसमें सेनापति बने। इसी वर्ष साइमन कमीशन भारत आया जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपतराय की पुलिस के प्रहार से घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। देश के इस अपमान का बदला लिया आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर, लाहौर में अंग्रेज अफसर सांडर्स का वध करके। दल की ओर से यह विवशतापूर्ण कार्यवाही थी। इस घटना के बाद ही भगत सिंह क्रांतिकारिणी दुर्गा भाभी के साथ छद्म वेश में लाहौर से कलकत्ता (अब, कोलकाता) निकल गए।

27 फरवरी 1931 की सुबह। इलाहाबाद (अब, प्रयागराज) के कटरा मुहल्ले का एक सुनसान मकान। सवेरे उठकर वह अपने साथी भवानी सिंह से बोले, 'किसी से मिलना है। लौटकर खाना-पीना करूंगा।' उन्होंने अपनी रिवाल्वर कुर्ते की भीतरी जेब में डाली और लंबे कदमों से बाहर निकल गए।

शहर के सन्नाटे में डूबा अल्फ्रेड पार्क। घनी झाड़ियों से घिरा इलाका। आजाद यहां एक बेंच पर बैठे अपने साथी सुखदेव राज से मशविरा कर ही रहे थे कि एक गोली के उनके कान के पास से निकल गई। उन्होंने फौरन रिवाल्वर निकाली। इन क्षणों में भी वह अपने साथी से बोले, तुम निकल जाओ। तभी एक और गोली उनकी जांघ में आ लगी। उन्होंने घिसटकर मौलश्री के वृक्ष का सहारा ले लिया और अपनी रिवाल्वर से गोलियों की बौछार करने लगे। अपने अचूक निशाने से उन्होंने सामने छिपकर खड़े ब्रिटिश पुलिस अफसर के छक्के छुड़ा दिए और दारोगा विश्वेश्वर सिंह का जबड़ा घायल कर दिया। कहा जाता है कि आजाद के पास जब एक गोली शेष बची तब उन्होंने उसे अपनी कनपटी पर दागकर सदा के लिए मृत्यु का वरण कर लिया। जीते जी पुलिस उनके शरीर को हाथ नहीं लगा पाई। वह अक्सर कहा भी करते थे, 'जब तक यह बमतुलबुखारा (आजाद प्यार से अपनी रिवाल्वर को यही कहा करते थे) उनके पास है, किसमें हिम्मत है जो जीते जी उनके शरीर को हाथ लगा ले।'

उनकी शहादत पर जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, 'इस लड़के की शहादत ने आज इलाहाबाद वालों का सिर ऊंचा कर दिया।'

सायंकाल काले कपड़ों में आजाद की भस्मी का इलाहाबाद के चौक पर जुलूस निकाला गया और एक सार्वजनिक सभा हुई। देखते-देखते शहर भर में हड़ताल हो गई। सब ओर पुलिस के पहरे के बीच 'अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहें' के नारों से आकाश गुंजायमान हो रहा था।

आजाद बहुत भावुक भी थे। अपने साथी भगवती चरण की लाहौर में रावी तट पर बम परीक्षण में हुई शहादत ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए आजाद जब दल-बल सहित रवाना होने लगे तब दुर्गा भाभी ने ही अंगूठा चीरकर रक्त से उनके माथे पर तिलक किया था। आजाद अपने साथी मास्टर रुद्रनारायण की पत्नी के 'चहेते देवर', भगवानदास माहौर की मां के 'प्यारे बचुआ' और कानपुर की श्रीदेवी मुसद्दी तथा तारारानी अग्रवाल के 'स्नेहभाजन' थे। फरारी दिनों में ये सब घर उनकी अभेद्य शरणस्थली बनते रहे।

प्रख्यात कवि शिव सिंह 'सरोज' ने आजाद के इसी नायकत्व और जीवन को सामने रखकर एक कविता में कहा था, 'लोग कहते हैं कि आजादी मिली थी बाद, चंद्रशेखर हो गया पहले यहां आजाद।

vidyarthisandarsh@gmail.com

**स्मृति शेष**

क्षमा शर्मा
नई दिल्ली

# विस्मित करती उनकी आभा

डोगरी और हिंदी भाषा की प्रख्यात साहित्यकार पद्मा सचदेव बीते दिनों साहित्य जगत को अलविदा कह गईं। वह जितनी सिद्धहस्त कथाकार थीं उतनी ही उम्दा कविता भी लिखती थीं। श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत है यह आत्मीय संस्मरण...

सवेरे फेसबुक से ही पता चला कि पद्मा जी नहीं रहीं। उनसे पहली मुलाकात सन् 1980 के दौरान हुई थी। जब मेरे संपादक श्री जयप्रकाश भारती ने कहानी लिखवाने के आग्रह के साथ उनसे मिलने भेजा। उन दिनों वह नई दिल्ली के बंगाली मार्केट में रहती थीं और आश्चर्य, पद्मा जी मेरे आतिथ्य में इस तरह लग गईं, हर तरह के व्यंजन परोसने लगीं। न करने पर बोलीं, 'चुपके से खा ले वर्ना उसी से शिकायत कर दूंगी, जिसने भेजा है।' अगले दिन भारती जी ने हंसते हुए कहा, 'तुम्हें पता है, पद्मा जी ने क्या कहा। बोलीं कि आपने इतनी सुंदर लड़की को मेरे पास भेजा था। अगर बेटा होता तो बहू बना लेती।' भारती जी की बात सुनकर कुछ कहते नहीं बना। वह मेरे पिता तुल्य थे।

आफिस में फाटक पर बैठे चौकीदार, रिसेप्शन पर बैठे रिसेप्शनिस्ट सबको पता है, मेरी यानी कि मैडम की सास आई हैं। रिसेप्शन से फोन आता है, 'मैडम आपकी मदर इन ला आई हैं।' मैं सारा काम छोड़कर रिसेप्शन की तरफ दौड़ती थी। इतने सालों में दफ्तर में वह कभी मेरे केबिन में नहीं आईं। रिसेप्शन रूम में ही बैठकर बातें करतीं। फिर बतातीं कि आज कहां जाना है। कहतीं कि इधर से गुजर रही थी तो लगा कि अपनी बहू से मिलती चलूं। न जाने कब उन्होंने मुझे अपनी बहू मान लिया। वह कहतीं, 'मुझे तुम और अनामिका (प्रसिद्ध लेखिका) अपनी बहू जैसे दिखती हो।' वह न कभी कुछ खातीं, न चाय पीतीं। मैं नीचे उन्हें गाड़ी तक छोड़ने जाती। फिर उनका मनपसंद पान लाकर देती। वह पान खातीं और चली जातीं। ऐसा महीने में एक-दो बार जरूर होता। एक बार दफ्तर की एक महिला ने कहा, 'मैडम, आपकी सासू मां तो बहुत यंग हैं। कितनी खूबसूरत भी हैं।' इतना सुनना था कि पद्मा जी बनावटी गुस्से से बोलीं, 'अरी, क्या कहती है। मेरी बहू जैसी दूसरी कोई नहीं। मन तो यह करता है कि इसे काजल का टीका लगाती रहूं, मगर दफ्तर है। इसलिए चुप रह जाती हूं।' इस तरह के हंसी-मजाक वह अक्सर करती थीं।

(जन्मतिथिः 17 अप्रैल, 1940 - पुण्यतिथिः 4 अगस्त, 2021)

मेरे बेटे की शादी में जब उन्हें पता चला कि आज मेहंदी लग रही है तो वह अपने आप आईं। उन्होंने न केवल अपनी सुरीली आवाज में गाया, बल्कि ढोलक भी खूब बजाई। शादी और रिसेप्शन में भी आईं और पूरे समय रहीं। सारे रिश्तेदार-नातेदार उनके मधुर व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए कि इतनी बड़ी लेखिका और जरा सा अभिमान नहीं। मेरे लिए वह कभी कोई सूट, साड़ी या मिठाई लाती रहतीं। मैं मना करती तो कभी मनुहार करतीं, 'अरे, मैं तेरी सास हूं। मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा या कभी डांटतीं-बड़ों से ज्यादा जिद नहीं करते।' सास की बात मानना बहू का फर्ज होता है। फिर खूब हंसतीं। आज भी उनका दिया लाल रंग का कश्मीरी कढ़ाई का सूट मेरे पास है।

उनका दमकता रंग, काजल लगी बड़ी आंखें, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हमेशा ढका सिर और मोती से दांत सुंदरता में सैकड़ों चंद्रमा को फीका कर देते। उनकी आभा से मैं अक्सर विस्मित होती।

डोगरी भाषा में कविता के लिए उनकी पुस्तक- 'मेरी कविता मेरे गीत' पर सन् 1971 में बहुत कम उम्र में ही उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। उनकी आत्मकथा- 'बूंद बावड़ी' बहुत चर्चित हुई। उसका एक प्रसंग कभी नहीं भूला। युवा पद्मा जी गंभीर रूप से बीमार थीं। श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती थीं। एक दिन जब डा. साहब उन्हें देखने आए तो देखा कि पद्मा जी रो रही हैं। डा. साहब के बहुत बार पूछने पर उन्होंने कहा कि आज रक्षाबंधन है। वह अस्पताल में हैं। किसे राखी बांधें। डा. साहब ने यह सुना तो फौरन अपनी कलाई आगे कर दी। इस घटना के बाद पद्मा जी ने जीवनभर उन्हें राखी बांधी। खास बात यह कि पद्मा जी हिंदू थीं और डा. साहब मुसलमान, लेकिन इंसानी रिश्ते धर्म और जाति से अलग होते हैं, उन्हें होना भी चाहिए। इस प्रसंग को जिस तरह से पद्मा जी ने लिखा है, वह द्रवित कर देता है। उनके लिखे ने हमें कश्मीर को समझने की एक नई नजर भी दी। सन् 1970-1980 के दौरान उन्होंने मशहूर गायिका लता मंगेशकर पर एक प्रसिद्ध पत्रिका में अद्भुत संस्मरण लिखे थे। बाद में एक पुस्तक भी लिखी-'ऐसा कहां से लाऊं'। यह पुस्तक भी बहुत लोकप्रिय हुई।

पद्मा जी के बारे में बहुत से लोगों ने फेसबुक पर लिखा है। सबके लिखे में एक ही बात सामने आई, उनके व्यवहार की मिठास, सहजता, पल के पल में किसी को अपना बनाने की ताकत और किसी संबंध को ताउम्र सहेजने की शालीनता।

kshamasharma1@gmail.com

## क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया

1925 में आज ही लखनऊ के पास काकोरी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन से जुड़े 10 से ज्यादा क्रांतिकारियों ने ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा था। इसमें शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी।

## इटली में पीसा की मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया गया

1173 में आज ही इटली के पीसा नामक शहर में मीनार का निर्माण शुरू हुआ था। 56 मीटर ऊंची पीसा की मीनार निर्माण के समय ही एक तरफ झुक गई थी। इसे पूरा करने में 200 साल लगे। सुरक्षा के चलते 11 साल बंद रहने के बाद 2001 में फिर से खुली।

## साहित्य, पत्रकारिता में शिवपूजन सहाय का अहम योगदान

साहित्य और पत्रकारिता के शिव कहे जाने वाले आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म आज ही 1893 में बिहार के बक्सर में हुआ था। 1921 तक हिंदी के शिक्षक रहे। इसके बाद मासिक पत्र मारवाड़ी सुधार से पत्रकारिता की शुरुआत की। 1923 में कोलकाता में मतवाला पत्रिका के संपादक बने। 1924 में लखनऊ में माधुरी पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने बिहारी अस्मिता पर आधारित देहाती दुनिया की रचना की थी। आजादी के बाद 1949 में बिहारी राष्ट्रभाषा परिषद के सचिव रहे। 1960 में उन्हें पद्म भूषण मिला। 1963 में पटना में निधन हो गया।

# 'थ्री इडियट्स' ने झकझोरा, बनाई तनाव मापने की मशीन

धीरज अग्निहोत्री, फर्रुखाबाद

- बीटेक छात्र ने तैयार की स्ट्रेस लेवल इंडीकेटर मशीन
- अटल टिकरिंग लैब में परीक्षण, आइआइटी में जांच

ये इंजीनियर लोग बड़े चालाक होते हैं... ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनाई जिससे पता चल सके कि दिमाग पर कितना प्रेशर है। फिल्म थ्री इडियट्स में इंजीनियरिंग छात्र की खुदकुशी के बाद फुंगसुक वांगडू (आमिर खान) का यह डायलाग तो याद ही होगा। फिल्म के इस एक सीन ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छात्र असित तिवारी को इस कदर झकझोरा कि उन्होंने दिमाग का तनाव मापने के लिए स्ट्रेस लेवल इंडीकेटर मशीन बना डाली। इस पर अंगुली रखने के कुछ पलों में आपके मानसिक तनाव का पता चल जाएगा। अब तक 50 लोगों पर इसके परीक्षण के साथ अटल टिकरिंग लैब में भी इसे परखा जा चुका है।

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के छात्र असित बताते हैं कि फिल्म थ्री इडियट्स के इस डायलाग ने सोचने को मजबूर किया तो स्ट्रेस लेवल इंडीकेटर मशीन बनाने में जुट गए। इसमें उन्होंने अटल टिकरिंग लैब कानपुर के संस्थापक व जय नारायण विद्या मंदिर इंटर कालेज के भौतिकी के शिक्षक कौस्तुभ तोमर की मदद ली। इसे तैयार करने में एक हजार रुपये की लागत आई।

**इंडीकेटर का रंग बताता स्थिति :** स्ट्रेस लेवल इंडीकेटर में रेड, ग्रीन व कलरफुल एलईडी लगी हैं। इंडीकेटर के सेंसर पर अंगुली रखी जाती है। इंडीकेटर में लाल बत्ती खतरे का इशारा करती है। बीप के साथ रेड एलईडी जलती है तो यह हाई डिप्रेशन में जाने का संकेत है। ग्रीन लाइट मानसिक तनाव कम होने की जानकारी देती है। वहीं, कलरफुल लाइट स्थिति सामान्य होने की जानकारी देती है। इसके ऊपर इमोजी भी लगाए गए हैं।

**ऐसे पता चलता तनाव का स्तर :** स्ट्रेस लेवल इंडीकेटर को त्वचा (स्किन) के संपर्क में लाकर त्वचा पर दबाव डाला जाता है। इसके बाद डिवाइस के सेंसर पर अंगूठा रखते ही तनाव की गणना होती है। तनाव जितना अधिक होगा, रजिस्टेंस (शरीर में करंट के विरोध करने की क्षमता) उतना कम हो जाएगा। तनाव व रजिस्टेंस को एक-दूसरे का पूरक बनाया गया है। यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। यदि रजिस्टेंस कम है तो तनाव अधिक है।

**परीक्षण के लिए भेजा आइआइटी :** शिक्षक कौस्तुभ ओमर ने बताया कि असित के प्रोजेक्ट को अटल टिकरिंग लैब में परखा गया है। इसमें अभी कुछ संशोधन की जरूरत है लेकिन इसे परीक्षण के लिए वीडियो के साथ ई-मेल से आइआइटी को भेजा है। वहां से प्रमाणित होने के बाद इसे आमजन के लिए बाजार में लाना आसान होगा।

स्ट्रेस लेवल मशीन दिखाते असित तिवारी। जागरण

अभी तो हम लोग चेहरे, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर से ही तनाव का आकलन करते थे, लेकिन ये मशीन तो अंगूठा रखने मात्र से मानसिक स्थिति बता रही है। इस संबंध में छात्र से बात करेंगे, ताकि चिकित्सा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सके।
–डॉ. आरती लालचंदानी, पूर्व प्राचार्य जीएसवीएम मेडिकल कालेज, कानपुर

मानसिक तनाव का सीधा संबंध न्यूरो से होता है। त्वचा के संपर्क में आने के बाद यह उपकरण मानसिक तनाव बता रहा है। ऐसे में ये बेहतर काम करेगा। इसके जरिये लोगों को अवसाद में जाने से पहले ही रोका जा सकेगा।
– डा. राजकुमार, पूर्व कुलपति उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा

## जलपरियों का डांस

जलपरियां (मर्मेड) आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य हैं। यह बहस चलती रहती है कि क्या हकीकत में जलपरियों का कोई अस्तित्व है? लेकिन अमेरिका के वर्जीनिया में दुनिया का सबसे बड़ा मर्मेड सम्मेलन होता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। इसका आयोजन सोसाइटी आफ मर्मेड्स करती है। हालांकि यह काफी महंगा शौक है और लोग लाखों रुपये मर्मेड की पूंछ और ड्रेस पर खर्च करते हैं। यह पूंछ सिलिकान से बनाई जाती है जो किसी मछली की तरह होती है। ड्रेस भी खास फोम से तैयार किए जाते हैं। इससे तैरने में आसानी रहती है। मर्मेड को कहानियों से हकीकत में उतारने वाले इसे एक पेशे के तौर पर अपना रहे हैं। एएफपी

## इधर-उधर की

### सफाईकर्मियों ने करीब 18 लाख रुपये लौटाए

**न्यूयार्क, एजेंसी:** अमेरिका के ओहायो में एक परिवार ने सफाई के दौरान गलती से करीब 18 लाख रुपये से भरा बैग कूड़े में फेंक दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि पूरे पैसे परिवार को वापस मिल गए। कूड़ा ले जाने वाली रिपब्लिक सर्विसेस ने कहा, एक परिवार ने ट्रक में गलती से पैसे फेंकने की बात कही। हमारी टीम ने तुरंत ट्रक ड्राइवर से संपर्क किया और लैंडफिल से पहले ही उसे रोक लिया। सफाईकर्मियों ने कुछ ही समय में उस बैग को ढूंढ निकाला और उस परिवार को पैसे लौटा दिए। हमें खुशी है कि उस परिवार की मदद कर पाए।

सफाई के दौरान गलती से कूड़े में फेंके थे पैसे। इंटरनेट मीडिया

# आलू में है दम, कैसे भी खाएं हम

**अध्ययन** ▶ फाइबर और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों की भी कमी की जा सकती दूर

### ये दोनों पोषक तत्व सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हैं चिंता के कारक

**शिकागो, एएनआइ :** डायबिटीज के रोगियों को आलू खाने से भले ही मना किया जाता हो, लेकिन हाल के एक अध्ययन से इसके पोषक गुणों प्रकाश डालते एक नया अध्ययन हुआ है। नौ साल से 18 साल तक बच्चों-किशोरों पर किए गए शोध के आधार पर बताया गया है कि आलू खाना कुछ अहम पोषण तत्वों की कमी पूरा करने या उसके स्तर में सुधार लाने की एक कारगर रणनीति हो सकती है। यह निष्कर्ष न्यूट्रिएंट्स जर्नल के आगामी अंक में प्रकाशित होने वाला है।

अध्ययन में आलू खाने वाले और आलू नहीं खाने वालों की तुलना करते हुए बताया गया है कि जो लोग आलू का किसी भी रूप में उपभोग करते हैं, उनमें फायबर और पोटैशियम समेत कई अन्य पोषक तत्वों इनटेक ज्यादा होता है। फायबर और पोटैशियम तो ऐसे पोषक तत्व हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता के कारक होते हैं। शोध के मुख्य लेखक विक्टर फुलगोनी के मुताबिक, आलू पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है, लेकिन किशोरों में पोषण की पूर्ति के लिए इसका उपभोग बहुत कम होता है। शोधकर्ताओं ने 2001-2018 के बीच नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे (एनएचएएनईएस) में शामिल नौ साल से 18 साल के 16,633 बच्चों और किशोरों के आहार संबंधी सूचनाएं एकत्रित की। यह सर्वे हेल्दी इटिंग इंडेक्स-2015 (एचईआइ) के लिए किया गया था, जिससे यह पता लगाया जाना था कि 2015 से 2020 के बीच अमेरिकियों ने आहार गाइडलाइन का कितना पालन किया। एचईआइ स्कोर में अंतर से पाया गया कि आलू खाने वाले प्रतिभागियों में न्यूट्रिएंट्स का इनटेक काफी अच्छा था।

फुलगोनी के मुताबिक, हमारा निष्कर्ष बताता है कि अमेरिकियों के लिए तय डायट गाइडलाइन की सिफारिशों को पूरा करने की दिशा में बच्चों और किशोरों के मामले में आलू अहम भूमिका निभा सकता है। इस लिहाज से पोषण लक्ष्य पूरा करने के लिए आलू एक अहम रणनीतिक आहार साबित हो सकता है।

पोषक तत्व का अहम स्रोत है आलू। फाइल फोटो

### अध्ययन का निष्कर्ष

- जिन प्रतिभागियों ने किसी भी रूप में आलू का सेवन किया, उनका एचईआइ स्कोर आलू नहीं खाने वालों से 4.7 फीसद ज्यादा था।
- फ्राइड आलू और फ्राइड आलू व आलू चिप्स खाने वाले बच्चे और किशोरों का एचईआइ स्कोर क्रमश: 2 फीसद तथा 1.6 फीसद ज्यादा था।

# एंटीबाडी से कोरोना की प्रभावी वैक्सीन बनाने की खोजी राह

**अनुसंधान**

बेहतर वैक्सीन की आस। फाइल फोटो

कोरोना वायरस का प्रभावी इलाज खोजने के लिए विज्ञानी दिन-रात काम कर रहे हैं। हाल ही में विज्ञानियों ने मानव शरीर में ही ऐसी एंटीबाडी को पहचाना है, जो कोरोना वायरस के हर वैरिएंट पर कारगर हो सकती है। अब इस एंटीबाडी से वैक्सीन बनाने पर अध्ययन किया जा रहा है, जो कोरोना के इलाज में सौ फीसद कारगर हो सके। ये एंटीबाडी उन लोगों के शरीर में मिली है, जो कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद ठीक हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी आफ वाशिंगटन का यह अध्ययन साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने कोरोना से ठीक हुए लोगों में पांच तरह के मोनोक्लोनल एंटीबाडी की पहचान की है, जो वायरस के कई वैरिएंट के साथ क्रास रिएक्शन कर उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम हैं। इन एंटीबाडी के सभी वैरिएंट को खत्म करने में कारगर होने से विज्ञानी उत्साहित हैं। इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए विज्ञानी एंटीबाडी से वैक्सीन बनाने की संभावना तलाश रहे हैं। अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि इस खोज के आधार पर ऐसी वैक्सीन तैयार हो सकती है, जो कोरोना के इलाज के लिए शत-प्रतिशत कारगर होगी। किसी नए वैरिएंट पर कारगर न होने की आशंका भी नहीं रहेगी। –आइएएनएस

## स्क्रीन शॉट

# ...तो इस घटना से प्रेरित है रानी मुखर्जी की फिल्म

बंटी और बबली 2 में भी नजर आएंगी रानी। इंटरनेट मीडिया

इस साल रानी मुखर्जी के बर्थडे पर उनकी अगली फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नार्वे की घोषणा की गई थी। इस फिल्म को सत्य घटना से प्रेरित बताया गया है। कहा गया था कि एक अनकही कहानी है, जिसमें पूरे देश के खिलाफ मां की लड़ाई की यात्रा है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यह घटना वर्ष 2016 के दौरान की है, जब एक भारतीय मूल की महिला के पांच वर्षीय बेटे को नार्वे के अधिकारी खराब बर्ताव की शिकायत की वजह से अपने साथ ले गए थे। महिला ने मामले में हस्तक्षेप के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई थी। उस समय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हुआ करती थीं। यह फिल्म उसी घटना से प्रेरित है। वैसे 2011 के बाद से यह तीसरा मामला था, जब नार्वे में अधिकारियों द्वारा बच्चों को उनके भारतीय मूल के माता-पिता से दुर्व्यवहार के आधार पर छीन लिया गया था। भारत सरकार द्वारा मामले को उठाए जाने पर बच्चों को उनके अभिभावकों को वापस कर दिया गया था। इस फिल्म का निर्देशन अशिमा चिब्बर करेंगी। वर्तमान में यह फिल्म प्री-प्रोडक्शन चरण में है और जल्द ही फ्लोर पर जाने की उम्मीद है। जी स्टूडियो के साथ-साथ मोनिशा आडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल आडवाणी की एम्मे एंटरटेनमेंट इसकी निर्माण कर रही है। रानी आगामी दिनों में बंटी और बबली 2 में नजर आएंगी।

## यूं तो हर जीव से प्यार, पर अब घोड़ों के साथ काम नहीं करूंगा : रितिक रोशन

**अभिनेता रितिक रोशन** ने जोधा अकबर और मोहेंजो दारो जैसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों में काम किया है। इन फिल्म में उन्हें घुड़सवारी भी करना पड़ा, जो कि उनके लिए काफी मुश्किल है। शनिवार को अभिनेता कुणाल कपूर की आगामी वेब सीरीज द एम्पायर पर बात करने के लिए रितिक उनके साथ इंस्टाग्राम लाइव पर जुड़े। इस दौरान रितिक ने कहा कि यूं तो मैं दुनिया के हर जीव को प्यार करता हूं, लेकिन मुझे घोड़ों के साथ काम करना पसंद नहीं। आगे मैं घोड़ों के साथ काम नहीं करना चाहूंगा। (हंसते हुए) अगर आगे निर्माता-निर्देशक को मेरे सीन में घोड़े चाहिए होंगे, तो उन्हें विजुअल या स्पेशल इफेक्ट्स के जरिये लाना पड़ेगा। इस दौरान प्रशंसकों द्वारा उनकी फिल्म कोई मिल गया के किरदार जादू के बारे में पूछे जाने पर रितिक ने जल्द ही कृष 4 के एलान का संकेत देते हुए कहा कि जादू कहां है, फिलहाल यह सवाल एक रहस्य है, लेकिन जल्द ही वह लोगों के बीच आने वाला है। मुगल शासक बाबर के जीवन सफर को दिखाती वेब सीरीज द एम्पायर, एलेक्स रदरफोर्ड की किताब एम्पायर आफ मुगल्स पर आधारित है। 27 अगस्त को डिज्नी प्लस हाटस्टार पर रिलीज हो रहे इस शो में कुणाल बाबर की भूमिका में हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि शो के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग राजस्थान में करीब सौ घोड़ों और हजारों कर्मियों के साथ की गई है। शो में कुणाल के साथ शबाना आजमी, डिनो मोरियो और राहुल देव भी अहम भूमिकाओं में हैं।

कुणाल कपूर के साथ लाइव आए रितिक। इंस्टाग्राम

## अलग-अलग उम्र वर्ग के किरदार निभा सकता हूं : अभय देओल

**बीते दिनों रिलीज** वेब सीरीज 1962 : द वार आन इन द हिल्स में अभय देओल सैन्य अधिकारी और एक आजाद ख्याल पिता की भूमिका में नजर आए थे। अब वह फिल्म स्पिन में किशोरवय संतान के पिता की भूमिका में नजर आएंगे। अभय का कहना है कि आन स्क्रीन पिता का रोल निभाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दैनिक जागरण के सहयोगी अखबार मिड डे से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मैंने मनोरमा : सिक्स फीट अंडर में भी पिता का किरदार निभाया था। बालीवुड में उम्र को लेकर असुरक्षा के चलते 50 की उम्र पार चुके अभिनेताओं को 20 वर्ष की उम्र के करीब की अभिनेत्रियों के साथ कास्ट करना सामान्य बात है। यह मजेदार है क्योंकि युवा अभिनेत्रियों के साथ उनकी उम्र अधिक दिखती हैं। मेरी अगली वेब सीरीज में मेरी उम्र 30 से 50 की दिखाई जाएगी। मैं अलग-अलग उम्र के किरदार सहजता से निभा सकता हूं।' इंडो-अमेरिकन फिल्म स्पिन का निर्देशन मंजरी माकिजानी कर रही हैं। यह कहानी एक अमेरिकी बच्चे के ईदगिर्द है, जिसका जुनून डीजे बनना है। देओल का मानना है कि यह फिल्म पर्दे पर दक्षिण एशियाई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह एक अमेरिकी बच्चे की कहानी है। यह उन्हें उनकी त्वचा के रंग से नहीं आंकने का सुझाव दे रही है। अभय ने हमेशा लीक से हटकर फिल्में की हैं। अब वह उपहार सिनेमा की त्रासदी पर बनने वाली वेब सीरीज में नजर आएंगे। ओय लकी! लकी ओय! अभिनेता इस बात से खुश हैं कि डिजिटल प्लेटफार्म ने मनोरंजन का एक विकल्प दिया है।

आगामी दिनों में फिल्म स्पिन में दिखेंगे अभय। इंस्टाग्राम

## निर्देशक के नजरिये के मुताबिक ही किरदार की तैयारी करती हूं : रिंकू

फिल्म 200 हल्ला हो में नजर आएंगी रिंकू। इंस्टाग्राम

**वास्तविक घटनाओं पर** बनने वाली फिल्मों की सूची में सार्थक दासगुप्ता द्वारा निर्देशित फिल्म 200 हल्ला बोल भी शामिल है। 20 अगस्त को डिजिटल प्लेटफार्म जी 5 पर रिलीज हो रही यह फिल्म दुष्कर्म और हत्या जैसे कई संगीन मामलों के आरोपित भारत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के जीवन से प्रेरित है। जिसे साल 2004 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 200 महिलाओं ने पीट-पीटकर मार डाला था। इस फिल्म में आशा सूर्वे का किरदार निभा रही अभिनेत्री रिंकू राजगुरु ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया, 'इस फिल्म के लिए मुझे सबसे पहले सार्थक सर का काल आया था। उन्होंने फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि इसमें आशा का किरदार आप निभाए, क्योंकि जब मैं फिल्म लिख रहा था तो मेरे सामने आप ही आ रही थीं। फिर मैंने उनसे स्क्रिप्ट सुनी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इस किरदार के लिए मैंने कुछ ज्यादा दबाव नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है। सार्थक सर से मैंने सिर्फ यह पूछा था कि आप बस आशा के व्यक्तित्व के बारे में समझा दीजिए। मैं कभी किसी किरदार को अपने लिए चुनौतीपूर्ण मानकर नहीं करती हूं। मेहनत तो हर किरदार में करनी पड़ती है, लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले मैं निर्देशक से पूछती हूं कि आपको क्या दिखाना है? फिर निर्देशक के नजरिये के अनुसार ही मैं अपने किरदार की भाषा, चलने का तरीका, बातचीत की शैली और उम्र पर काम करना शुरू करती हूं।' इस फिल्म में रिंकू के अलावा अमोल पालेकर, बरुण सोबती, इंद्रनील सेनगुप्ता और साहिल खट्टर भी अहम भूमिकाओं में हैं।

# बेल बाटम मुझे अक्षय कुमार ने ही आफर की थी : लारा दत्ता

लारा ने अक्षय के साथ अपनी डेब्यू फिल्म भी की थी • जागरण आर्काइव

**सात सवाल**

पिछले साल लाकडाउन खुलने के बाद विदेश में शूट होने वाली बेल बाटम पहली फिल्म थी। इस फिल्म में लारा दत्ता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। ट्रेलर में उन्हें पहचानना आसान नहीं था। फिल्म को मिल रही प्रतिक्रियाओं से लारा काफी उत्साहित हैं। बेल बाटम 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म और अन्य पहलुओं को लेकर लारा ने बातचीत की :

**• ट्रेलर में आपको पहचानना ही मुश्किल था..**

-मैं इसको लेकर बहुत उत्साहित हूं। इंडस्ट्री और फैंस दोनों से बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। बतौर अभिनेत्री यह मेरे लिए बेहतरीन मौका था कि मैं इंदिरा गांधी जैसी आइकानिक हस्ती का किरदार निभाऊं। मेरे लिए यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैंने शुरुआत में ही सोच लिया था कि लुक तो अपनी जगह जरूरी होता ही है, लेकिन इंदिरा जी की बाडी लैंग्वेज इतनी अलग थी कि किरदार में उसे पकड़ना बहुत जरूरी था। मेरे मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ ने जितना हो सकता था, मेरे लुक को इंदिरा जी की तरह रखने की कोशिश की।

**• मेकअप करने और उतारने में आपको कितना वक्त लगता था?**

-इस किरदार में तैयार होने के लिए मुझे कुल तीन घंटे लगते थे। शूटिंग के बाद प्रास्थेटिक्स को निकालने में एक घंटा चला जाता था, लेकिन प्रास्थेटिक को बनाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी। पहले तो पूरा हफ्ता मेरे चेहरे का एक मोल्ड (सांचा) तैयार करना पड़ा। फिर प्रास्थेटिक बनाया गया। उसके बाद किरदार में एजिंग (उम्र के हिसाब से झुर्रियां) डाली गई। इस लुक को तैयार करने में लगभग एक महीना लगा।

**• इंदिरा गांधी की किस खूबी की प्रशंसक रही हैं?**

-इंदिरा जी की खासियत थी कि वह किसी भी परिस्थिति में हिलती या घबराती नहीं थी। वह स्थाई रहती थी। उनका अपने विचारों पर एक यकीन था। इस फिल्म में भी प्लेन हाइजैक का एक बहुत ही ड्रैमेटिक इवेंट दिखाया गया है, उसमें भी वह हमेशा नियंत्रण में रही थी। मैंने अपनी तैयारी के लिए उनके जो इंटरव्यूज देखे थे उनमें भी वह कभी ज्यादा ड्रैमेटिक नहीं दिखी थी। अगर कोई उनको उकसाने की कोशिश भी करता, तो भी वह बहुत शांत रहती थी।

**• अक्षय के साथ कैसी केमिस्ट्री है? उनके साथ डेब्यू फिल्म के साथ और भी फिल्में की हैं?**

-यह अक्षय के साथ मेरी 13वीं फिल्म है। उनके साथ काम करते-करते 18 साल हो गए हैं। मैंने उनके सारे प्रैंक (मजाक) देखे हैं। मैं यह जरूर कह सकती हूं कि उनके साथ फिल्म करते हुए कभी यह नहीं लगता कि आप काम कर रहे हो। इस फिल्म में भी उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है कि तुम यह कर सकती हो। यहां तक यह फिल्म मुझे अक्षय ने ही आफर की थी। जब उन्होंने कहा कि लारा हम आपको इंदिरा गांधी के किरदार के लिए कास्ट कर रहे हैं तो मैं चौंक गई थी कि मुझमें आपको इंदिरा गांधी कहां दिख रही हैं? लेकिन उन्हें मुझ पर यकीन था।

**• महेश भूपति और लिएंडर पेस की जोड़ी पर वेब सीरीज बनाने की तैयारी है...**

-स्पोर्ट्स पर जरूर फिल्में बनानी चाहिए और पहले भी हमारे कई खिलाड़ियों पर फिल्में बन चुकी हैं। जितना हम अपने स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करेंगे, खिलाड़ियों के लिए उतना ही अच्छा होगा। खिलाड़ी (महेश भूपति) की पत्नी होने के कारण मुझे पता है कि उन्हें बहुत ही कम सपोर्ट मिलता है। मैं एक स्पोर्ट्स पर आधारित फिल्म प्रोड्यूस भी करने जा रही हूं। मैं और महेश अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर इंट्रोवर्ट हैं। इसलिए लोग हमारे बारे में ज्यादा चीजें नहीं देखते हैं।

**• अभिनेत्री के साथ-साथ आप प्रोड्यूसर और व्यवसायी भी हैं, क्या अपने सफर पर कोई किताब भी लिखने की योजना है?**

-नहीं, फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है कि अपनी कोई स्टोरी लिखूं। काफी जिम्मेदारी हैं। मैं प्रोड्यूसर, मां और व्यवसायी भी हूं। तो मैंने पहले से ही अपने आप को काफी व्यस्त कर लिया है, लेकिन मैं कभी किसी चीज को ना नहीं बोलती कि यह नहीं होगा। अगर भगवान चाहेंगे तो जब कभी मौका मिलेगा तो वह भी लिख लूंगी।

**• फैशन सेंस को लेकर आप पहली बार कब अलर्ट हुई थीं?**

-मेरा फैशन सेंस मेरे कंफर्ट लेवल और आस-पास के माहौल पर आधारित होता है। पहले मैं माडल, फिर मिस यूनिवर्स थी, हाई हील्स पहनती थी। अब हील्स पहनना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे लिए मेरी साइज कभी समस्या नहीं थी कि मैं साइज जीरो हूं, दो या चार हूं। मेरे लिए यह जरूरी था कि मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट रहूं और जो कपड़े मुझे फिट होते हैं उन्हें पहनूं। ट्रेंड के साथ चलना या स्टाइलिश के हाथ को पकड़कर चलना मेरे बस की बात नहीं है।

(स्मिता श्रीवास्तव)

## अभी सिर्फ म्यूजिक वीडियो का निर्देशन कर रही हैं फराह खान

मैं हूं ना, ओम शांति ओम और तीस मार खां जैसी फिल्मों की निर्देशिका फराह खान इन दिनों म्यूजिक वीडियोज और टीवी विज्ञापनों की शूटिंग में व्यस्त हैं। उनके निर्देशन में बना म्यूजिक वीडियो साथ क्या निभाओगे.. आज (सोमवार) रिलीज होगा। अल्ताफ राजा के लोकप्रिय गाने तुम तो ठहरे परदेसी से रीक्रिएट किए गए इस म्यूजिक वीडियो को सोनू सूद और निधि अग्रवाल पर फिल्माया गया है। खास बात यह है कि फराह इसके बाद दो और नए म्यूजिक वीडियो निर्देशित करने वाली हैं। इस बारे में फराह ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा, 'अभी मैं फिल्में नहीं, सिर्फ म्यूजिक वीडियो कर रही हूं। साथ क्या निभाओगे के अलावा दो और म्यूजिक वीडियो कर रही हूं। जल्द ही निर्माताओं की तरफ से इनके बारे में आधिकारिक ऐलान किया जाएगा।' वहीं फिल्मों के निर्देशन पर फराह का कहना है, 'पिछले साल मेरी एक फिल्म शुरू होने वाली थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने में लेट हो गई और उसके बाद महामारी आ गई। मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि हमारी फिल्म शुरू नहीं हुई, नहीं तो बीच में ही अटक जाती। अभी बातें चल रही हैं, जब वक्त आएगा तो उसकी भी शूटिंग शुरू कर देंगे। फिल्म के बारे में ज्यादा तो नहीं बस इतना बता सकती हूं, यह भी मेरी पिछली फिल्मों की तरह कामर्शियल मसाला फिल्म होगी।' फराह के निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर साल 2015 में रिलीज हुई थी।

आज रिलीज हो रहा है फराह के निर्देशन में बना म्यूजिक वीडियो साथ क्या निभाओगे • टीम फराह